राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 3 **सोलहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का छब्बीसवां दिवस** संख्या: 10

मंगलवार,

25 फरवरी 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: राम-राम। जय श्रीराम। ...(व्यवधान)... अब इधर तो कैसे करूं? ...(व्यवधान)...

प्रश्न काल।

प्रश्न संख्या 162

(माननीय सदस्य के निलम्बन के कारण असूचीबद्ध)

प्रश्न संख्या 163

डॉ. दयाराम परमार। डॉ. दयाराम परमार।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

डॉ. जसवन्त सिंह यादव।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में सृजित पद

164. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत किस-किस संवर्ग के कितने पद सृजित हैं? उक्त पदों में से किस-किस संवर्ग के कितने कर्मचारी स्थायी व कितने संविदा पर कार्यरत है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) वर्तमान में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों का श्रेणीवार मानदेय कितना है? क्या सरकार उक्त का मानदेय बढाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर

+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए सरकार की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) एनएचएम के अन्तर्गत Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 कुल 39579 पद स्वीकृत है तथा Non-CSR के भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पीआईपी में 3900 पद स्वीकृत है, संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के अधीन कार्यरत कार्मिकों को नियमित किये जाने का प्रावधान उक्त संविदा नियमों के नियम संख्या 20 (स्क्रीनिंग) में किया गया है, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में एनएचएम के अन्तर्गत कार्यरत स्थायी तथा संविदा कर्मचारियों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अन्तर्गत पात्रता रखने वाले कार्यरत कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर विभिन्न संवर्ग के कुल 4518 नियमित पद सृजित किये गये है। विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के उपनियम 20 स्क्रीनिंग में पात्र कार्यरत कार्मिकों के नियमितीकरण का प्रावधान निहित है। विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है। नियमितीकरण के संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी एसओपी दिनांक 25.10.2024 (परिशिष्ट 'य') में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त नियमित पदों के सेवा नियम हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सेवा नियम (राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963 एवं राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965) को राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी की अधिशाषी समिति द्वारा अंगीकार (एडॉप्ट) किया जा चुका है।

(3) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा एनएचएम के अन्तर्गत Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के तहत समस्त संविदा पदों का मानदेय निर्धारित किया गया है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के उपनियम 13(1) मानदेय एवं अन्य सुविधाएं में प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि का प्रावधान है जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(4) एनएचएम के अन्तर्गत संविदा कार्मिकों के रिलोकेशन किये जाने हेतु विभाग द्वारा रिलोकेशन पॉलिसी क्रमांक 250 दिनांक 19.02.2024 जारी की गयी है। विवरण परिशिष्ट 'र' पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्षजी, जिन संविदा कर्मियों को जैसे

फिजियोथेरेपिस्ट है, असिस्टेंट है, रिहेबिलिटेशन वर्कर है, के पदों पर नियुक्ति दी गयी है, इनकी योग्यता व कार्य समान है फिर भी रिहेबिलिटेशन वर्कर का वेतन और फिजियोथेरेपिस्ट का वेतन सबसे कम क्यों हैं? क्या इनको समान वेतन देने के लिए सरकार की कोई योजना है? जिन संविदा कर्मियों की नियुक्ति को 15 वर्ष हो गये और उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है तो उनकी एज के बारे में सरकार ने कोई सोच रखा है कि उनको एज में कोई रिलेक्सेशन दिया जाएगा जब आप भर्ती करेंगे तब? या उनके लिए कोई मानदण्ड बनाया हुआ है, नम्बर एक, दूसरा बाद में पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले 15 साल का नियम होता था कि रेगुलराइज करने के लिए अब डेढ़ साल पहले नया नियम बनाया गया है कि 9 साल के बाद में उनको रेगुलर किया जा सकता है। अभी जो एनएचएम के अन्दर गैप फिलिंग है, स्टेट अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि हमें टेम्परेरी बेसिस पर कितने लोग चाहिए और एनएचएम, नेशनल हैल्थ मिशन, 60:40 के रेश्यो पर हमें 60 परसेंट वो उनकी सेलरी देता है और 40 परसेंट हम देते हैं। अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो है टोटल वो 39,580 पद हैं। इसके अन्दर अभी और भी रिक्रूटमेंट ऑन है, इसके अन्दर जीएनएम 2338, एएनएम 3058 और सीएचओ 5261, ये शीघ्र ही आपके आ जायेंगे, भर्ती हो जायेगी इनकी।

इनके अलावा जैसे मैंने बोला था कि 15 साल से लगे हुए हैं और अभी 9 साल है, 9 साल वाले भी आ जाते हैं रेगुलर के अन्दर, तो उसमें हमने क्या किया कि पोइंट सिस्टम कर दिया है। हर 3 साल को 1 पोइंट दिया है। जो 15 साल वाला है उसको 5 पोइंट मिलेंगे, 9 साल वाले को 3 पोइंट मिलेंगे, तो इस अनुसार हमने भर्ती की है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इन्होंने 9 साल का कर रखा था, सबको तो अभी तक ये रेगुलराइज कर नहीं पाये। जिनको 15 साल हो गये करते हुए उनकी तो एज ओवर एज हो जायेगी, उनके बारे में प्रावधान है, उनकी तो कोई गलती है नहीं, रेगुलराइज तो सरकार को ही करने हैं। ऐसा कोई प्रावधान है कि उनके 15 साल हो गये तो उनको एज में कोई रिलेक्सेशन देंगे या नहीं देंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एज सभी डिपार्टमेंट में बिलकुल ही यूनिफोर्म है। एज लिमिट है सब डिपार्टमेंट सरकार के होते है उनमें उस नियम के अनुसार हम चलेंगे।

प्रश्न संख्या 165

श्री अध्यक्ष: श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा। श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 166

श्री विनोद कुमार। श्री विनोद कुमार।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री भागचन्द टांकड़ा।

प्रदेश में गौशालाओं के विकास हेतु संचालित योजनाएं

167. श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गोशालाओं के विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में गो-सेस में कितने प्रतिशत राशि किस मद से ली जा रही है तथा उसको व्यय कैसे किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे पास उत्तर आ गया है। मेरा पूरक प्रश्न है। क्या सरकार पंचायत समिति एवं नगरपालिका स्तर पर गो शाला खोले जाने पर विचार रखती है क्या? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इनको बोलने दो। ...(व्यवधान)... हो गया न एक बार। एक बार हो गया। ...(व्यवधान)... आप पहले बात कर लेते। ...(व्यवधान)...

माननीय मंत्रीजी।

गोपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) प्रदेश में गोशालाओं के विकास हेतु गोशाला विकास जन सहभागिता योजना संचालित है। योजनान्तर्गत गोशालाओं में गो-आवास, शेड, पानी का टांका, चारा भण्डार आदि के निर्माण हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये (90:10) की सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

गो-काष्ठ मशीन योजनान्तर्गत प्रदेश की 100 गोशालाओं को रियायती दरों पर गो-काष्ठ मशीन उपलब्ध करवाना जिसके तहत 600 या 600 से अधिक गोवंश संधारित गोशालाओं में से योजना के दिशा-निर्देशानुसार 100 गोशालाओं का चयन किया जाकर कुल राशि रुपये 70350/- प्रति गो-काष्ठ मशीन जिसमें 20 प्रतिशत राशि (14070/-) का गोशाला द्वारा तथा 80 प्रतिशत राशि (56280/-) का सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

(2) गोसरंक्षण एवं संवर्धन निधि में स्टाम्प ड्यूटी पर मद 0030-02-800-03 में 10 प्रतिशत तथा मदिरा की बिक्री के वैट पर मद 0040-00-800-06 में 20 प्रतिशत अधिभार (सेस) लगाया जाता है तथा गो संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 संशोधित 2021 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार गो-सेस का व्यय गोसंरक्षण एवं संवर्धन हेतु किया जाता है।

MLS/RTM/25.02.2025/11:10/1b

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न मदों से प्राप्त गो सैस का विगत तीन वर्षों में दौसा जिले में गो संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कब-कब और कितना-

कितना व्यय किया गया? क्या सरकार पंचायत समिति एवं नगरपालिका के स्तर पर गोशालाएं खोलने का विचार रखती है या नहीं?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में 1 करोड़ 39 लाख गोवंश हैं और उनमें से 15 लाख के आसपास गोवंश गोशालाओं में संधारित हैं। प्रदेश में कुल पंजीकृत गोशालाएं 4146 हैं, जिनमें से 13.57 लाख गोवंश संधारित हैं। निदेशालय गोपालन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3043 पात्र गोशालाओं को निधि अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता राशि 1056.98 करोड़ रुपये दी जा चुकी है।

माननीय विधायक महोदय ने यह जानना चाहा है कि दौसा जिले में कौन-कौन-सी गोशालाओं को कितना अनुदान दिया। दौसा जिले की 23 पंजीकृत गोशालाओं में कुल 1701 गोवंश संधारित हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय चरण में 5 पात्र गोशालाओं को राशि 47 लाख रुपये की सहायता दी गयी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण में 6 पात्र गोशालाओं को राशि 46.44 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी। वित्तीय स्वीकृति के बाद में राशि गोशालाओं के खातों में जारी की जायेगी।

साथ ही साथ, माननीय सदस्य ने यह भी जानना चाहा कि गोशालाओं के लिए और कौन-कौन-सी योजनाएं संधारित हैं, जो शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं। माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि इन गोशाला विकास योजनाओं के अलावा जो निराश्रित गोवंश हैं, उनके संधारण के लिए, उनके संरक्षण के लिए पूरे राजस्थान भर में जिला स्तर पर नन्दीशालाएं खोलने की योजना है। साथ ही साथ, पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशालाएं खोलने की योजना है, जिसमें 1 करोड़ 56 लाख रुपये का प्रावधान है। 10 परसेंट जन सहभागिता से राशि जमा करवाकर कार्य करवाने होते हैं। साथ ही साथ, हर पंचायत स्तर पर पशु आश्रय स्थल खोलने की भी योजना है। वह भी 10 परसेंट राशि जन सहभागिता से जमा करवाने का प्रावधान है।

इस तरह से तीन नयी गोशालाएं खोलने की योजना है। नन्दीशाला पंचायत समिति स्तर पर खोलने की योजना है। शहरी क्षेत्र में भी खोल सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी खोल सकते हैं। माननीय सदस्य से मेरा तो आग्रह है कि अपने क्षेत्र में पंचायतों में भी नन्दीशालाएं खुलवाएं, पंचायत समिति स्तर पर खुलवाएं, शहरी क्षेत्र में भी खुलवाएं, जिससे गोमाता का संरक्षण हो सके।

प्रश्न संख्या 168

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती धारीवाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री देवीसिंह शेखावत।

बानसूर की कृषि मण्डियों द्वारा स्वीकृत कार्य

169. श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बानसूर के उप खण्ड नारायणपुर की कृषि मण्डी को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर की कृषि मण्डियों द्वारा माह अप्रैल, 2018 से दिसम्बर, 2025 तक कितनी-कितनी राशि के कौन-कौनसे कार्य स्वीकृत किये गये? कार्यवार व राशिवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्य किन-किन संवेदकों से करवाये गये? संवेदकों के नाम एवं भुगतान राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर के नारायणपुर उप खण्ड में नारायणपुर गौण मण्डी यार्ड घोषित है, जिसमें फल-सब्जी का व्यापार होता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति, बानसूर एवं गौण मण्डी यार्ड नारायणपुर में अप्रैल, 2018 से दिनांक 31.12.2024 तक सम्पादित कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण मय स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कार्यवार/संवेदकवार परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) संवेदकों से करवाये गये कार्यों, नाम एवं भुगतान राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा पूरक प्रश्न है, नारायणपुर में जो फल-सब्जी मण्डी है, उसमें काफी बड़ा व्यापार होता है, लेकिन वहां बिजली, पानी और सार्वजनिक शौचालय की कमी है, इसलिए लोगों को बड़ी असुविधा होती है। मेरी मंत्री जी से मांग है कि इन मांगों को पूरा किया जाये।

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है, हमारी मण्डी बानसूर और मण्डी नारायणपुर और कृषि मण्डी से जो कार्य करवाये गये, 2018 से जो कार्य हुए हैं, उनकी क्वॉलिटी अच्छी नहीं है, उनकी अन्य एजेंसी से जांच करवाकर मुझे उसकी रिपोर्ट भिजवाने का श्रम कराएं।

श्री अध्यक्ष: यह सुझाव है, प्रश्न पूछें।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि इनकी जांच करायी जाये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 2018 से 2024 तक नारायणपुर यार्ड में 330 लाख 53 हजार के कार्यों की स्वीकृति हुई, जिसमें 283.46 लाख के कार्य हुए। विधान सभा क्षेत्र बानसूर के अन्तर्गत जो कृषि उपज मण्डी समिति बानसूर एवं कृषि उपज मण्डी समिति अलवर के अधीन आपकी जो गौण मण्डी नारायणपुर आती है, इसमें 20 दुकानें अभी तक निर्मित हैं, जिसमें 8 दुकानें आवंटित हैं और 12 दुकानें अभी रिक्त हैं। दिनांक 03.08.2022 को आवंटन विज्ञप्ति जारी की गयी थी, परन्तु कोई भी आवेदन इसमें प्राप्त नहीं हुआ।

आपका जो इनमें विकास कार्य हेतु प्रश्न है, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया, हमने 330 लाख के कार्य स्वीकृत किये, जिनमें से 283 लाख के कार्य पूर्ण हो चुके। जो आपकी मांग है पानी, बिजली और शौचालय की, उसे हम पूरा करेंगे, जो भी उसमें कमी है, उसे दुरुस्त करेंगे। जो कार्य किये गये, उनकी गुणवत्ता को लेकर जो आपका प्रश्न है, मैं आपको आश्वस्त करते हुए कहना चाहूंगा कि हम इसकी जांच कराएंगे और जो भी कमी है, उसे दुरुस्त कराया जायेगा।

प्रश्न संख्या 170

श्री अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

स्मार्ट पीडीएस योजना

171. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में केन्द्र सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना की वर्तमान कार्यान्वयन की क्या स्थिति है? उक्त योजना के अन्तर्गत कितने उचित मूल्य के दुकानदारों का डिजिटलीकरण किया गया है?

(2) उक्त योजना के माध्यम से प्रदेश के कितने लाभार्थियों को पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से राशन वितरण सुनिश्चित किया गया तथा डिजिटलीकरण के पश्चात अनियमितताओं में कितनी कमी आयी है?

(3) प्रदेश में उक्त योजना के अन्तर्गत कितने जिलों व उचित मूल्य की दुकानों को सम्मिलित किया गया है? सरकार की शेष जिलों में योजना को लागू करने की क्या समय-सीमा है?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) भारत सरकार द्वारा स्मार्ट पीडीएस (Scheme for modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System) योजना अप्रैल, 2023 से प्रारम्भ कर मार्च, 2026 तक लागू रहेगी।

इसके तहत राशन कार्ड मैनेजमेंट, सप्लाई चेन ऑपरेशन, एफपीएस ऑटोमेशन, पोर्टेबिलिटी डाटा प्रमाणीकरण, डाटा विश्लेषण, राशन कार्डो के डी-डूप्लिकेशन/प्रमाणीकरण से सम्बन्धित कार्य किये जा रहे है।

वर्तमान में 25,527 उचित मूल्य दुकानदारों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है, जहां पर ई-पोस मशीन, IRIS मशीन एवं इलैक्ट्रॉनिक तुलनयंत्र से संयोजित किया जा चुका है।

(2) उक्त योजना के माध्यम से प्रदेश के 1,06,34,518 राशन कार्डधारी, 4,39,08,363 यूनिट को बायोमेट्रिक सत्यापन पश्चात पारदर्शी रूप से प्रतिमाह समयबद्ध तरीके से राशन

वितरण किया जा रहा है।

सम्बन्धित लाभार्थी को बायोमेट्रिक सत्यापन पश्चात राशन सामग्री वितरण होने से अनियमितता की सम्भावना नगण्य है।

(3) उक्त योजना के तहत प्रदेश के समस्त 41 जिलों की उचित मूल्य की 25,527 दुकानों को शामिल किया गया है, जिनमें से शेष 4 दुकानों- बीलखेड़ा डांग (जिला बारां) की 2, मोठड़ी (जिला बाड़मेर) की 1, छींड (कोटपूतली-बहरोड़) की 1 में नेटवर्क समस्या के कारण उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के बिना ऑफ-लाइन वितरण किया जा रहा है।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि राज्य सरकार द्वारा जो उचित मूल्य की दुकानों पर वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री है, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामलों में अब तक कितनी कार्यवाही हुई है? यह जो गुणवत्ता की हम जांच करेंगे, क्या कोई इसके लिए हमने अलग से जांच कमेटी बैठायी है?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि अनियमितता को रोकने के लिए हमारे अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जाती है और जहां भी उचित मूल्य की दुकानों पर अनियमितता पायी जाती है, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी की जाती है, जिसमें निलम्बन होना एवं ज्यादा गम्भीर कार्यवाही होने पर उचित मूल्य दुकानदार का लाइसेंस निरस्त करने का कार्य भी हमारे विभाग द्वारा किया जाता है।

MKD/RTM/25.02.2025/11:20/1c

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि राज्य सरकार उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं और चावल के अलावा दाल, तेल, चीनी और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों को भी अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं? क्या सरकार इस व्यवस्था का विस्तार करने पर विचार कर रही है ताकि गरीब और जरूरतमन्द परिवारों को अधिक लाभ मिले सके? इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कौन से तंत्र विकसित किये गये हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यगण को बताना चाहता हूं कि इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी की भावनाओं को देखते हुए, हमारे राशन की उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, उन 5000 हजार दुकानों को अन्नपूर्णा स्टोर के रूप में विकसित करने की बजट में घोषणा की है, जिससे अनेक प्रकार की सामग्री वहां पर मिलेगी, उचित मूल्य पर मिलेगी, जिससे हमारे लाभार्थियों

को लाभ मिलेगा। साथ ही, जो हमारे उचित मूल्य का दुकानदार है, उसकी आमदनी भी बढ़ेगी और साथ ही ग्रामवासी हैं, जहां दुकान है, जहां क्षेत्र है, उन क्षेत्रवासियों को भी लाभ मिलेगा।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने बजट में 5000 उचित मूल्य दुकानों पर अन्नपूर्णा स्टोर की घोषणा की है।

प्रश्न संख्या 172

श्री अध्यक्ष: श्री हरीश चौधरी।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 173

श्री भीम राज भाटी।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री युनूस खान।

डीडवाना में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु संचालित योजनाएं

174. श्री यूनुस खान (डीडवाना): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में माह जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2024 तक केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई? वर्षवार व योजनावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं में विगत तीन वर्षों में कितने लोगों को लाभान्वित किया गया? लाभान्वितों का योजनावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा (1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2022 से दिसम्बर 2024 तक स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त संचालित योजनाओं के तहत विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में विगत 03 वर्षों में लाभान्वित किये गये लोगों की योजनावार संख्यात्मक सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे उत्तर तो मिल गया है, आज ही मिला है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से आग्रह है कि मैंने

अल्पसंख्यकों के बारे में पूछा है। मैंने मुस्लिम के बारे में नहीं पूछा है। राजस्थान में 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी हैं। इन्होंने मुझे खाली मदरसा बोर्ड का जवाब भेजा है।

आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस प्रदेश में सवा करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें हमारे जैन भाई भी रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं, सब रहते हैं तो उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है? उसका जवाब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। वे मुझे पूरा दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, समय का अभाव था या समझने में, क्योंकि मैंने प्रदेश में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए क्वेश्चन पूछा है। मैंने मुस्लिम उत्थान के लिए नहीं पूछा। उसमें भी मुझे सिर्फ मदरसा बोर्ड का जवाब मिला है।

मेरा आपसे आग्रह है कि मदरसा बोर्ड के अलावा भी, मैं इनका वह देख रहा था, मदरसा बोर्ड के अलावा भी अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी, वक्फ विकास परिषद, मुस्लिम वक्फ ये सब हैं। जो इन्होंने जवाब दिया है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा।

मैं आपके माध्यम से इतना ही आग्रह करूंगा कि बाकी समुदाय जैसे सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, इनके लिए भी क्या राज्य सरकार कोई योजना बनाने का विचार रखती है? या उनकी कोई योजना है तो मुझे नये सिरे से उत्तर दे दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर, मेरी ऐसी कोई जिद नहीं है।

दूसरा मेरा यह है, मैं इनका वक्फ बोर्ड का पढ़ रहा था। मैं माननीय मंत्री जी से एक तो यह निवेदन करूंगा कि एक बार पुनः इन सब समुदायों को जोड़ते हुए जवाब दे दें। दूसरा यह है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन, जो भेजा है माननीय मंत्री जी ने, कांग्रेस वाले हमेशा यह कहते हैं कि हम, साहब, अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं। आप कांग्रेस सरकार का इम्प्लीमेंटेशन देखिये, उन्होंने किस तरीके से, आपके इस उत्तर को ही मैंने देखा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 89 काम घोषित किये, उनमें से सिर्फ दो काम कम्प्लीट किये हैं, सिर्फ दो काम कम्प्लीट किये हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार, अभी हमारी केन्द्रीय सरकार ने भी बजट रखा, वर्तमान सरकार ने भी बजट रखा, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ हमें काम करना चाहिए।

पिछली सरकार 2018 से लेकर 2023 तक चली, क्या उसके कार्यकाल में, आपने उस कार्यकाल की मुझे रिपोर्ट भेजी है, क्या सरकार उस कार्यकाल के जांच का विचार रखती है? अगर रखती है तो अकेले वक्फ बोर्ड को अगर आप पकड़ लेंगे तो उसमें लगभग 1 करोड़ 71 लाख की इनकम बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप जहां भी जाओगे वहां वक्फ की सम्पत्तियां मिलेंगी, तो यह पैसा खा कौन रहा है? यह पैसा खा कौन रहा है? सरकार क्या इसकी जांच करवायेगी? यह मेरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार भी अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए लगातार योजनाएं चला रही हैं। मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, मुख्य मंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, नि:शुल्क छात्रावास योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने हेतु कार्यक्रम, मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, ये सब इस तरह की योजनाएं हैं जो समस्त अल्पसंख्यक वर्ग को सम्मलित करते हुए, सबका साथ, सबका विकास कार्यक्रम को देखते हुए काम कर रही हैं।

आपका दूसरा प्रश्न कि जो कांग्रेस के शासन में 89 घोषणाएं हुईं, उनमें से दो पर ही काम हुआ। माननीय सदस्यगण की यह बात रखते हुए कि प्रधान मंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, यह बिलकुल सत्य है। देश में जो भी काम हो रहे हैं, चाहे प्रधान मंत्री आवास योजना देखें, चाहे खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थी देखें, कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग अलग रहा है। यदि सबसे अधिक किसी योजना का लाभ भारत के सभी नागरिकों के साथ, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त, जो 6 वर्ग आपने बताये हैं, उन सबने लाभ लिया है और राजस्थान में भी उन सबने लाभ लिया है।

मैं आपके माध्यम से जो आपने बात की, जो पिछली सरकार के दौरान कार्यों में कमियां रही हैं और आप उनकी जांच चाहते हैं तो आप मुझे बता देना, हम उसकी जांच करवाकर, उस पर जरूर कार्यवाही करेंगे।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे माननीय भजन लाल जी की सरकार पर कोई अविश्वास नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के साथ काम करेगी, लेकिन ये जो तथाकथित लोग ग्राउंड के अन्दर साफा बांधते हैं, मालाएं पहनते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं तो जनता के सामने इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं यह लाना चाह रहा था कि जनता के सामने यह आये कि यह खाली वोट के लिए ही ऐसा कर रहे हैं।

इसलिए, आप मेरे क्वेश्चन का नये सिरे से दोबारा जवाब देंगे तो उसमें सारी चीजें आ जायेंगी। पुन: मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि क्या आप जांच करवायेंगे? खाली वक्फ बोर्ड की करवा दीजिये, जिससे जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: आप मिल लें। आपको कुछ बोलना है, कुछ उत्तर देना है तो बताये।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: अब नहीं, नहीं, विराजो। नई परम्परा नहीं, विराजो। माननीय सदस्य, नो। मंत्री जी कुछ जवाब देना है तो बोलिये।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): जैन और सिख वाले में जवाब दिलवा दें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, डीडवाना से

आने वाले सदस्य, वरिष्ठ सदस्य हैं। इन्होंने बात रखी है तो उसमें जरूर कुछ न कुछ तथ्य होंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसकी हम जांच करायेंगे और बिलकुल दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे।

प्रश्न संख्या 175

श्री अध्यक्षः श्री कान्ति प्रसाद।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल।

ग्राम बहरावण्डा खुर्द (खण्डार) में ट्रोमा सेंटर की स्थापना

176. श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) प्रदेश में ट्रोमा सेन्टर खोले जाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्राम बहरावण्डा खुर्द में ट्रोमा सेन्टर खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) भारत सरकार की ट्रोमा गार्इडलाइन के अनुसार दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 50 किलोमीटर से अधिक परिवहन की आवश्यकता न पडे, इसी क्रम में प्रत्येक 100 किलोमीटर पर एक ट्रोमा सेंटर खोले जाने का प्रावधान है। विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) खण्डार के ग्राम बहरावण्डा खुर्द से नजदीकी ट्रोमा सेंटर मलारना चौड, सवाईमाधोपुर की दूरी 63 किलोमीटर एवं ट्रोमा सेंटर सवाई माधोपुर की दूरी लगभग 26 किलोमीटर है।

अतः वर्तमान में खण्डार के ग्राम बहरावण्डा खुर्द में ट्रोमा सेंटर खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सबसे पहले तो यह पूछा है कि कोई भी ट्रोमा सेंटर स्टेट में बनता है तो उसके क्या नियम और रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि 50 किलोमीटर आप कहीं भी हैं, कोई भी मैन रोड पर, उससे 50 किलोमीटर दूर एक ट्रोमा सेंटर होना चाहिए और दो ट्रोमा सेंटर के बीच में 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए।

आपने जो बहरावण्डा के बारे में बात की, आपने बोला कि वहां पर ट्रोमा सेंटर बनाना रूल्स, रेगुलेशन के अनुसार सम्भव है। इसमें नहीं है, क्योंकि सवाई माधोपुर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वह केवल 26 किलोमीटर दूर है।

फिर भी, माननीय सदस्य के वहां बहरावण्डा है। मैं वहां पर एक प्राइमरी ट्रोमा सेंटर नया खुलवा दूंगा। जिसके अन्दर 45 इक्यूपमेंट होंगे और सर्टेन इक्यूपमेंट जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटीलेटर व ट्रेंड स्टाफ होगा। यूं भी 26 किलोमीटर दूर आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके बावजूद वहां पर आपके हाईवे पर मूवमेंट आपके काफी है, इसके लिए मैं आपके वहां प्राइमरी ट्रोमा सेंटर खोल दूंगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य,पूछना है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): धन्यवाद, माननीय मंत्री महोदय, आपने मेरी मांग को स्वीकार किया, क्योंकि खण्डार विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आपने बताया कि नॉर्म्स के हिसाब से 50 किलोमीटर का जो पैरामीटर है।

Bhs/Rtm/25.02.25/11.30/1d

लेकिन उसके बाद भी आपने मेरी मांग को स्वीकार किया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चूंकि खण्डार विधान सभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिये खण्डार की दूरी सवाई माधोपुर से लगभग 75 किलोमीटर है। मैंने कई बार सरकारों से उप जिला स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग रखी। आपसे निवेदन है कि मेरी उस मांग को भी गम्भीरता से लेकर और उस पर भी इसी तरह बड़ा मन रख कर सरकार से कार्यवाही करा दें। धन्यवाद। मैं आपके जवाब से संतुष्ट हूं।

प्रश्न संख्या 177

श्री अध्यक्षः श्री रामनिवास गावड़िया।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री कालूराम।

धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार व तीर्थ यात्रा पर व्यय

178. श्री कालूराम (डग): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष निर्माण, जीर्णोद्धार, तीर्थ यात्रा एवं अन्य आधारों पर कितना बजट आवंटित एवं कितना व्यय किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में वर्ष की समाप्ति पर विभाग की विनियोजित राशि एवं वर्ष में विनियोजन से प्राप्त आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में नवीन धर्मस्थलों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला झालावाड़ में वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत संचालित देवालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

देवस्थान मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(1) विगत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष निर्माण, जीर्णोद्धार, तीर्थयात्रा व अन्य आधारों पर बजट आवंटित एवं व्यय की सूचना परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विगत पांच वर्षों में वर्ष की समाप्ति पर विभाग की विनियोजित राशि एवं वर्ष में विनियोजन से प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) देवस्थान विभाग के स्तर से विगत पांच वर्षों में कोई नवीन धर्म स्थल का निर्माण

नहीं किया गया है।

(4) झालावाड़ जिले में वर्तमान में देवस्थान के अंतर्गत संचालित मंदिरों की सूची परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि हमारी सरकार 2013 से 2018 में रही उस समय कई मन्दिरों का जीर्णोद्धार हुआ और बहुत अच्छा काम हुआ और आपने खण्ड 3 पर लिखा है कि देवस्थान विभाग स्तर पर विगत पांच वर्षों में कोई नवीन धर्म स्थल का निर्माण कार्य नहीं किया गया। यह कांग्रेस सरकार ने पिछले पांच वर्ष में ऐसे कोई नवीन धर्म स्थल का निर्माण नहीं किया तो क्या अपनी सरकार नये मन्दिरों के निर्माण करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने देवस्थान विभाग पर ध्यान नहीं दिया, जो थोड़े बहुत काम हुए वो भी उन्होंने स्वीकृत किये वो भी पूरे नहीं कराये। खाटू श्याम जी सहित 14 मन्दिरों के उन्होंने बजट में घोषणाएं की थी लेकिन वो काम भी उन्होंने पूरे नहीं करवाये और सरकार बदलने के बाद में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी माननीय भजन लाल जी उन कामों को भी वापस जोड़ते हुए बीस मन्दिरों की स्वीकृति इस बार 2024-25 के बजट में की है, जिनके ऊपर डी.पी.आर. बन रही है, एस्टीमेट बन रहे हैं और प्रक्रियाधीन है।

साथ ही साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी इस वर्ष जो बजट पेश हुआ है उसमें भी माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश हैं, वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी ने करीब 45 मन्दिरों के जीर्णोद्धार, उनके रखरखाव व सुविधाएं विकसित करने के काम की भी इस बार बजट में घोषणा की है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार संवेदनशील है। देवस्थान के प्रति, मन्दिरों के प्रति और मन्दिरों के विकास के प्रति संवेदनशील है और आगे भी जो माननीय सदस्य बतायेंगे उसके अनुरूप सरकार काम करेगी।

श्री कालूराम (डग): नम्बर 2, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में काया वर्णेश्वर महादेव मन्दिर बहुत ही प्राचीन मन्दिर है, कल शिवरात्रि पर करीब 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां दर्शन करने आयेंगे इसलिये हमारी वसुन्धरा राजे जी की सरकार में अस्सी लाख रुपये स्वीकृत हुए थे 2013 से 2018 में। हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस की सरकार आई, उसने उस राशि को लैप्स कर दिया। क्या, माननीय मंत्री महोदय, आप पुनः उस राशि को स्वीकृत करने के आदेश फरमायेंगे? और उस जगह पर डेढ़ किलोमीटर मात्र रोड है वो अगर डिवाइडर बन जाता है तो श्रद्धालुओं को आने-जाने में सुविधा रहेगी, और भी काफी मन्दिर हैं, उस पर आप विचार करें और उस राशि को पुनः स्वीकृत करने की क्या मंशा है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में हमारे देवस्थान विभाग के 593 मन्दिर हैं, उनमें 552 राजस्थान में हैं और 41 मन्दिर राजस्थान से बाहर हैं। उन मन्दिरों के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बार बजट में घोषणा की है। 101 करोड़ राजस्थान के मन्दिरों के विकास के लिए और साठ करोड़ जो राजस्थान से बाहर हैं उनके विकास के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। साथ ही साथ में अंशकालीन पुजारी जिनको लम्बे समय से वेतन में उनके वृद्धि नहीं हो रही थी, उनको पांच हजार से पच्चीस सौ बढ़ा कर साढ़े सात हजार करने की भी घोषणा की है।

साथ ही साथ में मन्दिरों में जो भोग के पैसे हैं वो बहुत लम्बे समय से 1500 रुपये दिये जा रहे थे तो उनको भी सीधा डबल करके 3000 करने की भी घोषणा की है, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रयागराज में वहां पर जो महाकुम्भ चल रहा है उस महाकुम्भ में कैबिनेट की बैठक बुला करके वहां यह देवस्थानों के बहुत सारे निर्णय लिये। निश्चित रूप से हमारी सरकार सनातन के प्रति भी संवेदनशील है, देवस्थान के प्रति भी संवेदनशील है और आगे भी ऐसी घोषणाएं होती रहेंगी। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा लेकिन साथ ही साथ में यह बात भी कहना चाहूंगा जो माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि झालावाड़ जिले में ...

श्री कालूराम (डग): काया वरणेश्वर महादेव।

श्री अध्यक्षः इनको मिल गया है।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): काया वर्णेश्वर महादेव मन्दिर जो मन्दिर श्री काया वर्णेश्वर महादेव मन्दिर प्रबन्ध समिति, ग्राम क्यासरा, तहसील गंगधार, जिला झालवाड़, राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास का मन्दिर है। प्रन्यास मन्दिर श्री काया वरणेश्वर महादेव, झालावाड़ में सार्वजनिक सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2017-18 में माननीय वसुन्धरा राजे जी की सरकार थी उस समय बजट मद में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यों की कार्यकारी एजेंसी राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा कार्य की कुल लागत 180 लाख रुपये की स्वीकृति की गई थी, जिसमें वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधित राशि बीस लाख रुपये एवं वर्ष 2018-19 के विरुद्ध 160 लाख रुपये व्यय किये जाने की स्वीकृति दी गई थी। तत्पश्चात शासन के पत्रांक 2/देव/20148, जयपुर, दिनांक 15.6.2018 के अनुसार उक्त मन्दिर की कार्यकारी एजेंसी R.S.R.D.C. के स्थान पर देवस्थान विभाग को बनाया गया।

श्री अध्यक्षः हो गया, मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह सारी स्वीकृति होने के बाद में भी जो पिछली सरकार थी उन्होंने इस मन्दिर के प्रति उदासीनता रखी और बाद में सरकार चैंज हो गई और वसुन्धरा जी की सरकार भारतीय

जनता पार्टी की सरकार चैंज हो गई। पांच साल कांग्रेस की सरकार रही उस कांग्रेस की सरकार ने इस काम को कैंसिल किया। इस काम को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया तो मैं माननीय सदस्य को भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति का परीक्षण करवा कर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

श्री कालूराम (डग): बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर (दक्षिण) के गुलाबबाड़ी में मातृ वन की स्थापना

179. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) की गुलाबबाड़ी वन खण्ड में मातृ वन बनाए जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विगत वर्ष में उक्त मातृ वन हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बजट 2024-25 में नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ वायु के लिए 175 करोड़ से अधिक की लागत से पौधारोपण एवं पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो उक्त घोषणा के तहत अब तक कितने कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय कर कहां-कहां पार्क बनाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी नहीं ।

(2) जी हां । नगरीय विकास विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त घोषणा के तहत अब तक किये गये कार्य का विवरण परिशिष्ट - 1 पर सलंग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि प्रदेश में मातृ वन की स्थापना की घोषणा बजट में हुई, ये मातृ वन जिले में कहां-कहां स्थापित हुए, कितने जिलों में स्थापित हुए और अजमेर जिले में मातृ वन कहां स्थापित करने जा रहे हैं? एक प्रश्न तो मेरा यह है।

दूसरा प्रश्न है, जो जवाब के खण्ड 2 का है। 175 करोड़ रुपये की घोषणा हुई है, 175 करोड़ रुपये में 43 करोड़ 29 लाख रुपये के काम स्वीकृत हुए, 3 करोड़ 92 हजार रुपये के काम प्रगति पर हैं। क्या अजमेर जिले में शेष रहे 131 करोड़ में से अजमेर जिले में भी पार्क अथवा ग्रीन लैंड्स बनाने की मंशा रखते हैं?

Kas/rtm/25.02.2025/11.40/1e

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्या ने मातृ वन के सन्दर्भ में प्रश्न किया है, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि जिलेवार सूची या तो मैं माननीय सदस्या को उपलब्ध करा दूंगा, मेरे पास है, मैं आपको

उपलब्ध करा दूंगा।

दूसरा प्रश्न आपने किया है, मैंने आपको उत्तर में भी कहा है कि यह कार्य यू.डी.एच. विभाग द्वारा कराये जायेंगे। क्योंकि प्रश्न हमको भेजा गया था, मैंने आपको जानकारी दी है और मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि अजमेर से सम्बन्धित जो भी कार्य हैं, वो माननीय सदस्या को बता दें।

साथ ही साथ जो मेरी आपसे अभी चर्चा हुई, आप अजमेर गुलाबबाड़ी नगर वन के बारे में जानकारी चाह रही हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पिछले बजट में यह घोषणा की गई थी और उसको लेकर 50 हैक्टेयर में 2 करोड़ रुपये का प्रस्ताव जुलाई माह में भारत सरकार को भेजा गया था। कुछ क्वेरीज भारत सरकार द्वारा मांगी गई थी और हमारे अधिकारियों ने बताया कि वो क्वेरीज पूरी करके भारत सरकार ने आश्वस्त किया है कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर उस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया जायेगा और काम बहुत शीघ्र शुरू हो जायेगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कंवरलाल।

जिला बारां में श्रमिक कार्ड योजना के लाभार्थी

180. श्री कंवरलाल (अंता): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं का श्रमिक कार्ड धारक एवं उनके परिजन किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बारां में सरकार द्वारा वर्ष 2020 से दिनांक 15.01.2025 तक कितने पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कर कितनी राशि व्यय की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में उक्त अवधि में कितने पात्र व्यक्तियों को बजट के अभाव में लाभान्वित नहीं किया गया? सरकार द्वारा उक्त पात्र व्यक्तियों को कब तक लाभान्वित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): (1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। उक्त योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिक एंव उनके परिजन ऑनलाइन माध्यम (स्वयं की एसएसओ आईडी या ई-मित्र) से योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु एलडीएमएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।

जिला बारां में मण्डल द्वारा वर्ष 2020 से दिनांक 15.01.2025 तक 29,418 आवेदनों के स्वीकृत कर राशि रुपये 34,55,48,985 (चौतीस करोड़ पचपन लाख अड़तालीस हजार नौ सौ पिच्यासी) व्यय की गई है। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

उक्त जिला में उक्त अवधि में योजनाओं के शून्य आवेदन लम्बित हैं। मण्डल की विभिन्न योजनाओं आवेदनों के निस्तारण तथा भुगतान की प्रक्रिया जारी हैं योजना आवेदनों का

निस्तारण वरीयतानुसार एवं पात्रतानुसार यथाशीघ्र किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खण्ड तीन में कहा है कि उक्त जिले में उक्त अवधि में योजना में शून्य आवेदन लंबित हैं। नीचे उन्होंने लिखा है कि मंडल की विभिन्न योजनाओं में आवेदनों के निस्तारण तथा भुगतान प्रक्रिया जारी है। योजना आवेदनों का निस्तारण वरीयता अनुसार एवं पात्रता अनुसार यथाशीघ्र किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने प्रश्न में पूछा है कि उक्त जिले में उक्त अवधि में कितने पात्र व्यक्तियों को बजट के अभाव में लाभान्वित नहीं किया गया। इसमें यह कहना है कि बजट के कारण एक भी लाभान्वित लंबित नहीं है, प्रक्रिया के कारण 79 लाख लंबित हैं। बजट के कारण नहीं है, बजट की इस सरकार में कोई कमी नहीं है।

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में वास्तविक श्रमिक, जो बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, पुलिया बनाने में काम करते हैं, उनका सर्वे करवा कर इस योजना में आवेदन कराने की क्या प्रक्रिया है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस योजना में चाहे जिसने आवेदन किया है, जो वास्तविक श्रमिक है, वास्तविक मजदूर है, उसमें ठेकेदार या मकान मालिक के माध्यम से उस आवेदनकर्ता को ही उस काम में लगायें, ताकि उसको फायदा मिले।

अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा मंत्री महोदय से एक और निवेदन है कि आवेदन कर दिया, लिस्टेड हो गया और जब वह छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये आवेदन करता है तो उस ठेकेदार के, उस मकान मालिक के साइन कराने के लिये चक्कर काटता है, उसके पास कोई रजिस्टर नहीं होता है, कोई दर्ज नाम नहीं होता है और वो साइन करने के पैसे वसूल करते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर रोक लगाने की या रजिस्टर बनाने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पहले तो जो इन्होंने बात रखी कि इसमें इस तरह का कोई प्रसंग आया, वो हमारे संज्ञान में नहीं है। ऐसा कोई प्रसंग हो तो आप जरूर बताना, सरकार उस पर कार्यवाही करेगी।

दूसरा, आपने श्रमिकों के लिये बताया, तो श्रमिकों के लाभ के लिये तो अनेक योजनाएं चल रही हैं, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसे निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना है। इसमें श्रमिकों के जो बच्चे छठी से लेकर एम.ए. तक पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसमें 8 हजार से अधिकतम 25 हजार तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है। दूसरी, प्रसूति सहायता योजना है, इसमें भी जो महिला श्रमिक कार्ड धारक है,

उसको दो बच्चों पर यह राशि मिलती है। पुत्र होने पर 20 हजार और पुत्री पर 21 हजार मिलते हैं। इसमें जन्म होने पर पहली किस्त दी जाती है, दूसरी किस्त एक साल पूर्ण होने पर और तीसरी पांच साल बाद जब बच्चा फर्स्ट में एडमिशन लेता है, तब दी जाती है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं, जैसे खाताधिकारी के सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना है। इसमें 5 लाख दुर्घटना होने पर राशि मिलती है, जिसमें 50 परसेंट कैश और 50 परसेंट एफ.डी. है। 3 लाख स्थायी अपंगता, 1 लाख अस्थायी अपंगता पर मिलते हैं। सिलिकोसिस को लेकर भी योजना है।

आपका विशेष फोकस था कि किस तरह के श्रमिक हो सकते हैं, उन श्रमिकों के लिये एक विशेष योजना चल रही है निर्माण श्रमिक औजार सहायता योजना। इसमें कोई भी श्रमिक हो, उसको 2 हजार रुपये तक के औजार के लिये सरकार द्वारा राशि प्रदान की जाती है, चाहे हजार रुपये के हों चाहे 1500 रुपये के हों, बिल देने पर उसमें दो हजार रुपये तक की राशि सरकार द्वारा दी जाती है।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह।

आसीन्द के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

181. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं? उक्त केन्द्रों में कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में कुल 335 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं तथा रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्न तालिका के अनुसार है-

परियोजना	कुल आंगनबाड़ी केन्द्र	कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की संख्या	कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिकाओं की संख्या	आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की संख्या
आसीन्द	135	135	00	129	06
हुरडा	131	130	01	126	05
बदनोर	69	68	01	58	11
कुल	**335**	**333**	**02**	**313**	**22**

2. आसीन्द विधान सभा के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मानदेय सेवा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं

सहायिकाओं के सभी रिक्त पदों को समेकित करते हुए जिला स्तर से विज्ञप्ति जारी करवाकर विभागीय नियमानुसार चयन प्रकिया शीघ्र सम्पादित करायी जायेगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि सरकार ने 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी की जो गाइड लाइन बना रखी है, अध्यक्ष महोदय, यह जनगणना 2011 के आधार पर है। मंत्री महोदय, 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी खोलने का जो प्रावधान है, क्या इसको 500 की जनसंख्या पर करने का विचार रखते हैं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा कि यह जो फोटो लगा था, यह विधान सभा सचिवालय से गलत लगा है या मेरे साथी ने यही फोटो दिया है?

श्री अध्यक्षः ठीक कर देंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोल सकता हूं?

श्री अध्यक्षः नहीं, बाद में। इसी विषय में?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि फीलिंग सही नहीं आ रही है, कुछ सदस्य उधर बैठ जाएं या सामने वालों की तस्वीरें लगा दो आप।

श्री अध्यक्षः बैठिए। हो गया आपका पूरक प्रश्न? माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नये आंगनबाडी खोलने के जो नार्म्स हैं, जो माननीय सदस्य ने बात रखी है, यह भारत सरकार के नॉर्म्स के आधार पर होते हैं। वहां जो नॉर्म्स होंगे, उसी के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे।

Msk/rtm/25.02.25/1150/1f

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या सरकार प्रस्ताव बनाकर भेजने का विचार रखती है?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को दोबारा बताना चाहूंगी कि अगर भारत सरकार नॉर्म्स आगे बनायेगी तो बिल्कुल राजस्थान सरकार भी उन्हीं नॉर्म्स के अंतर्गत नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलेगी।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्रीमती शोभा चौहान।

सोजत के चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण

182. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत के राजकीय चिकित्सालयों के निर्माण, मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु विगत पांच वर्षों में कितना बजट आवंटित किया गया? वर्षवार एवं संस्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उप जिला चिकित्सालय सोजत के जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नति के उपरांत चिकित्सालय के निर्माण, नवीनीकरण एवं मरम्मत हेतु आवंटित बजट के किस-किस मद से क्या-क्या कार्य करवाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में राजकीय चिकित्सालयों के निर्माण, मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु विगत पांच वर्षों में बजट आवंटित का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) उप जिला चिकित्सालय सोजत के जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नति के उपरान्त चिकित्सालय के निर्माण, नवीनीकरण एवं मरम्मत हेतु बजट मद एनएचएम पीआईपी में एल.एम.यू. का निर्माण करवाकर हस्तान्तरित किया जा चुका है तथा एनएचएम के अन्तर्गत न्यू डीडीसी का कार्य प्रगतिरत है। विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि प्रश्न संख्या एक के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट-अ के अनुसार सोजत विधान सभा क्षेत्र में राजकीय चिकित्सालयों निर्माण, नवीनीकरण एवं मरम्मत हेतु वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक कुल स्वीकृत राशि 715.94 लाख रुपये दर्शायी गयी है। कृपया मंत्री जी यह बताने का श्रम करें कि इसमें से अभी तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्ष में विधान सभा क्षेत्र सोजत में निर्माण कार्य के अन्दर 477.39 लाख रुपये, नवीनीकरण में 239.55 लाख रुपये का खर्चा हो चुका है। इसकी डिटेल आप चाहेंगे कि कहां-कहां लगे हैं तो मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, और पूछना है?

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): आखिरी प्रश्न है, साहब, आज का।

श्री अध्यक्ष: पूछो, नहीं तो उनके प्रश्न मैं पूछूंगा।

उचित मूल्य की दुकानों पर चीनी की आपूर्ति

183.श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर चीनी आपूर्ति कब से बन्द है?

(2) क्या सरकार उचित मूल्य की दुकानों पर चीनी आपूर्ति पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) सक्षम स्तर पर निर्णय के उपरान्त उचित मूल्य दुकानों पर चीनी आपूर्ति बन्द की गई थी। दिनांक 31.03.2021 को चीनी का आंवटन आदेश जारी किया गया था। उसके पश्चात कोई आदेश जारी नहीं किया

गया।

(2) जी नहीं। वर्तमान में राशन की दुकानों पर चीनी की आपूर्ति पुनः शुरू किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने जवाब में कहा कि सक्षम स्तर पर निर्णय के उपरान्त उचित मूल्य दुकानों पर चीनी आपूर्ति बन्द की गई। तो क्या इस निर्णय से प्रदेश के 6 लाख 28 हजार 582 अंत्योदय लाभार्थी परिवारों को सस्ती चीनी 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से छह किलो चीनी प्रति माह मिलती थी, वह बन्द हो गयी और अब इन गरीब परिवारों को बाजार से ढाई गुना कीमत पर 42 से 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी खरीदनी पड़ रही है? यदि हां, तो पूर्ववर्ती सरकार के समय किये गये इस अविवेकपूर्ण गरीब विरोधी निर्णय को वर्तमान सरकार क्यों नहीं बदलना चाहती? इसलिए मेरी आपसे मांग है कि गरीब विरोधी निर्णय को सरकार तुरंत वापस ले और पहले की भांति गरीब परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पुन: चीनी की आपूर्ति की जाये, जिससे उन्हें राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, डिटेल में उत्तर दे दें, ताकि दूसरा पूरक नहीं बचे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, 7 लाख परिवार हैं और वे बन्द कर दिये और अपने कहा कि सक्षम अधिकारी ने बन्द कर दिये। उस योजना को दोबारा चालू करने का कोई विचार नहीं है। हमारी सरकार तो गरीब कल्याणकारी सरकार है, मैं चाहूंगा कि आप इसको पुन: चालू करे और इसकी घोषणा यहां पर करें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): इसके साथ-साथ कैरोसीन भी चालू करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी का उत्तर आने दें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्यगण को बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर जो परिस्थिति बनी, जिसके कारण चीनी का वितरण क्यों बन्द किया गया? वर्ष 2016-17 तक बीपीएल एवं अंत्योदय परिवारों हेतु भारत सरकार द्वारा चीनी का आवंटन जारी किया जाता था, जिसमें प्रत्येक राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 500 ग्राम चीनी देय थी। वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा चीनी की नयी नीति लागू की गयी, जिसके अनुसार मात्र अंत्योदय परिवार को ही 1 जून, 2017 से एक किलो, प्रति परिवार, प्रति माह के आधार पर चीनी का वितरण किया जाना था। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु बारामती एग्रो लिमिटेड व गंगानगर चीनी मिल्स से अंत्योदय परिवारों हेतु 10816.66 मैट्रिक टन चीनी की खरीद की गयी थी। इसके पश्चात वर्ष 2020-21 में प्रथम त्रिमास अप्रेल, 2020 से जून, 2020 हेतु गंगानगर चीनी मिल्स से 1520.30 मैट्रिक टन चीनी की खरीद की गयी। पूरा विस्तार से बता रहा हूं। आप सुन रहे हैं। चीनी की आवश्यकता से अधिक क्रय.. मैं माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश था, उसी की पालना कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब सुनिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सीधा प्रश्न है कि 6 लाख से ज्यादा अंत्योदय के परिवार, जो इसके लाभार्थी थे, उनको 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी मिलती थी, वे आज उसे 42-43 रुपये में खरीद रहे हैं, तो क्या इसको पुन: चालू करने का आपको विचार है? यदि है, तो कब तक करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? जहां तक भारत सरकार का सवाल है। कई राज्यों में इस प्रकार की चीनी वितरित की जा रही है। केवल राजस्थान में पिछली सरकार ने इसको बन्द किया। मेरा सीधा-सा सवाल है कि आप इसको चालू करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य, आपने गंभीर सवाल रखा, उसके लिए आपको धन्यवाद। वैसे भी आप हमेशा गंभीर विषय ही रखते हैं। आप सबसे वरिष्ठ हैं। मैं इसमें थोड़ा-सा आपको और जवाब दे दूं, ताकि सबके समक्ष आ जाये, आप तो जानकार हैं, कई नये सदस्य हैं, उनको भी यह विषय रहे, क्योंकि कहीं भी क्षेत्र में जायें तो उनको इस बात का संज्ञान होना चाहिए। उसमें मैंने बात की थी कि गंगानगर चीनी मिल्स से चीनी खरीदी गयी, उसके बाद चीनी की आवश्यकता से अधिक क्रय, चीनी का विक्रय मूल्य 24 रुपये प्रति किलो होना, चीनी की पैकेजिंग 50 किलो की होना और प्रति एफपीएस, अपने अंत्योदय परिवारों..

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, क्या जवाब दे रहे हैं?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप हां, ना में उत्तर दे दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं आपको जो पूछ रहा हूं, उसका जवाब आप क्या दे रहे हैं।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं वही तो दे रहा हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं यह कह रहा हूं कि छह लाख परिवार जो पहले 18 रुपये किलो में चीनी खरीदते थे, वह आपने बन्द कर दी, अब उनको बाजार से 42 रुपये में खरीदनी पड़ रही है तो क्या आप दोबारा से उचित मूल्य की दुकानों पर यह चीनी वितरित करने का निर्णय करेंगे या नहीं करेंगे, आप यह बताइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप उत्साहित मत हो, आप वरिष्ठ हैं, हम तो आपसे सीखना चाहते हैं, आप आठ बार आये। हम तो यह सीखें कि किस तरह जवाब दें, ताकि दूसरे भी सीख पायें। आप तो ज्ञान के भण्डार हों, पर हम जैसे कई नये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, हां या ना में दे दीजिये, दो प्रश्न और हैं। ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप चालू करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने जो

प्रश्न पूछा कि 6 लाख 28 हजार 582 अंत्योदय लाभार्थियों को चीनी बन्द करने का जो विषय रखा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा अन्नपूर्णा भण्डार के माध्यम से कार्य शुरू किया जा रहा है। उसमें इसका वितरण प्रारंभ करने का विचार सरकार रख रही है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 184

श्री चेतन पटेल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 185

श्री मनीष यादव।

(अनुपस्थित।)

चूंकि यह प्रश्न सदन की प्रापर्टी है। माननीय सदस्य नहीं है और प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए उस प्रश्न को मैं ही पूछ लेता हूं। प्रश्न संख्या 185, वन मंत्री जी उत्तर दीजिये।

प्रदेश में मातृ वन की स्थापना

185. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट 2024-2025 में वृक्षारोपण महाअभियान के तहत सात करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में कितना वृक्षारोपण किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बजट में प्रदेश के प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक मातृ वन की स्थापना तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पेसिज कार्यक्रम का लक्ष्य भी रखा गया था? यदि हां, तो किन-किन जिलों में उक्त कार्य पूर्ण हो गये हैं? जिलावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पौधों के समुचित पालन का सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए 2000 स्थानीय व्यक्तियों को इनसेंटिव के आधार पर वन मित्र लगाने तथा इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी को पौधों की रक्षा के लिए संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) जी हां। वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत 7 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। इस अभियान के तहत वन विभाग द्वारा 80 हजार हैक्टेयर वन भूमि पर 2.50 करोड़ पौधे तथा विभिन्न विभागों/गैर सरकारी संगठनों/आमजन आदि द्वारा 4.72 करोड़ पौधे रोपित कर कुल 7 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के विरुद्ध 7.22 करोड़..

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, प्रश्न टेबल कर दीजिये, समय हो गया।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): ठीक है, साहब।

mdp/rtm/25.02.2025/12:00/1g

श्री अध्यक्षः प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री भगवाना राम सैनी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से दिनांक 21 फरवरी, 2025 की रात झुंझुनू जिले में गोठडा थाना क्षेत्र के पहाडिला गांव के माउंटेन होटल में घटित घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री पितराम सिंह काला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी में पेयजल समस्या का समाधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूँगरपुर के ग्राम बिलड़ी एवं ग्राम पंचायत पालवाड़ा में आदिवासियों की भूमि के अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से धरियावद विधान सभा क्षेत्र के झल्लारा ब्लॉक में महाविद्यालय के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

5. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से पंचायती राज चुनावों में 1995 के बाद तीसरी संतान होने संबंधी नियमों में शिथिलता प्रदान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. डा. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन जी.एस.एस. के निर्माण कार्यों में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के कुडला गांव में नगर परिषद द्वारा स्थापित सीवरेट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट जल भराव क्षेत्र में स्थित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, डा. ऋतु बनावत एवं डॉ. प्रियंका चौधरी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से चूरू जिले में बीमा कम्पनी द्वारा फसल खराबे का क्लेम नहीं दिये जाने के संबंध में।

2. श्री राजेन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महवा में नशा मुक्ति अभियान चलाकर मादक पदार्थों पर रोक लगाने के संबंध में।

3. श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर में अमृत 2.0 योजना के तहत पेयजल व्यवस्था के संबंध में।

4. श्री धर्मपाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव पुन: प्रारम्भ करवाये जाने के संबंध में।

5. श्री अंशुमान सिंह भाटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोलायत में डीएमएफटी में प्राप्त राजस्व का खनन प्रभावित क्षेत्रों में ही उपयोग किये जाने के संबंध में।

6. श्री मनोज कुमार(सादुलपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में कतिपय मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

7. श्री कैलाश चन्द वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बगरू में लैण्ड पूलिंग योजना से प्रभावित काश्तकारों की मांगों के संबंध में।

8. श्री अरूण चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में सुचारू पेयजल आपूर्ति हेतु कार्ययोजना बनाने के संबंध में।

9. श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से कोटा शहर में कोचिंग छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्या को रोकने हेतु प्रभावी योजना बनाये जाने के के संबंध में।

10. श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से जवाई परियोजना की डी.पी.आर. में आसीन्द के खारी बाँध को जोड़े जाने के संबंध में।

11. श्री हंसराज मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वन भूमि एवं पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का सीमाकंन किये जाने के संबंध में।

12. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से बून्दी में नगर विकास न्यास का गठन एवं मिनी सचिवालय की स्थापना किये जाने के संबंध में।

13. श्री मोतीराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर की सुकड़ी-सेलवाड़ा सिंचाई परियोजना की क्षतिग्रस्त नहरों व वितरिकाओं की मरम्मत हेतु बजट आवंटन करवाये जाने के संबंध में।

14. श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर, सदस्य की ओर से गबन के आरोपी अधिकारी को उसी कार्यालय में पदस्थापित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

15. श्री उदयलाल भडाना, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिले में गाडरी समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्या के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 25/02/2025 को शून्यकाल में बोलने हेतु 32 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	माननीय सदस्य का नाम	विषय
1.	श्री गोविन्द प्रसाद	जल संरक्षण हेतु नीति बनाए जाने के सम्बन्ध में।

2.	डा. सुभाष गर्ग	भरतपुर शहर में CFCD परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित 280 किलोमीटर की नालियों का निर्माण नहीं होने के संबंध में।
3.	श्री रविन्द्र सिंह भाटी	पश्चिमी राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर ख्याला मठ एवं गरीबनाथ जी के मंदिर में जीर्णोद्धार एवं व्यवस्थाओं के संबंध में।
4.	श्री प्रताप लाल भील	गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र के धोलिया जी पर्वत को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के संबंध में।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

पंचायती राज चुनावों में तीसरी संतान होने संबंधी नियमों में शिथिलता की प्रदायगी

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने स्थगन पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज पर, नगर पालिका में और सहकारिता में जब किसी के तीन बच्चे होते हैं तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, उसके भले ही चार लड़के हों, पांच लड़के हों, दस लड़के हों या तो एम.एल.ए., एम.पी. के भी तीसरी संतान वाला नियम लागू होना चाहिए, नाम तो मैं काउंट करूं अच्छी बात नहीं है, परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, जिस प्रकार की जनसंख्या पूरे देश में कम पड़ रही है, या तो आप तीसरी संतान वाला मामला पंचायत राज में खतम करें, नगरपालिका में खतम करें या सहकारिता में खतम करें। यदि आप इसको लागू करना चाहते हैं तो एम.एल.ए., विधायक और सांसद पर भी लागू कीजिए।

माननीय मंत्री महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। अच्छे जन-प्रतिनिधि भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। काफी ऐसे जन-प्रतिनिधि हैं, जिनके तीसरी संतान होने की वजह से, दो-दो लड़कियां हो गयी, लड़के के इंतजार में तीन-तीन, चार-चार लड़के हो गये तो चुनाव नहीं लड़ पाये, इसलिए माननीय मंत्री महोदय इसको संशोधन करते हुए, इसका प्रस्ताव लेते हुए सरकार तीसरी संतान वाला मामला हटाते हुए आने वाले पंचायत राज चुनाव में तीन संतान हो, चार संतान हो, पांच संतान हो, छह संतान हो या दस संतान हो, वह चुनाव पंचायती राज का भी लड़े, नगर पालिका का भी लड़े, सहकारिता का भी लड़े। यह बहुत गंभीर मामला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में आना चाहिए। माननीय संसदीय कार्यमंत्री बैठे हैं और उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी बैठे हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। इस गंभीर मामले को लेते हुए एक प्रस्ताव आप लाएं। मदन जी दिलावर भी पंचायती राज मंत्री बैठे हैं, उन्होंने भी मेरे को कहा, मैं इनसे मिला भी था, पंचायती राज मंत्री से, उन्होंने कहा कि पंचायती राज में जो तीसरी संतान वाला मामला है, आने वाले पंचायती राज चुनाव में हटाएंगे, नगर पालिका चुनाव में हटाएंगे। जनसंख्या की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, क्योंकि इस कारण, माननीय

अध्यक्ष महोदय, आप एक बार सुनें और सरकार के संज्ञान में लाएं कि आने वाले दिनों में ये तीसरी संतान वाले मामले को हटाते हुए या अगली बार जो भी विधायक बनेगा, उसके भी तीसरी संतान वाला मामला लागू होगा। जो लोक सभा में जाएगा, उसके भी तीसरी संतान वाला मामला लागू होगा या राज्य सभा में जाएगा, उसके भी तीसरी संतान का मामला लागू होगा। या तो नियम लागू करवाएं या पंचायती राज चुनाव में, नगरपालिका चुनाव में, कोपरेटिव चुनाव में तीसरी संतान वाला जो आपने राइडर लगा रखा है, वह राइडर हटाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः डा. ऋतु बनावत।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): साहब, सरकार जवाब दे रही है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): सरकार जवाब देना चाहती है। संसदीय कार्यमंत्री जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्षः डा. ऋतु बनावत। इस पर बोला थोड़े ही जाता है। उत्तर देते हैं क्या?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं, उत्तर नहीं, एक निवेदन कर रहा हूं। माननीय सदस्य का विषय बड़ा गंभीर है और यह विषय किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं रखता है, यह विषय आमजन से सम्बन्ध रखता है। राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में गंभीर भी है और नौकरी में प्रमोशन के विषय में यह भी राइडर था, उसको राजस्थान सरकार ने हटाया है। इसीलिए आपने जो विषय रखा है, उसकी गंभीरता को देखते हुए, यह परिपाटी नहीं है, अध्यक्ष महोदय ने विशेष परिस्थिति में जवाब देने की अनुमति दी है, सरकार इसका संज्ञान लेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः डा. ऋतु बनावत।

Ans/rtm 12.10 1h 25.02.2025

श्री यूनुस खान (डीडवाना): इन्होंने लड़कियों की बात कही। माननीय अध्यक्ष महोदय लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है, लड़की शब्द एक्सपंज कराया जाए। लड़की शब्द एक्सपंज कराया जाए।

श्री अध्यक्षः संज्ञान में आ गया।

बयाना में निर्माणाधीन जी.एस.एस.के निर्माण में विलम्ब

डा. ऋतु बनावत (बयाना): अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र बयाना उपखण्ड में 50 हजार से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ता हैं और समय-समय पर बिजली तंत्र विकसित करने के लिए जी.एस.एस. की घोषणा वहां पर की गई। पिछली सरकार के समय जिन जी.एस.एस. की घोषणा हुई उनका धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। उनकी सरकार की प्रायोरिटी भी नहीं थी कि इस तरह का कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली के क्षेत्र में डवलप

किया जाए। 132 केवी का जी.एस.एस. हमारे यहां रूदावल में घोषित किया उसका काम आज दिन तक भी पूरा नहीं हुआ है, लाइनें नहीं डली है। मेरा लगातार सम्बन्धित क्षेत्र में अधिकारियों से आग्रह भी रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि 132 का जी.एस.एस. है उसका काम पूरा कराया जाए, जिससे हमारे किसानों को ट्रिपिंग में आ रही समस्या से राहत मिल सके। साथ ही 33/11 के जी.एस.एस. जो निम्बेहरा में है उसमें भी अभी तक लाइन का काम पूरा नहीं हुआ। कपूरा मलुका में जो जी.एस.एस. है वह पूरी तरह बनकर तैयार है लेकिन उसको भी चालू नहीं किया गया है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि इन जी.एस.एस. का काम पूरा हो जाए तो क्षेत्र की जनता को बिजली के क्षेत्र में बहुत सहूलियत मिलेगी।

रामपुरा का एक जी.एस.एस. मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो डांग इलाक़े में है, बिजली तंत्र को विकसित करने के लिए बनाया जा रहा है उसमें जी.एस.एस.की बिल्डिंग तैयार हो गई है, लेकिन वन विभाग, बिजली विभाग के गतिरोध के कारण वहां लाइन नहीं ड़ल पा रही है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस गतिरोध को खतम किया जाए ताकि डांग क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा सके। इन जी.एस.एस. का काम पूरा होने से मेरे क्षेत्र में निर्बाध आपूर्ति होने से लोगों को सहूलियत मिलेगी। बिजली की वजह से हमारे यहां टेम्परेचर भी हमेशा हाई रहता है, सर्दियों का टाइम हो तो सर्दी के कारण किसानों को पानी देने में समस्या आती है, गर्मियों के समय तापमान हाई रहने की वजह से बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती है। मेरा निवेदन है कि बिजली तंत्र को ढंग से विकसित किया जाए। जनता में इस वजह से रोष भी व्याप्त रहता है। विधान सभा क्षेत्र में बिजली को लेकर बहुत संकट है। मैं यही निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निदान किया जाए1

श्री अध्यक्षः डॉ. प्रियंका चौधरी।

बाड़मेर के कुडला में स्थापित सीवरेट ट्रीटमेंट प्लांट के स्थान पर नये प्लांट की स्थापना

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मुझे स्थगन प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का अवसर मुझे दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं बाड़मेर विधान सभा से आती हूं जहां पिछले 15 साल से कांग्रेस के विधायक रहे। पिछले 15 साल से कांग्रेस का ही नगर परिषद का बोर्ड रहा। कांग्रेस के ही विधायक ने बाड़मेर नगर परिषद पर सबसे भ्रष्ट नगर परिषद होने का आरोप इसी सदन में लगाया। कांग्रेस के ही पार्षदों ने इसी कार्यकाल में 100 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उसी का हमारे सामने यह एक उदाहरण है कि नगर परिषद द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बाड़मेर में कुडला गांव में है, जो बाड़मेर शहर से पांच किलोमीटर की दूरी पर है, उससे जो भयानक स्थिति उत्पन्न हुई है तथा बाड़मेर की जनता को जो परेशानी हो रही है यह कांग्रेस के भ्रष्टाचार का ही एक उदाहरण हमारे सामने है।

2015 में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हुई थी। रूडिप ने बनाया था और पांच साल तक उन्होंने ही इसका मेंटीनेंस और ऑपरेशन का काम किया। 2021 में नगर परिषद बाड़मेर

को सुपुर्द किया गया। 2021 से यह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद पडा है। यह प्लांट बना था तो यह जल भराव के क्षेत्र में बना था। बारिश की स्थिति में यह स्थिति हो जाती है कि सीवरेज का पूरा पानी और बारिश का पूरा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। चूंकि ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा तो साफ पानी की तो हम सोच ही नहीं सकते। गंदा पानी, बदबूदार पानी, केमिकल युक्त पानी वहां के आस-पास के क्षेत्र में, 50 हैक्टेयर की जमीन पर वह लोग वहां खेती कर रहे हैं, जीरा, सरसों उगा रहे हैं और वही सब्जी वहां मार्केट में बिकने जा रही है, वहां मच्छर उत्पन्न हो गए, दुनिया भर की बीमारियां हो गई। मेरा सरकार से निवेदन है कि आने वाले समय में रूडिप फेज-4 में इसके उन्नयन की भी प्रस्तावना की गई है लेकिन आज के दिन भी यह प्लांट काम नहीं कर रहा है, तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन रहेगा कि एक नये सिरे से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की डीपीआर तैयार करवाई जाए और सिक्वेंशियल बैच रियक्टर तकनीक के तहत एक नये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करवाया जाए ताकि बाड़मेर की जनता को सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

श्री अध्यक्षः 295, श्री पूसाराम गोदारा। (अनुपस्थित) श्री राजेन्द्र।

महवा में नशा मुक्ति अभियान चला कर मादक पदार्थों पर रोक

श्री राजेन्द्र (महवा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत नशे की गिरफ्त से युवा पीढ़ी को बचाने हेतु विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के तहत मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र महवा सहित सम्पूर्ण राजस्थान और देश की गंभीर समस्या के बारे में ले जाना चाहता हूं और वह है युवा पीढ़ी का नशे की तरफ पलायन करना।

महोदय युवाओं और नशे के आदी लोगों का दूध, दही, घी जैसी आदि चीजों से ध्यान हट गया है और शराब, गांजा, भांग, अफीम, स्मैक, चरस, नशीली दवाएं और विभिन्न प्रकार के नशों का उपयोग शौक से करते हैं, जिससे स्वयं तथा उसके परिवार के साथ सामाजिक जीवन में बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। नशे के आदी लोगों को जब नशा करने के लिए पैसे नहीं मिलते तो वे लोग चोरी, डकैती, लूट-पाट, और बच्चों, बुज़ुर्गों, महिलाओं तथा राहगीरों के साथ अनैतिक व्यवहार करते हैं और कई बार तो मरने-मारने की स्थिति पर आ जाते है। जब यह स्थिति ज्यादा खराब होने लगती है तो मां-बाप अपनी युवा संतान को अपनी आंखों के सामने खोता हुआ देख असहाय होने लगते हैं। नाबालिग बच्चे अनाथ हो रहे हैं, बहन बेटियां कम उम्र में विधवा हो रही हैं। समाज में भय का वातावरण बन रहा है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर माननीय आबकारी मंत्री जी से निवेदन है कि महवा विधानसभा क्षेत्र में नशे की जड़ों को फैलाने वाले अड्डों, अवैध रूप से गांव ढाणियों और गलियों तथा घरों में मिलने वाले शराब, अफीम स्मैक चरस भाँग आदि..

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय, धीरे बोले।

श्री राजेन्द्र (महवा): जैसी मादक पदार्थों का अभियान चला कर और औचक निरीक्षण करवा कर वहां हो रही अवैध नशाखोरी को बंद करवाने और युवा पीढ़ी को बचाने और नशामुक्त करवाने के लिए और महवा में एक नशामुक्ति केंद्र खुलवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर में अमृत 2.0 योजना के तहत पेयजल व्यवस्था

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाडा शहर की बिखरी आबादी को लाभान्वित करने हेतु बिलाडा शहर की पुर्नगठित योजना अमृत 2.0 के अन्तर्गत राशि रुपये 1200.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 06.02.2023 को जारी की गई हैं। तत्पश्चात योजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू) राजस्थान जयपुर तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 7564-71 दिनांक 10.09.2024 को 1131.13 लाख की राशि जारी की जा चुकी हैं। वर्तमान में उक्त योजना निविदा प्रक्रियाधीन में हैं। इसके अतिरिक्त बजट सीमाओं की वजह से बिलाडा शहर की शेष बचे लगभग 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बसी आबादी को लाभान्वित करने हेतु लगभग 15 किलोमीटर राइंजिग मैन पाइप लाइन 50 किलोमीटर वितरण पाइप लाइन एवं 2 उच्च जलाशय की ओर आवश्यकता रहेगी जिसकी अनुमानित राशि रुपये 20 करोड़ रहेगी।

इसके साथ ही पीपाड शहर की बिखरी आबादी को लाभान्वित करने हेतु पीपाड शहर की पुनर्गठित योजना अमृत 2.0 के अन्तर्गत राशि रुपये 810. 00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 06.02.2023 को जारी की गई हैं। तत्पश्चात योजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू) राजस्थान जयपुर द्वारा 30.08.2024 को 773.18 लाख की राशि जारी की जा चुकी है। वर्तमान में उक्त योजना निविदा प्रक्रियाधीन में है। इसके अतिरिक्त बजट सीमाओं की वजह से पीपाड शहर की शेष बचे लगभग 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बसी आबादी को लाभान्वित करने हेतु लगभग 10 किलोमीटर राइंजिग मैन पाइप लाइन 40 किलोमीटर वितरण पाइप लाइन एवं 2 उच्च जलाशय की ओर आवश्यकता रहेगी जिसकी अनुमानित राशि रूपये 15 करोड़ रहेगी। धन्यवाद।

VPS-RTM-25.02.2025-12.20-1j

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मपाल।

प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव की पुन: शुरुआत

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि विगत सरकार ने कुलपति समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2023-24 के छात्र

संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी। समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार छात्र संघ चुनाव नवीन शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक है। छात्र संघ चुनावों के संबंध में उक्त तर्क पूर्णतया औचित्यहीन है।

महोदय, सदन के माध्यम से राज्य सरकार से मेरा अनुरोध है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व के विकास के लिए छात्र संघ चुनाव कराया जाना युवाओं के लिए नितान्त आवश्यक है। छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती हैं। आज राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व के साथ-साथ राज्य स्तर के अधिकतम नेतृत्वकर्ता छात्र संघ राजनीति से ही निकले हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में भी आज बड़ी संख्या में ऐसे सदस्य उपस्थित हैं जिन्होंने छात्र राजनीति के मंच से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है। छात्र संघ चुनाव वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का आधार स्तम्भ है, जिस पर आगामी राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा तय होगी। एक स्वाभाविक लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ चुनाव अपरिहार्य और अनिवार्य है।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि पारदर्शी और नियमित छात्र संघ चुनाव प्रारम्भ करवाये जाए। आपका यह निर्णय राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के नीति निर्माण में सहयोग प्रदान करेगा। धन्यवाद ।

श्री अध्यक्षः श्री अंशुमान सिंह भाटी।

कोलायत में डी एम एफ टी में प्राप्त राजस्व का खनन प्रभावित क्षेत्रों में ही उपयोग

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से डीएमएफटी में प्राप्त राजस्व राशि का उपयोग आनुपातिक रूप से खनन से प्रभावित क्षेत्रों में किये जाने के संबंध में निवेदन है कि भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा 15-01-2024 को डीएमएफटी के नए नियम लागू करने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। डीएमएफटी निधि का न्यूनतम 70 प्रतिशत राशि खदानों की सीमा से 15 किलोमीटर तक खनन कार्य से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों को जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के प्रवेश क्षेत्र की सीमा से अधिकतम 25 किलोमीटर दूर है उनमें डीएमएफटी निधि का अधिकतम 30 प्रतिशत राशि दिए जाने का प्रावधान था।

इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा, स्वच्छता आदि में कुल राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत व्यय करना अनिवार्य किया गया था तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे सड़क, सिंचाई आदि में अधिकतम 30 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाना था।

कोलायत बीकानेर जिले का खनिज कैंद्र है, जहां खनन के माध्यम से सरकार को सर्वाधिक सालाना करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। वर्ष 2021 से अक्टूबर, 2023 तक कुल प्राप्त डीएमएफटी लगभग 53 करोड़ में 62.88 प्रतिशत योगदान कोलायत विधानसभा

क्षेत्र का था, उसके बावजूद कोलायत विधान सभा क्षेत्र को मात्र डीएमएफटी का 31.6 प्रतिशत की राशि ही दी गई। डीएमएफटी उन क्षेत्रों को दे दिया जाता है जहां पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी खनन कार्य हुआ ही नहीं।

मेरा अनुरोध है कि जिन क्षेत्रों में सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं तथा जिन ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो दिन-रात खनन से होने वाले धुएं, प्रदूषण और शोर-शराबे के अन्दर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन प्रभावित लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए डीएमएफटी राशि का अधिकतम उपयोग किया जाए। डीएमएफटी फंड का वितरण प्रभावित क्षेत्रों के संबंधित योगदान के अनुपात में किया जाए।

घोषणा

मांगों पर चर्चा के 48 घंटे पूर्व कटौती प्रस्ताव की प्रस्तुति

श्री अध्यक्षः मैं अगला नाम पुकारूं उसके पहले एक सूचना है कि सबके पास सुबह बुलेटिन पहुंच गया है, जिसमें 28 तारीख से डिमांड्स पर चर्चा होगी। चूंकि, हमेशा 48 घंटे पहले कटमोशन देना होता है तो 26 की कल छुट्टी है। कोशिश करें कि आज ही देकर जाएं हालांकि, कल एक व्यक्ति यहां पर रहेगा और वह एक बजे तक आपके कटमोशन रिसीव करेगा ताकि ऐसा नहीं हो कि फिर अपन यह कहे कि सूचना नहीं हुई। बाकी तो सब जगह कटौती प्रस्ताव डिमांड के 48 घंटे पहले नीचे कमरे में देने होते हैं।

श्री मनोज कुमार।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सादुलपुर में कतिपय मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर का क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र है एवं ग्रामीण परिवेश की संख्या ज्यादा है इसलिए क्षेत्र के आवागमन के लिए सुदृढ़ सड़कों का होना बहुत जरूरी है एवं पंचायतों का विस्तृत क्षेत्र है। एक ग्राम पंचायत में 4 से 7 गांव शामिल हैं, जिससे पंचायतों को जोड़ना भी आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत सरकार से यह मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र को निम्नानुसार स्वीकृत मिसिंग लिंक में प्रदान करने का श्रम करें:-

1. हिसार-राजगढ़ के राजगढ़ मध्य एन० एच० 52 से लुटाणा अमिचन्द तक, अनुमानित 1.5 किलोमीटर।
2. ग्वालिसर से झुंपा (हरियाणा बॉर्डर) तक अनुमानित 02 किलोमीटर।
3. बीराण से हरियाणा बॉर्डर बहल तक अनुमानित 02 किलोमीटर।
4. चुबकीगढ़ से रेलवे स्टेशन तक अनुमानित 1.5 किलोमीटर।
5. राऊ टिब्बा से राजकीय विद्यालय तक अनुमानित 1.5 किलोमीटर।
6. बालाण से हरियाणा बॉर्डर बहल तक अनुमानित 01 किलोमीटर।

7. रामपुरा से हमीरवास सड़क के मध्य से किरतान तक अनुमानित 02 किलोमीटर।

8. राधा छोटी से जाटुवास तक अनुमानित 4 किलोमीटर।

9. कांध्रराण से जाटुवास तक अनुमानित 4 किलोमीटर।

10. ढाणी मौजी से. दन्देऊ मोहनसिंह तक (वाया नीम का बास) अनुमानित 4 किलोमीटर।

11. रड़वा से लम्बोर छोटी तक अनुमानित 4 किलोमीटर।

12. हरपालू कुबड़ी से लम्बोर छोटी तक अनुमानित 4 किलोमीटर।

13. कांधराण से कालरी तक अनुमानित 4.5 किलोमीटर।

14. भगेला से न्यांगल छोटी तक अनुमानित 5 किलोमीटर।

15. चांदगोठी से सुलखनियां बड़ा वाया अम्बेडकर भवन चांदगोठी तक अनुमानित 5 किलोमीटर।

16. कांजण बास से चैनपुरा बडा तक अनुमानित 5 किलोमीटर।

17. बालाण से गुगलंवा तक अनुमानित 6 किलोमीटर।

18. समरपुरा से रावतसर कुंजला रोड़ तक अनुमानित 4 किलोमीटर।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के मार्फत सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर मे उक्त सडकों का निर्माण कार्य अतिशीघ्र करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चन्द वर्मा।

बगरू में लैण्ड पूलिंग योजना से प्रभावित काश्तकारों को राहत

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से लैण्ड पूलिंग योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र बगरू के ग्राम तेजावाला, अचरावाला, अभयपुरा में प्रभावित काश्तकारों की मांगों के संबंध में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बगरू के ग्राम तेजावाला, अचरावाला, अभयपुरा में प्रदेश सरकार द्वारा लैण्ड पूलिंग योजना के अन्तर्गत प्रभावित काश्तकारों की निम्नांकित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है:-

1. लैण्ड पूलिंग योजना में किसानों से लिए जाने वाला विकास शुल्क, लीज मनी पूर्णतया माफ हो।

2. उक्त योजना के प्रभावित भूमि धारकों को सामूहिक पट्टा नहीं देकर जमाबंदी के अनुसार अलग-अलग पट्टे दिये जाए।

3. खातेदारों को कम से कम 10 प्रतिशत भूमि व्यावसायिक उपयोग के लिए दी जाए।

4. प्रभावित खातेदारों को ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर मौके पर ही पट्टे वितरित किये जाए।

5. उक्त योजना से प्रभावित खातेदारों को मकान, कुएं, बाड़ा सहित अन्य निर्माण का शत प्रतिशत मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री अरूण चौधरी।

पचपदरा में सुचारु पेयजल आपूर्ति हेतु कार्ययोजना

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र जैसे बालोतरा शहर, जसोल, पचपदरा, सिणली, कितपाला, कतवारी, आकड़ली, हेमपुरा, भांडियावास, उमरलाई, पारलू, कनाना, खारवा, कांकराला, सरुपरा, रणिया देशपुरा, ग्वालनाडा, डोली, थोब, जास्ती रोड़वा, बुड़ीवाड़ा, जागसा, किटनोद, आसोतरा, मूल जी ढाणी, बादू का बाड़ा, सरवड़ी, कुड़ी आदि कई गांवों में स्थानीय कार्मिकों को पानी के डिस्ट्रीब्यूट करने एवं उम्मेद सागर घवा परियोजना पर L&T कम्पनी के खराब वितरण प्रणाली तथा इस पेयजल लाइन पर लगे प्राइवेट कम्पनी के कर्मचारियों के द्वारा एवं पोकरण फूलसण्ड योजना के बार-बार पाइप लीकेज होने के कारण कई स्थानों पर 15 से 20 दिन में पानी आता है। कई स्थानों पर दोनों योजना के चालू हो जाने के उपरान्त भी आज दिन तक पानी नहीं पहुंचा है। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में कर्मचारियों के पद भी रिक्त होने से भी काफी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

अतः नियम 295 के तहत मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में पानी की सुचारु आपूर्ति करने हेतु आपके मार्फत निवेदन करता हूं कि समस्या का तुरन्त निस्तारण हेतु आवश्यक कदम उठाएं एवं उम्मेद सागर घवा परियोजना के समानान्तर एक नई पानी की पाइप लाइन तथा नर्मदा नगर का पानी सिवाणा एवं पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में लाने हेतु नई कार्य योजना बनाने का निर्देश दिलाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

SSY/RTM/25.02.2025/12.30/1k

कोटा में कोचिंग छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्या को रोकने हेतु प्रभावी योजना

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि प्रदेश के कोटा शहर में कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के बीच मानसिक दबाव और तनाव के मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके परिणामस्वरूप, आए दिन कोटा में कई छात्र व छात्राओं ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। यह एक गम्भीर और चिंताजनक मामला है, जो राज्य सरकार की शिक्षा नीति और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।

कोटा शहर कोचिंग संस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। कोटा में हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें मानसिक दबाव, प्रतियोगिता का अत्यधिक बोझ, और व्यक्तिगत समस्याओं से जूझना पड़ता है। कई

आत्महत्या के मामलों ने समाज और सरकार को गंभीर चिंतन में डाल दिया है। छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्या को रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाओं का विस्तार, कार्यशालाएं, पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए। सभी बच्चे संपन्न परिवार से नहीं होते है कुछ बच्चे गरीब परिवार से आते है। संस्थानों द्वारा फीस अधिक लेने से गरीब परिवार के बच्चे मानसिक दबाव महसूस करते है। भविष्य में कोई छात्र आत्महत्या जैसा कदम न उठाए इसके लिए कोई ठोस नीति बनाई जानी चाहिए और उसका कठोरता से पालन कराया जाना चाहिए। आपसे निवेदन है कि कोटा शहर में कोचिंग करने वालें छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्या को रोकने हेतु प्रभावी योजना बनाए जाने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह सांखला।

जवाई परियोजना की डी.पी.आर. में आसीन्द के खारी बाँध को जोड़ा जाना

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द पिछले 40-50 वर्षों से पानी नहीं होने से. अकाल से ग्रस्त है। यहां के हजारों किसान व युवा रोजगार हेतु अन्य राज्यों में पलायन कर रहे है व खेती की उपजाऊ जमीन भी पानी के अभाव में बंजर हो रही है।

राजस्थान सरकार वर्तमान में ERCP योजना की तर्ज पर माही, सोम, कमला नदी जोडने की जवाई परियोजना की डीपीआर बनायी जा रही है। जिसमें भीलवाड़ा जिले का मेजा डेम को भी सम्मिलित किया गया है। इसी क्रम में मेरे क्षेत्र की अकाल की गम्भीर समस्या को देखते हुए उक्त परियोजना में मेजा डेम से खारी डेम को भी सम्मिलित किया जावे। जिससे मेरे विधानसभा क्षेत्र आसीन्द के 200 किलोमीटर परिधि में किसानो को सिचाई का पानी मिलेगा। क्षेत्र में किसान व युवाओ का पलायन रुकेगा तथा रोजगार के नये आयाम स्थापित होंगे।

अत: (जवाई परियोजना) की डीपीआर में आसीन्द के खारी डेम को जोडने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री हंसराज मीणा।

सपोटरा में वन भूमि एवं पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का सीमाकंन

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों को "ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें पहचाने गये पर्यावरणीय संसाधन हैं जिनका मूल्य अतुलनीय है, और जिनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इनमें भू-दृश्य, वन्यजीव, जैव विविधता, ऐतिहासिक और प्राकृतिक मूल्य है।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार देश के संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के चारों ओर न्यूनतम एक किलोमीटर का पारिस्थितिकी तंत्र

संवेदनशील घोषित किया गया है। जिसमें कोई भी स्थायी ढांचा (स्थायी निर्माण कार्य), एवं खनन कार्य प्रतिबंधित है।

करौली जिले का अधिकांश भू-भाग विशेष रूप से विधान सभा क्षेत्र- सपोटरा का सम्पूर्ण भाग डांग क्षेत्र है। यहां लोगों के जीविकोपार्जन के लिए कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त खनन यहां का मुख्य व्यवसाय है।

यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि विधान सभा क्षेत्र सपोटरा का अधिकांश भाग वन-भूमि है जो रणथम्भौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित है, परन्तु वन भूमि एवं पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का सीमांकन नहीं होने के कारण वन विभाग द्वारा सम्पूर्ण भू-भाग को स्वयं के अधिकार क्षेत्र में बताया जाकर आबादी क्षेत्र में आवश्यक संरचनाओं के निर्माण एवं पहाड़ी क्षेत्र में खनन कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाता है जिससे वन विभाग के अधिकारियों एवं आमजन के बीच आये दिन टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है।

मेरा सदन के माध्यम से लोकहित के इस मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि वन भूमि के साथ ही पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का निर्धारण किया जाकर सीमांकन कराया जावे, जिससे क्षेत्र में खनन व्यवसाय में प्रगति होकर लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो।

श्री अध्यक्षः श्री हरिमोहन शर्मा। (अनुपस्थित)

श्री मोतीराम। (अनुपस्थित)

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर। (अनुपस्थित)

श्री उदयलाल भडाणा।

भीलवाड़ा में गाडरी समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्या

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि भीलवाडा में गाडरी समाज के लोगो के जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने में आ रही समस्या के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा गाडरी समाज को MBC में शामिल किये जाने हेतु गजट नोटिफिकेशन संख्या 83573, दिनांक 28.11.2012 द्वारा आरक्षण दिया गया था। बाद में वर्ष 2013 में OBC लिस्ट में पूर्विया, धनगर के साथ (गाडरी) जाति को भी उनके साथ जोड़ दिया गया। जिससे यह साबित होता है कि मूल जाति गाडरी हैं और धनगर व पूर्विया इस जाति के सरनेम हैं। इस कारण उक्त समाज को पूर्विया, धनगर, (गाडरी) का जाति प्रमाण पत्र दिया जाता हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन हैं कि वर्ष 2013 में OBC लिस्ट में पूर्विया, धनगर के साथ (गाडरी) जाति अंकित हैं जो मूल जाति होने के कारण गाडरी का कोष्ठक () हटाये जाने हेतु संबंधित को निदेशित करे जिससे MBC की सूची क्रमांक 5 पर गाडरी अंकित होने से गडरिया, (गाडरी) गायरी के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके एवं जनता को आरक्षण का लाभ मिल सके। साथ ही राजस्थान सरकार की जाति सुची

क्रम संख्या 81 पर अंकित जाति कोतवाल/कटवाल (KOTWAL/KATWAL) है और सभी समाज बधुओं का उपनाम कटवाल है, इसको कटवाल ही रखा जाये।

श्री अध्यक्षः पर्ची। श्री गोविन्द प्रसाद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जल संरक्षण हेतु नीति निर्माण

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज देश व प्रदेश में जल की महती आवश्यकता है। मान्यवर, आज जीने का सबसे बड़ा स्रोत पानी और हवा है। हम महानगरों में जाते हैं तो प्रदूषण हमें मिलता है। प्रदूषण के कारण हम खींच-खींचकर सांस ले पाते हैं। प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। कहने-सुनने से नहीं, हवा में जहर दिन-ब-दिन घुलता जा रहा है। लोग बिना वजह पानी की बरबादी करते जा रहे हैं। बिना वजह आप पानी का खात्मा करते जा रहे हैं, जो कि शरीर के लिए अति जरूरी है।

आज हमारे वैज्ञानिकों को डर है कि कहीं जल के लिए विश्व युद्ध ना हो जाये। अगर इंसान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करता तो यह विपदा आती ही नहीं। आज लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। यदि पेड़ों को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं तो पेड़ों की कटाई कम हो जाती तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता।

समुद्र और बड़े जलाशयों में लोग गंदगी फैला रहे हैं जिससे पानी गंदा हो रहा है तथा अनेक तरह की गंदगी हमें मिलती है। गंदे पानी से बीमारियां फैल रही हैं। आप पानी को बचायेंगे तो पानी आपको बचायेगा। पानी बचाने के लिए पूरे विश्व में सभी को आगे आना होगा। इस प्रकार यदि कोयला, डीजल, पेट्रोल की यूं ही खपत होती रही और जनसंख्या तेजी से बढ़ती रही तो फिर क्या होगा, इस पर हम सबको मिलकर ध्यान देना होगा। जल को हमें बचाना होगा। जल ही जीवन है। जल को बचायें तो बड़ी अच्छी बात होगी। जय हिन्द। जय भारत।

spp/rtm/25.02.2025/12.40/1l

श्री अध्यक्षः डॉ. सुभाष गर्ग।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः इस पर जवाब होता नहीं है, आप बैठिये।

भरतपुर शहर में CFCD परियोजना के अन्तर्गत नालियों के निर्माण का अभाव

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया। मैं भरतपुर शहर के CFCD परियोजना के अन्तर्गत, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने भरतपुर की 50 वर्षों की जल भराव की जो समस्या थी,

उससे निजात दिलाने के लिये 362 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी योजना दी थी, जिसका कार्य शुरू हो चुका था। फर्स्ट फेज का काम चल रहा है और उसमें लगभग 280 किलोमीटर की नालियों का निर्माण होना था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी तक एक किलोमीटर नाली का निर्माण नहीं हुआ है। पक्की ड्रेन बन रही है, कच्ची ड्रेन पर भी काम चल रहा है। लेकिन जो प्रमुख समस्या भरतपुर के नागरिकों की है, जिसकी वजह से बहुत सारे हैल्थ हजार्ड होते हैं। स्वास्थ्य की प्रॉब्लम क्रियेट होती है, उसको दूर करने के लिये इन नालियों का निर्माण बहुत जरूरी था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि पूरा शहर, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा इस बात के लिये, कि उन्होंने स्मार्ट सिटी में इसको लिया है। स्मार्ट सिटी की पहले भी घोषणा की गयी थी, अब भी लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी के मायने क्या हैं? जब तक किसी भी शहर से पानी भराव और जलभराव की समस्या को मुक्त नहीं किया जाएगा, तो स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। भरतपुर शहर की वर्तमान आबादी करीब पांच लाख से अधिक है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है, नगर निगम के अधिकारी, एक्स.ईएन. और दूसरे अभियंता करते क्या हैं कि 280 किलोमीटर की नालियों के प्रावधान में से एक किलोमीटर भी नाली का निर्माण अभी नहीं हो पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से कहना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी भी यहां बिराजमान हैं, कि एक बार मीटिंग करें CFCD के ऊपर, और जरूरत पड़े तो मुझको भी आप बुला लें कि किस तरह से किस मिलीभगत से यह काम नहीं किया जा रहा है। इसकी भी आप जांच करायें। माननीय मुख्य मंत्रीजी भरतपुर शहर के रहने वाले हैं और मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि भरतपुर जिले के व्यक्ति को मुख्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर के नगर निगम के अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

आज भी आप देखेंगे, आप पूरा विजिट कर लें, करीब तीन-चार किलोमीटर का एरिये में पानी भरा हुआ है। कॉलोनियों के अन्दर जाने के रास्ते भी नहीं हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर ध्यान दिया जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

पश्चिमी राजस्थान के प्रसिद्ध मन्दिर ख्याला मठ एवं गरीबनाथ जी के मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं अन्य व्यवस्थाएं

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। आपने मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कई सारे धर्म के बड़े केन्द्र हैं, जिनमें से ख्याला मठ अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह रखता है। सीमांत क्षेत्र पर आस्था का एक बहुत बड़ा केन्द्र है। भील समाज से आने वाले ख्याल जी ने उस समय जमीन उपहारस्वरूप रताकोट से आये महाराज सहजनाथ जी को दी थी और जिसके फलस्वरूप ख्याला मठ स्थापित हुआ। पश्चिमी राजस्थान का यह बहुत बड़ा आस्था का केन्द्र है। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से, कल शिवरात्रि भी है, आप बड़ी

घोषणा आस्था का बहुत बड़ा केन्द्र रखने वाले ऐसे जो मठ हैं, उनके लिये आप कोई बड़ी घोषणा करें। साथ ही साथ, मैं निवेदन करना चाहूंगा, शिव विधान सभा क्षेत्र, जहां से मैं आता हूं, वह बाबा गरीब नाथ जी की नगरी है। बाबा गरीब नाथ जी का अपना एक बहुत बड़ा चमत्कार रहा है। 700-800 साल पहले जब महाराज जी पधारे थे तो उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप यह तमाम चीजें हो पायी हैं। मेरा निवेदन है कि नागरदा गांव जो उन्होंने बसाया, साथ ही साथ शिव में जहां पर समाधि ली, यह तमाम जो क्षेत्र हैं, वो बहुत बड़े आस्था के केन्द्र हैं। न सिर्फ आस्था के केन्द्र बल्कि जब वह पुरानी प्रणाली थी, तो उस समय पंच-पंचायत भी हुआ करती थी, वह इन मठों में ही होती थी। जब सुकाल होता था तो वहां पर धन-धान्य इकट्ठा करके अकाल के समय में वहां पर जीवन-यापन के लिये दिया जाता था। साथ ही साथ, जब भी कभी कोई युद्ध की घटना घटित होती थी या कभी गाय पर बात आती थी तो यह जो मठाधीश और संत महात्मा थे, तो लड़ने के लिये आगे आया करते थे। इनका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है।(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आज हमारे बीच में पोकरण से आने वाले विधायक भी हैं, अलवर से आने वाले विधायक भी हैं। बालकनाथ जी हैं, बालमुकन्दाचार्य जी हैं, मैं इन सभी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक प्राइवेट बिल लायें और तमाम जो मठ हैं, उनके बारे में एक विशेष आप अपील इस सदन के माध्यम से करें। इसके साथ ही शिव और नागरदा में जो हमारा मठ है, बाबा गरीब नाथ जी की जो यह धरती हे, इसके लिये गवर्नमेंट, विशेषकर एक पेनोरमा बनायें और इसके अलावा भी आप कुछ कर सकें तो आप जरूर करायें। साथ ही साथ, मानसरोवर जो तालाब है, उसके लिये भी करवायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही चंचल प्रयाग मठ है, हमारे बाड़मेर का एक बहुत बड़ा मठ है जिससे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मेरा निवेदन है कि अकाल का दौर हो, चाहे बीमारियों का दौर हो, चाहे कोई पशुओं में बीमारी का दौर हो, इनके आशीर्वाद की बदौलत वह तमाम चीजें सही हो पायी हैं। लोक आस्था से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है, निवेदन है कि इस बारे में सोचा जाये। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्षः बैठिये, हो गया आपका। श्री प्रताप लाल, शुरू करिये आप।

गोगुन्दा के धोलिया जी पर्वत का पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका आभार। राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित गोगुन्दा जिला उदयपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर-पश्चिम के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित है। गोगुन्दा उपखण्ड तहसील पंचायत समिति मुख्यालय है और ऐतिहासिक प्राप्त श्री वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की राजतिलक स्थली भी है और मुख्य गांव गोगुन्दा से दक्षिण की ओर तीन-चार किलोमीटर पर गांव राणा बसा हुआ है और पास में ही धोलिया जी का एक बहुत बड़ा पहाड़ है और इस पहाड़ की ऊँचाई लगभग 1180 किलोमीटर है। धोलिया जी को एक धार्मिक स्थल के रूप में भी माना

जाता है और धोलिया जी के शिखर पर भैंरूजी लोक देवता जी वहां बिराजमान है, लोगों की मान्यता भी यह पूरी करते हैं। ऐतिहासिक रूप से भी धोलिया जी बहुत प्रसिद्ध हैं एवं मुगलों से संघर्ष के समय महाराणा प्रताप ने अपना काफी समय इसी क्षेत्र में गुजारा था। धोलिया जी के शिखर से 35 से 40 किलोमीटर की परिधि में आप देख सकते हैं और मेरा निवेदन रहेगा कि इस स्थान को पर्यटन के रूप में विकसित किया जावे। हमारी पर्यटन मंत्रीजी, दिया कुमारी जी भी यहीं बिराजमान हैं तो घोषणा हो जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग। कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 10)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2025 को मध्याह्न पश्चात् 03.30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2025 से बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2025	1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2024-25 का उपस्थापन 2. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2024-25 का मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान, पारण एवं तत्सम्बन्धी विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2025 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण 3. आय व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शनिवार, दिनांक 01 मार्च 2025 रविवार, दिनांक 02 मार्च 2025	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 03 मार्च 2025 मंगलवार, दिनांक 04 मार्च 2025 बुधवार, दिनांक 05 मार्च 2025 गुरुवार, दिनांक 06 मार्च 2025 शुक्रवार, दिनांक 07 मार्च 2025	आय व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शनिवार, दिनांक 08 मार्च 2025	बैठक नहीं होगी

रविवार, दिनांक 09 मार्च 2025	
सोमवार, दिनांक 10 मार्च 2025 मंगलवार, दिनांक 11 मार्च 2025	आय व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(आय व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 11 मार्च 2025 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेगी)

बुधवार, दिनांक 12 मार्च 2025	1. राजस्थान वित्त विधेयक, 2025 एवं 2. राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025 - पर विचार एवं पारण

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री कन्हैया लाल।

jyg/Rtm/25.02.25/12.50/1m

समिति प्रतिवेदन : प्रवर समिति

राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिका उपस्थापन।

डॉ. शिखा मील बराला। डॉ. शिखा मील बराला। (अनुपस्थित)।

विधायी कार्य।

भू-राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025

श्री हेमन्त मीणा।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आज 25 फरवरी है। कल महाशिवरात्रि का अपना बड़ा उत्सव भी है और एक तरह से सभी लोग अपने घरों पर जाना चाहेंगे, अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना चाहेंगे। इसलिए आज का भोजन अवकाश, मैं समझता हूं कि इसको कैंसिल किया जाये और इसके बाद विधिवत, केवल आज-आज के लिए, रोजाना करायेंगे भोजन, तो आज-आज भोजन अवकाश को निरस्त किया जाता है और इसके बाद अपने जो सदस्य हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि माननीय सचेतक ने सूची दी है, उस अनुसार अपन बहस में भाग लें। समय सीमित है, क्योंकि आज 6 बजे सदन की कार्यवाही समाप्त की जायेगी और जो उसमें से दो-तीन माननीय सदस्य रह भी जायेंगे उनको परसों की सूची में माननीय सचेतक जोड़ सकेंगे। 6 बजे बाद सदन की कार्यवाही कृपया न बढ़ायें क्योंकि सभी लोग जाना चाह रहे हैं।

आप कुछ कह रहे हैं?

अनुरोध एवं मांग

सदन की विधिवत् बैठक के अभाव में भी सदन के अमर्यादित उपयोग व उसमें आसन के प्रति अत्यन्त आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के अक्षम्य अपराध हेतु कार्यवाही की मांग

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय बड़ा गम्भीर है और बहुत चिंताजनक भी है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हम लोग विचारधाराओं से हमारा मतभेद हो सकता है, विचारधारा का हमारा डिफरेंस हो सकता है, विचारधाराओं में हमारा एक दूसरे के प्रति एक मत भी नहीं हो सकते हैं लेकिन यह राजस्थान की विधान सभा है, इसका बहुत बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है। नरोत्तम दास जी से लगाकर जो-जो भी माननीय अध्यक्ष इस कुर्सी पर विराजे हैं, यह विक्रमादित्य का आसन है और यह विक्रमादित्य का आसन सभी को एक ही नजर से देखता है और इस आसन पर जो विराजमान है वो हम सबके लिए बहुत ही सम्माननीय है।

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, हम पक्ष-विपक्ष के बीच मत-मतांतर, विशेष विरोधाभास, टकराव, नीतिगत निर्णयों में विरोध होना स्वाभाविक है। माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान

विधान सभा का जैसा मैंने अभी कहा, एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। आपका आसन हम सबके लिए बहुत आदर, मान और सम्मान का है। आसन पर विराजमान, माननीय अध्यक्षजी, आपने अपनी जो भी विचारधारा रही होगी, इस आसन ग्रहण करने के उपरांत आपने आपको उससे पूर्ण रूप से अलग कर दिया, आपकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। आपके लिए इस विधान सभा में विराजने वाले सभी माननीय सदस्य एक समान है। किसी भी राजनीतिक दल से आपने सम्बन्ध रखना बंद कर दिया, आपके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक समान है, दोनों ही आपकी दो आंखें हैं। आपने जो आचरण अपनाया और अपना दायित्व निभाया है, हम गौरवांवित हैं कि आपने निर्भीक, निष्पक्षता से नियमों के अनुसार इस विधान सभा का पिछले लम्बे समय से जब भी इस आसन को आपने ग्रहण किया है, संचालन कर रहे हैं। आपने पूरे नियमों के अनुसार सभी को एक नजर से देखा है और उलटा प्रतिपक्ष को यथासम्भव नियमानुसार संरक्षण देने का प्रयास भी किया है।

परंतु विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने कल विधान सभा में जो अपना आचरण किया, आपके प्रति, आसन के प्रति जिन शब्दों का, जिन निन्दनीय शब्दों का, जिन घोर गैर जिम्मेदाराना शब्दों का, जिस ओछी मानसिकता का, जो गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया, यहां खड़े होकर अपने कांग्रेसी साथियों को जिस तरह से सम्बोधित किया, जिसका आज राजस्थान के सभी बड़े-बड़े समाचार पत्रों ने, टीवी चैनलों ने, मीडिया ने, इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने और जितने भी हैं, उन्होंने जितनी भी निन्दा की, वो कम है, उसको देखते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। हम आपके प्रति आभारी हैं कि इन सबके बावजूद भी इतने कठोर निन्दनीय शब्दों का प्रयोग करने के बावजूद भी जब हमने आपसे प्रार्थना की तो आपने अपने चैंबर में, अपने कक्ष में सभी को सुना, आपके समक्ष क्षमा याचना की, तदोपरांत भी आपने बड़ा दिल रखा और आपने कहा कि जो गतिरोध है उस गतिरोध को तोड़ने के लिए आप लोग सहमत हो जायें, हम सहमत हुए, तय हुआ, उसी अनुसार यहां माननीय सदस्यों ने अपना-अपना वक्तव्य दिया लेकिन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने जो आपके चैंबर में तय हुआ, सबके सामने तय हुआ, उनके वरिष्ठ सदस्यों के सामने तय हुआ, आपके समक्ष मूल रूप से स्वीकार किया कि सदन में जाकर हम यह वक्तव्य देंगे, माफी मांगेंगे, खेद व्यक्त करेंगे, लेकिन यहां पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदाराना कृत्य किया, नट गये, अपने स्वयं के वचनों से विपरीत यहां पर आचरण किया, जिसकी हमारा सत्ता पक्ष पूर्ण रूप से घोर निन्दा करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की परम्परा के विपरीत आसन के प्रति ऐसे शब्दों के प्रयोग शायद कोई दुश्मन भी या छोटी मानसिकता के लोग भी या बच्चे भी या समाज का कोई भी वर्ग कभी नहीं करता है। जिन शब्दों का प्रयोग यहां किया गया है वो शब्द कभी भी इस आसन के प्रति जो प्रयोग किये गये हैं, राजस्थान के इतिहास से चाहे मीडिया के समक्ष रिकॉर्डेड है, सोशल मीडिया के समक्ष रिकॉर्डेड है, आज के सबसे प्रसिद्ध समाचार पत्र ने हूबहू उसका वर्णन किया है, वो क्षमा योग्य नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऐसे सदस्य भी निर्वाचित होकर आये हैं जो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं सत्ता पक्ष की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा जो भी, कभी भी हमने कोई भी कृत्य नहीं किया न हमारा कोई माननीय सदस्य और जो हमारे साथी सदस्य हैं, कोई नहीं करेंगे। आसन के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा आसन के प्रति जिम्मेदारी के साथ-साथ हमारी जो श्रद्धा और भावना है, वो जुड़ी हुई है और आपने तो पूर्ण निर्भीकता से, पूर्ण रूप से निष्पक्षता से और यहां तक कि प्रतिपक्ष को यथा सम्भव नियमानुसार संरक्षण देने का भी प्रयास किया और जिस माननीय सदस्य को विशेष संरक्षण देने का प्रयास किया, नियमों के अनुसार उस सदस्य का आचरण कल का रहा वो इतिहास में कांग्रेस के लिए काला दिवस के रूप में हमेशा-हमेशा के लिए याद किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में मैं आज आपसे, हमारे दल के परिवार की ओर से, सत्ता पक्ष इससे गम्भीर रूप से आहत हुआ है। हमारा पूरा परिवार, चाहे हमारा भाजपा परिवार है, सत्ता पक्ष का परिवार है, हमारे साथी लोग हैं या हमारे साथ सदन में बैठे सभी माननीय सदस्य हैं, बहुत ही आहत हुए हैं। हम मजबूर हैं, हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सदस्य के प्रति जो कठोर से कठोर कार्यवाही हो सके नियमों के अनुसार वो कार्यवाही करने के लिए भी हम नहीं चूकेंगे, हम नहीं झिझकेंगे, नियमानुसार देखेंगे और जो भी कार्यवाही होगी, वो विधान सभा में करेंगे, इस विधान सभा के इतिहास में जो काला दिवस लिखा गया है, उसके लिए जब कभी इतिहास पढ़ा जायेगा, हमारी उपस्थिति मानी जायेगी तो हमें भी या हमारी औलाद को भी शर्मिंदगी महसूस होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की ओर से कभी भी विनम्रता से कोई आचरण नहीं किया गया और कल के आचरण से इतना मैं अवश्य कहूंगा कि सत्ता पक्ष के जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो भी आहत हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो आहत नहीं हुए हैं और उन्होंने हमसे अलग से कहा है और आपके समक्ष कहा है, अपने ना पक्ष की लॉबी में जो कहा है उससे लगता है कि एक माननीय प्रदेश अध्यक्ष की वजह से कांग्रेस को इतनी राजस्थान में उसकी थू-थू हो रही है और उसको नीचा देखना पड़ रहा है।

MLS/RTM/25.02.2025/13:00/1n

हम आपसे पुरजोर प्रार्थना करते हैं, ऐसे शब्दों के लिए उनकी निन्दा करते हैं। चूंकि सदस्य जब बोले, तब विधान सभा की कार्यवाही चल नहीं रही थी, नहीं तो हम आपसे प्रार्थना करते कि इसको डिलीट किया जाये, परन्तु जो बोला गया है, वह इतिहास में रिकॉर्ड हो गया है। वह समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में, मीडिया में रिकॉर्ड हो गया है। वह कभी क्षमा योग्य नहीं है। सत्ता पक्ष के हम सभी लोग, हमारे सभी साथी लोग, आज इस विधान सभा में विराजमान सभी माननीय सदस्य आपको विश्वास दिलाते हैं कि उनकी ओछी मानसिकता का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जिस निर्भीकता, निष्पक्षता से इस

सदन को चलाने का प्रयास किया और चला रहे हैं, उसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं और ऐसे कृत्य की हम घोर निन्दा करते हैं। आपको पुनः विश्वास दिलाते हैं कि इस विक्रमादित्य के आसन को जिस तरह से आपने निभाया है, हमारी प्रार्थना है कि उसी तरह से निभाएं। हमारे अनेक सदस्यों की मांग है कि उनके ऊपर कठोर कार्यवाही की जाये, पर हम नियमानुसार देखकर ही इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे। पुनः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, जो अभी संसदीय मंत्री जी ने कहा है, उसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। आप भी कुछ कहेंगे? जल्दी कहें, फिर मैं भी कुछ कहूंगा।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अभी बात कही, चाहे सदन चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, लेकिन परिसर तो सदन का ही था और उस सदन के परिसर का दुरुपयोग किया गया। उसकी हम सब भर्त्सना करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जो पद है, वह आपके नाम से नहीं जाना जाता।

राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष की एक गरिमा है। उस गरिमा को कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह सत्ताधारी पक्ष का हो, चाहे ना पक्ष का हो, चाहे हम में से कोई भी पक्ष का हो, अगर इस तरीके के वाक्य बोलता है तो ऐसा आचरण विधान विरुद्ध है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाये, उतनी कम है। आज जो अखबारों में हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद में यह लगा कि यह राजस्थान की परम्परा नहीं रही है। राजस्थान में इस तरीके से आज तक किसी ने भी अध्यक्ष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है, इसलिए चाहे वह अन्ऑफिशियली की हो, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री तो नियमों की बात कर रहे हैं, लेकिन नियमों के बाहर भी, परम्पराओं से आप देखिये, इंग्लैंड का तो सदन ही पूरा परम्पराओं से चलता है, अगर परम्पराएं ही खराब हो गईं और हमारे संस्कार और संस्कृति ही खराब हो गयी तो यह हिन्दुस्तान और यह राजस्थान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आग्रह है, सरकार से भी आग्रह है कि सदन चलाने के लिए लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष हैं। आप डायलॉग जरूर रखें। डायलॉग के माध्यम से इस बात को निपटाने की कोशिश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने तो अपनी जुबान भी खराब की, अपना व्यवहार भी खराब किया, लेकिन फिर भी हमारा आग्रह रहेगा कि आप बड़ा मन करके, कानून के दायरे में जो चीज आती है, उसके अनुसार तो कार्यवाही करें ही, लेकिन आप बड़ा मन करके हाउस चलाने के लिए, एक बार मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि डायलॉग करके इस गतिरोध को तोड़ें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः और कोई बोलेंगे?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में हमारे इस सदन की बड़ी परम्पराएं रही हैं और हमारे बीच जो सीनियर्स हैं, उनसे हम सीखने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कल का जो दिन, यहां पर दो-चार दिनों से जो घटनाक्रम हुआ और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर जो टिप्पणियां की गईं, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया,

हमारे पारिवारिक रूप से भी किसी समाज में ऐसे शब्दों को मान्यता नहीं दी जा सकती और जिस तरीके से उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाकर, गम्भीरता से जिन शब्दों को बोला, मैं उन शब्दों की निन्दा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, निन्दा के साथ-साथ, आप हमारे इस सदन के बड़े संरक्षक हैं और आपका बड़ा मन और बड़ा विचार होना चाहिये। इस सदन में मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, हम सब मिलकर, चाहे सर्वदलीय बैठक बुलाकर या सभी को बुलाकर इस सदन को वापस निश्चित रूप से चलाने का प्रयास करें।

जिन-जिन लोगों ने आपका अपमान करने का प्रयास किया, जिन लोगों ने अपशब्द बोले, उन लोगों का ही अपमान हुआ। मैं यह मानता हूं कि आप जिस स्थान पर बैठे हैं, वह बड़ा सम्मान का स्थान है और हम जिस स्थान पर बैठे हैं, वह सम्मान का स्थान है। जो शब्दों से गलत बोलते हैं, मैं यह मानता हूं कि जिसने अपनी वाणी का गलत इस्तेमाल किया है, वह उन्हीं का अपमान होगा, हमारे इस सदन का अपमान नहीं होगा, इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय से भी आग्रह करता हूं, जो भी शर्तें, जो भी नियम, जो भी कानून हों, इस सदन को चलाने के लिए हम सबको शामिल करते हुए एक बार फिर प्रयास करें। आपके प्रति जो शब्द कहे गये, उनकी फिर से निन्दा और भर्त्सना करते हुए आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में उम्र में मैं सबसे छोटा हूं। जब कभी भी इस सदन की बात होती थी, भैरों सिंह जी के समय की, उनसे पहले के समय की, यहां पर जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने हमेशा परम्पराओं के बारे में बताया है कि इस सदन की क्या परम्पराएं रही हैं। जब विद्यालय में थे, विश्वविद्यालय में थे, उस समय सदन के बारे में सोचते थे कि किस तरीके से चलता होगा, माननीय सदस्य क्या-क्या करते होंगे, पर बड़ा दु:ख होता है कई बार कि जब वही माननीय सदस्य, जिनकी भागीदारी प्रदेश के विकास में होनी चाहिये, वे इस तरीके से यहां पर बर्ताव करते हैं।

सबसे बुरा तब लगता है, जो विक्रमादित्य का आसन है, जो हम सभी के संरक्षक हैं, चाहे वह पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, उनके बारे में जब इस तरीके की बातें की जाती हैं, वाकई चिन्ताजनक है और हम सभी को हृदय से दु:ख भी हुआ है। हम सभी कड़े शब्दों में इस चीज की निन्दा भी करते हैं। साथ ही साथ, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा, आपसे भी निवेदन करूंगा, उन्होंने जो किया है, वाकई वह बहुत बड़ा अपराध है, पर आप बड़ा दिल रखें, बड़ा मन दिखाएं और इस सदन को आगे चलाएं ताकि इस प्रदेश की 8 करोड़ जनता का कुछ भला हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो पिछले चार-पांच दिनों में गतिरोध हुआ, वह नहीं होना चाहिये था। कोई जीता, कोई हारा, यह भी प्रश्न नहीं है। जिन शब्दों का इस्तेमाल कल किया गया, उनकी निश्चित रूप से कोई भी प्रशंसा नहीं कर सकता। मैं भी प्रशंसा नहीं कर सकता। विरोध होते हैं, इससे पहले भी कार्यवाहियां होती रही

हैं, विपक्ष का एक धर्म होता है, वह निभाता है, आप स्वयं गवाह रहे हैं कई बार। इधर सत्ता पक्ष भी गवाह रहा है। सर, मेरा तो एक ही आग्रह है, वह तो निश्चित रूप से सही है कि गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आप बहुत अनुभवी, वरिष्ठ विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और अब अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हैं, मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है कि पिता तुल्य व्यवहार।

कई बार बेटा भी पिता से नाराज हो जाता है, अपशब्द भी कह देता है, लेकिन पिता अल्टीमेटली उसे माफ ही करता है और हम सब जानते हैं कि इसका हश्र भी अल्टीमेटली यही होना है। समझौता तो होगा ही, बजट सत्र के बाद नहीं, फिर होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार भी थोड़ा बड़ा दिल रखते हुए, क्योंकि स्वयं मैंने प्रत्यक्ष रूप से यहां देखा है, शब्दों के इस्तेमाल की निश्चित रूप से मैं भी निन्दा करता हूं, लेकिन यह कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, जो उस दिन घटी थी। उसी वक्त शायद शाम को हो जाता तो मेरा तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है और माननीय संसदीय मंत्री, आपसे विशेष रूप से, और आप स्वयं भी जानते हैं कि यह इश्यु नहीं है। जनता आपकी तरफ देख रही है। जनता आपकी तरफ देख रही है। गलती उनकी हो सकती है, गलती आपकी भी हो सकती है, गलतियों की छोड़ दीजिये, लेकिन उन गलतियों को छोड़ते हुए भी एक बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ा हृदय दिखाते हुए हमें यह करना चाहिये।

संवाद शुरू करें। कल भी हो सकता था। कहीं न कहीं कम्यूनिकेशन गैप हुआ कि पहले कौन करे। आप कहते हैं कि उन्होंने तय किया, हो सकता है तय किया होगा, मैं उससे बिलकुल असहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं तो था नहीं, कहीं न कहीं गलती हुई है। कई बार संवाद को न समझने की वजह से भी गलतियां हो जाती हैं। संसदीय मंत्री जी, मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि बजट सत्र तो पूरा हो जायेगा, लेकिन न तो आपको मजा आ रहा है, न हमको मजा आ रहा है और न उनको भी मजा आ रहा होगा, क्योंकि सदन का मतलब होता है, विपक्ष की उपस्थिति जरूरी है। उस विपक्ष की उपस्थिति को जरूरी मानते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए आप पुनः संवाद कायम करें, उन्हें बुलाएं। छोटा कोई नहीं होता। जो आदमी बड़ा हृदय दिखाता है, माफ करने वाला बड़ा ही होता है, छोटा कभी नहीं हो सकता। गलती करने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता। वह छोटा ही रहेगा। मेरा तो आपसे एक आग्रह है कि संवाद को पुनः शुरू किया जाये। निश्चित रूप से आप जो भी बाद में तय करें, नियम, प्रक्रिया जो भी हैं, उनके अनुसार कार्यवाही करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन संवाद होना चाहिये।

MKD/RTM/25.02.2025/13:10/1o

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): गर्ग साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि स्पीकर के पोडियम पर चढ़ना, एक छोटी बात नहीं है। It is a very major Parliamentarian crime. It is not something small.

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): बिलकुल सर, आपका कहना सही है।

श्री अध्यक्षः हो गया?

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): एक सैकंड, आपका कहना बिलकुल सही है। इस सीट से क्रॉस करना गलत था, लेकिन उससे पहले भी, मैं भी गवाह हूं और बहुत से सदस्य भी गवाह हैं। हमारे वर्तमान राज्यपाल कटारिया साहब यहां तक खड़े होते थे, इस जगह पर तो वे तो गये हैं अकेले, वो गये, जो उनका बिलकुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस जगह खड़े नहीं हुए हैं। खुद माननीय अध्यक्ष गवाह हैं तो मेरा यह मानना है कि यह इश्यु प्रतिष्ठा का नहीं है। यह इश्यु क्षमा करने का है और यह इश्यु बात को आगे सवांद को बढ़ाने का है। धन्यवाद, साहब।

श्री अध्यक्षः अपने दल से दो-तीन हो गये हैं, अन्य दल का हो तो फिर भी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, गलती दो तरह की होती है, एक हो जाती है, एक की जाती है और की जाती है में, जो बार-बार की जाती है, सोच-समझकर की जाती है तो वह चिन्तनीय होती है और उस पर आपत्ति किया जाना आवश्यक होता है। आसन से जिनको दंडित किया गया है या भूतकाल में जिनको किया गया है और आगे जिनको किया जायेगा, उसमें आसन का उद्देश्य यह रहता है कि अगला गलती को महसूस करे और उसको स्वीकार करे और उसको सुधारने की दिशा में अपना मानस व्यक्त करे।

वह सारा अवसर दिया गया है, पर्याप्त अवसर दिया गया है, जिन-जिन ने गलती की है, उनको सुधरने का, सुधारने का अवसर दिया गया है, खेद व्यक्त करने का अवसर दिया गया। उसमें भी वो चूके हैं। फिर भी, मैं सत्ता पक्ष की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि प्रतिपक्ष के सारे माननीय सदस्यों के लिए वार्ता के द्वार भी खुले हैं, हमारे दिलों के द्वार भी खुले हैं। आप अपनी गलती का अहसास करते हुए, अपने व्यवहार को सुधारने का आश्वासन देते हुए, यदि आयेंगे तो आपका स्वागत है। हमको भी आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सदन की मर्यादा और सदन की गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आप आइए, वेलकम। हम वार्ता के लिए भी तैयार हैं और आपका स्वागत करने को भी तैयार हैं।

श्री अध्यक्षः अब लास्ट।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आप भी बोल लीजियेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्री जी ने जिस तरह के उच्च विचारों का और खुले हृदय का परिचय दिया है, वह स्वागत योग्य है, लेकिन क्या भारत की लोक सभा, भारत की राज्य सभा और राजस्थान की विधान सभा इस बात की साक्षी नहीं है कि ऐसे अवसर भी आये हैं, जब हमको कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हम कड़े फैसले नहीं लेते हैं तो हम लोकतंत्र के ऊपर आघात करते हैं, हम पाप के साक्षी बनते हैं, उसमें भागीदार बनते हैं।

जिस तरह के शब्दों का उपयोग माननीय अध्यक्ष महोदय के लिए किया गया है, ऐसा हिन्दुस्तान के इतिहास के अन्दर कभी भी किसी अध्यक्ष के लिए नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, नहीं किया गया है।

मैं माननीय मुख्य सचेतक जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की भावना का सम्मान करते हुए यह कहना चाहता हूं कि क्या लोक सभा से हमेशा के लिए, पूरे कार्यकाल के लिए किसी को निकाला नहीं गया है? यह हमारे लिए शर्म की बात है। हम सदस्यों के लिए शर्म की बात है। हमारे अध्यक्ष महोदय के लिए कोई +++ की बात करता है और हम कहते हैं कि हमारा हृदय खुला है, हमारे पिताजी के ऊपर आकर के कोई +++ मारे और कहें कि हमारा हृदय खुला है, ऐसा क्या हृदय खुला है।

मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य महोदय से कहना चाहता हूं, आपका पुराना प्रेम जग सकता है। आपका पुराना प्रेम जग सकता है, लेकिन इसके कारण आप लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, उसके भागीदार मत बनिये, मत बनिये, मत बनिये।

मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डोटासरा जी को अगर राजस्थान विधान सभा से पूरे कार्यकाल के लिए निलम्बित कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, वो भी कम है, कम है, कम है।

श्री अध्यक्षः लास्ट, थावर चन्द।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण काफी गम्भीर है। इसमें आपका भी अपमान हुआ है, सदन का भी अपमान हुआ और यहां जिस प्रकार सदन में उपस्थित रहकर भाषा का उपयोग किया गया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यह अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए, उनकी सदस्यता रद्द करिये, गोविन्द सिंह डोटासरा जी की।

श्री अध्यक्षः माननीय थावर चन्द, लास्ट हो गया। सबकी भावनाएं आ गई हैं। आपकी भावनाएं आ गईं। माननीय सदस्य, भावनाएं आ गई हैं। इस तरह तो हर सदस्य बोलना चाहेगा, यह अलग दल है।

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की घटना इस महान पवित्र सदन के अन्दर देखी गई, वह निन्दनीय है। हम लोग भी नौजवान हैं और इस सदन में आना हमारा एक सपना होता है। आठ करोड़ जनता, किसान, नौजवान, सबका एक सपना होता है कि यहां से कोई हल निकलेगा, कोई अच्छी बात निकलेगी और प्रदेश का भला होगा।

सत्ता पक्ष और विपक्ष एक गाड़ी के दो पहिये के समान हैं और दोनों की सदन के अन्दर आवश्यकता जरूरी होती है। जो घटना हुई, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग यहां परम्पराएं सीखेंगे, हमें एक उम्मीद रहती है। हम नौजवान हैं, नये हैं। ऐसी परम्पराएं सीखेंगे, जो बाहर समाज के भीतर भी ले जा सकें और आने वाले समय में नौजवान पीढ़ी भी इस सदन के अन्दर आये तो इन परम्पराओं का पालन करें।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है, परन्तु आठ करोड़ जनता की आवाज और जनता की जो उम्मीद और विश्वास है, उसको देखते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और राजस्थान की सरकार इस पर बड़ा फैसला लेते हुए, कोई ठोस कदम उठाते हुए, सत्ता पक्ष विपक्ष को भी आमंत्रित करे और वाद-विवाद और संवाद, अगर जरूरी रूप से सही रहा तो आने वाले समय में यह प्रदेश

फिर से नई ऊचाइयों की ओर जायेगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः अब मुझे, हो गया भाई। आपकी पार्टी से दोनों ने कर दिया। अब सब बोलेंगे, माननीय सचेतक महोदय, सब बोल लिये। सबकी भावनाएं आ गई हैं।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो घटनाक्रम हुआ, जो गतिरोध सदन में चल रहा है। जब आज हमने मीडिया के माध्यम से और अख़बार भी पढ़े, निश्चित रूप से जो भी सदन के यहां सदस्य हैं, उनको आज विपक्ष के कारण शर्मिंदा होना पडा। सदन में चाहे कार्यवाही समाप्त होने के बाद की ही घटना हो, लेकिन सदन में जिन हल्के शब्दों का, जिन गिरे हुए शब्दों को इस्तेमाल किया गया, निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं, वे लोगों से नजर नहीं मिला पाते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसी का व्यक्तिगत अपमान नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा आसन है, जिसकी मर्यादा में हम सब लोग बंधे हुए हैं, जिन कानून-कायदों में हम लोग बंधे हुए हैं, उस आसन की तरफ इशारा करके और ओछे शब्दों का इस्तेमाल करना, निश्चित रूप से यह सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कार्य हैं।

यह कोई सभा स्थल नहीं था। यह कोई पार्टी की मीटिंग नहीं थी। इतनी गिरी हुई बात कहकर सदन को शर्मसार करना, निश्चित रूप से उनको माफी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः आप बोलिये, फिर तो कहीं रुकेंगे ही नहीं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): साहब, मैंने क्या बिगाड़ा है?

श्री अध्यक्षः किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, आपकी भावनाएं आ गईं। मैं आपकी भावनाओं को समझ गया। किसी ने बिगाड़ा नहीं है, आपकी भावनाएं आ गईं। मुझे दो मिनट में समाप्त करके आगे बहस शुरू करवानी है। इन्होंने आपकी भावनाएं दे दीं। सत्ता पक्ष से कोई मत बोलो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इसलिए बोलना चाह रहा था। इस पूरी घटना का कल मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। जब आपने हाउस एडजॉर्न किया। जब सब यहां इकट्ठे हो रहे थे और जिस तरह की भाषाओं का यहां उपयोग किया गया और मेरे साथ कई दो-चार लोग और खड़े थे, मैंने रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि कुछ सदस्य लगातार छोटी-छोटी बात पर उत्तेजित हो जाते हैं, छोटी-छोटी बात पर डायस पर आ जाते हैं, कभी कहां आ जाते हैं। सदन स्थगित हो जाये। उसके बाद जब वेल में लोग बैठे हैं तो वहां पर कोई अपशब्द बोला जाता है तो उसका भी कोई नियम कानून बनना चाहिए। उनके खिलाफ भी कार्यवाही होने की व्यवस्था इस सदन में होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा का सदस्य भी रहा हूं। मुझे 35 साल हो गये, लेकिन 35 साल के इतिहास में पहली बार, मैंने कल जो दृश्य देखा, वह बहुत ज्यादा निन्दनीय है। राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा हम सदन में, मैंने प्रतिवाद किया, मैंने विरोध भी किया, लेकिन मेरी तरफ भी इशारा करके उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया।

अध्यक्ष महोदय, 35 साल में मैंने कभी इस तरह का दृश्य नहीं देखा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हम हमेशा परम्पराओं की, सदन की मान्यताओं की बात करते हैं, लेकिन उसको निभा क्यों नहीं पा रहे हैं, उस पर हमको विचार करना चाहिए।

आसन का सम्मान होना चाहिए, सदन के अध्यक्ष का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हम सब आपके लिए समान हैं। यह भी सही बात है, टॉक होनी चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत के पहले सारे सदस्य सन्तुष्ट होने चाहिए। वे माफी मांगें, जो भी आप तय करें, तब जाकर सदन का सम्मान गरिमापूर्ण रहेगा, इतना ही मुझे निवेदन करना है।

Bhs/Rtm/25.02.25/13.20/1p

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब शान्त रहें। अब शान्त रहें। माननीय सदस्यगण, आ गई बात। हो गई।

माननीय सदस्यगण, सब लोगों ने जो आसन के प्रति भावनाएं प्रकट की, मैं उनका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं और उनको अपनी ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद, विधान सभाएं सब उसमें काम कर रही हैं। सन 1952 से लेकर के राजस्थान विधान सभा भी काम कर रही है और तब तो मैं छोटा था लेकिन जब से समझ आई तब से विधान सभा की कार्यवाही समाचार पत्रों में लगातार पढ़ता रहा हूं लेकिन तब से लेकर के आज तक कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी। विरोधाभास भी हुआ, आन्दोलन भी हुए, खड़े होकर विरोध भी हुआ और दो-तीन बार यहां पर धरने भी दोनों पक्षों में से किसी न किसी ने धरने दिये। धरने के दौरान भी कभी भी ऐसी बात मैंने नहीं सुनी जिस प्रकार का यहां पर उन्होंने भाषण दिया, वातावरण दिया। वह भी किसी साधारण सदस्य ने नहीं एक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने और उसमें मुझे लगा कि सारी गरिमा और मर्यादाएं तार-तार हुईं, जिसको कोई भी आप में से भी बाकी मैं समझता हूं कि उनमें से भी व्यक्तिगत रूप से, कुछ लोगों ने आकर जब बताया, उनके मन में भी पीड़ा है। चूंकि पार्टी के साथ जुड़ाव होने के कारण वो खुले में नहीं कर पा रहे हैं और लगातार आसन पर आरोप लगा रहा था कि साहब पक्ष-विपक्ष दोनों तो एग्री हैं, आप एग्री नहीं हो, जबकि यह बात गलत थी और उसके आधार पर मैंने बड़ा मन रखते हुए भी जैसे ही परसों शाम को आया, बात करने के प्रयास किये। वरिष्ठ लोगों से भी टेलीफोन से भी बात हुई और कल जब सदन में आया, सदन में आने के बाद भी जिस तरह से प्रश्न काल के दौरान व्यवहार हुआ विपक्ष का मैंने बार-बार अपील की कि बैठ जायें और यह नियम है कि जिसको सदन निलम्बित करता है, अध्यक्ष नहीं करता, सदन जब प्रस्ताव लाता है तो हम सब मिल कर उस प्रस्ताव को पारित करते हैं, उसमें निलम्बित सदस्यों को तुरन्त यहां से चला जाना चाहिये थे, फिर भी नहीं गये। धरना दिया, धरने में मुझे प्रसन्नता है कि सत्ता पक्ष ने उनका पूर्ण सम्मान किया और उनके लिए जो व्यवस्थाएं थी वो मेरे सेक्रेट्री ने और आप सबने मिल करके उनकी समुचित व्यवस्थाएं कीं। उन व्यवस्थाओं के बावजूद भी कल जो दृश्य खड़ा

हुआ, मैं समझता हूं कि यह शर्मसार करने वाला भी है और बार-बार कहा जाता है कि बाप को बड़ा मन रखना होता है, बाप बड़ा मन तब रखता है जब बेटा भी बेटे का कर्तव्य निभाये। यदि बेटा नहीं निभाये तो बाप भी उससे अलग हो करके उसको घर से भी विदा कर देता है। कभी बाप फिर बेटे को घर में नहीं रखता। कठोर मन होता है, लेकिन कठोर मन से यह भी व्यवस्था कई बार बाप को लेनी पड़ती है।

हम संसदीय व्यवस्थाओं में रहते हैं इसलिये बड़ा मन करके ही कल मैंने सबको बुलाया। सत्ता पक्ष के भी लोग थे, विपक्ष के लोग भी थे, इनके वरिष्ठ लोग भी थे। वहां पर सारी बातचीत के बाद भी सारी बातें भूल करके व्यवस्था हुई और आज वो कह रहे हैं निलम्बित वालों को तो ना लॉबी में बैठने का अधिकार, मुझे बता दें नियमों में कहां बैठने का अधिकार है। कल स्पेशली परमीशन दी कि सदन में चूंकि डेडलॉक हम तोड़ना चाह रहे थे, सत्ता पक्ष भी तोड़ना चाह रहे थे और हम सब भी चाहते थे कि सब लोग आ जायें इसलिये बड़ा मन करके उनको बाहर भेज करके वापस स्पेशली जो आज तक की विधान सभाओं के इतिहास में पहली बार है कि राजस्थान में उनको अन्दर आने की अनुमति देकर के और बोलने की अनुमति दी। वहां पर जो वरिष्ठ व्यक्ति थे मैं उनके नाम भी सबके सामने, अब कोई उसमें छिपाने की बात नहीं है, सर्वसम्मति बनी कि सदन में उनको बुला करके वह अपने व्यवहार पर खेद प्रकट करेंगे। पहले माफी की बात थी लेकिन माफी चूंकि उनको लगा तीखा शब्द है तो फिर भी बड़ा मन रख करके हमने कहा कि वो अपना खेद प्रकट करें। उसके बाद जब वो खेद प्रकट कर लेंगे उनके निलम्बन को भी निरस्त करने पर भी सदन विचार करेगा और उस समय हमारे मंत्री जिस विषय को लेकर चला है कि आज जो उस लाइन को पढ़ा है मंत्री जी भी ऐसा कहने को तैयार थे कि उनके ऐसी कोई भावना नहीं थी। वह सदन में सबके सामने मैंने कहवाने की हां भर दी कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मंत्री जी बोलेंगे लेकिन शायद वो चाहते नहीं थे कि मंत्री यह बोलें। अब बार-बार कह रहे हैं कि साहब, मंत्री नहीं बोले इसलिये हमने खेद प्रकट नहीं किया। मंत्री जी उसके बाद ही बोलने वाले थे। पहले उनको बोलना था क्योंकि व्यवहार उनका यहां गलत था।

मुझे भी संसदीय अनुभव है। पांच बार से तो मैं भी विधायक हूं और यहां मैंने कभी नहीं देखा। कभी आये होंगे, बात करने के लिए आये होंगे और गलती से कभी एक बार 1952 से लेकर के आज तक के इतिहास में हुआ हो तो इसका मतलब अब परम्परा बनेगी इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और आपको लोक सभा की भी मैंने कल पढ़ कर के बतायी थी। वहां तो यहां तक है कि यदि कोई ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा, चढ़ेगा तो उसके निलम्बन के लिए प्रस्ताव लाने की भी आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः निलम्बित हो जायेगा।

व्यवस्था

भविष्य में सदस्य द्वारा आसन के समक्ष अवहेलना की स्थिति में वह स्वतः निलम्बित समझा जाएगा

तो आज मैं यह व्यवस्था दे रहा हूं कि आगे से कोई भी सदस्य किसी भी दल का होगा

यदि यहां पर खड़े होकर के सदन के यहां आसन की अवहेलना करेगा तो वह स्वतः ही निलम्बित माना जायेगा, कोई प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है।

अब उसके बाद कल यदि मैं स्थगित नहीं करता तो पता नहीं क्या दृश्य उपस्थित हो सकता था लेकिन सदन की गरिमा बनी रहे इसलिये स्थगित किया। स्थगित करने के बाद सब सदस्य बैठ जाते हैं जो भी उनको रहना होता है। यहां बैठ करके एक दल का अध्यक्ष प्रदेश का भाषण करे, उन शब्दों को मैं दोहरा नहीं सकता, आज अखबारों में सबने पढ़ा है। वह शब्द इस सदन के अन्दर ही कहे गये हैं। चाहे सदन की कार्यवाही चल रही हो चाहे न चल रही हो लेकिन सदन में बोलने जाने वाले शब्द बहुत गम्भीर हैं, अपमानजनक हैं। मेरा अपमान नहीं हुआ है यह इस आसन का हुआ है। अब यदि हम आसन का सम्मान चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं इस बात स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि यदि जो कुछ सदस्य ने कहा क्या करेंगे आप लोग यह सदन तय करेगा लेकिन ऐसा व्यक्ति सदन के सदस्य बनने के भी योग्य नहीं है। अब उसके लिए क्या किया जाये, क्या नियम है, यह सदन को तय करना है। सत्ता पक्ष प्रस्ताव कोई लाता है या विपक्ष लाता है और सदन उसमें क्या अपना व्यु करता है मैं उसमें कहीं भाग नहीं लेता। मैंने कोशिश की कि सबको संरक्षण, विपक्ष को भी देते हुए अपने सदन की कार्यवाही चलाऊं। इसलिये मेरे पर कई बार सत्ता पक्ष की ओर से भी आरोप लगा कि आप विपक्ष का पक्ष ले रहे हो। विपक्ष को लगा कि आप सत्ता पक्ष को बचा रहे हो, यह मेरे को दोनों ओर से, लेकिन मैं आज अपनी आत्मा के साथ कह सकता हूं कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। इसके बाद भी यदि इस तरह के शब्द सुने जायें तो मन को पीड़ा होना स्वाभाविक है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन आपके साथ है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः समझौते में वार्ता उन्होंने भंग की और उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं उनके सदस्य श्रीमान राजेन्द्र जी पारीक वहां थे, वो तो कह रहे हैं कि गीता पर रख कर कहें, वो वैसे ही कह रहे हैं कि जो समझौता हुआ है उसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद भी वो इस तरह का बाहर अभी भी टीवी पर जिस तरह का अपने शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, विरोध होता है, मैं सहमत नहीं हूं, असहमत हूं, विरोध होता है, लेकिन सदन के लिए और अध्यक्ष के लिए आसन के लिए आज भी जिन शब्दों का उपयोग हो रहा है क्या ऐसे वातावरण में कोई बात होना कितना उचित होगा यह सदन तय करे उसमें मैं तय नहीं करूंगा।

अब इसलिये इन अपशब्दों के लिए मैं आपसे आखिर में एक ही निवेदन करूंगा कि आप सब मेरे व्यक्तिगत नहीं, आसन का सम्मान रहे, यहां की परम्पराएं जिन्दा रहें, यहां की मर्यादाएं बनें और यहां के जो नियम हैं उनका पालन हो, इसके लिए आप लोगों ने मुझे इस आसन पर बैठाया। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था। एक कॉलेज में पढ़ाता था। कभी कल्पना नहीं की थी कि यहां पर पहुंचूंगा लेकिन मुझे आपने पहुंचाया, ऐसे शब्द सुनने के लिए तो मैं आसन पर नहीं आया हूं, अध्यक्ष नहीं बना हूं। इसलिये अब आप लोगों पर

छोड़ता हूं कि इस पर क्या किया जाये, कैसे किया जाये, कौन करे लेकिन इस पर कठोरतम विचार करके, ठीक है विरोध होते हैं, अल्टीमेटली बातचीत भी होती है लेकिन बातचीत का भी आधार क्या हो, किन बातों पर हो तो यह सब कैसे समाधान हो इस बात पर आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। मुझे इतना ही आपसे निवेदन करना है कि सदन के आसन की मार्यादाएं रखने के लिए और सदन की मर्यादा रखने के लिए हम सब कृतसंकल्प हैं और आप सब लोग भी उसके प्रति कटिबद्ध रहे। इतनी बात कहते हुए अपनी बात पूरी करता हूं।

अब चूंकि बहस होनी है।

श्री जयदीप बिहाणी (गंगानगर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह आपके आंसू नहीं हैं यह भारतीय संविधान के आंसू हैं। ...(व्यवधान)... आजीवन बैन लगना चाहिये डोटासरा जी के चुनाव पर। आजीवन बैन लगना चाहिये। आज भारतीय संविधान रोया है।

Kas/rtm/25.02.2025/13.30/1q

श्री अध्यक्ष: अब अपनी बहस शुरू हो, इसमें सबसे पहले प्रताप सिंह सिंघवी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, मैं भी कल के घटनाक्रम पर मेरी भावनाएं प्रकट करना चाहता था, लेकिन आपने मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष: आपकी भावनाओं का आदर है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): प्रताप सिंह जी, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, यह आपके आंसू नहीं बोल रहे हैं, संविधान के रखवाले के मन के हृदय के भाव हैं। संविधान की रक्षा करने के लिये, नियमों की पालना करने के लिये, स्वस्थ परम्पराओं की पालना करने के लिये विक्रमादित्य के आसन से उसके आंसू बोल रहे हैं। हमारे सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों की जो भावना है, उस भावना के अनुसार ही कार्यवाही होगी, आप निश्चित रहें, नियम और प्रक्रिया के तहत जो कार्यवाही करनी है, वह निश्चित रूप से करेंगे।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस विधान सभा के तीसरे सत्र के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले राजस्थान की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने असत्य वादे करके सरकार में आई कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका। उन्होंने असत्य वादा किया कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे वादे करके सरकार तो बना ली, पर ना तो किसानों को कुछ मिला और ना नौजवानों को कुछ

मिला और उनके साथ धोखा हुआ। इसी का नतीजा है कि राजस्थान की जनता ने उनको सबक सिखाया और वापस सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में दी। सभापति महोदय, आप यह भी जानते हैं कि बाकी की कसर गहलोत साहब और पायलट साहब के झगड़े में निकल गई। हाई कमान और गहलोत साहब के झगड़े में बाकी जो थोड़ी बहुत कोर-कसर बची थी, वह निकल गई और राजस्थान की जनता परेशान होती रही। सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची और यह सरकार मात्र सर्कस बन कर रह गई।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का भी आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित होकर यह राजस्थान का खूबसूरत बजट यहां पर पेश किया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह बजट राजस्थान की तकदीर और तस्वीर को बदलेगा।

माननीय सभापति महोदय, विकसित भारत के शिल्पकार हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। उसी की प्रेरणा से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी एक प्रण किया है कि राजस्थान को हिन्दुस्तान के अग्रणी प्रदेशों में लाएं। आज हम राजस्थान की ओर देख भी रहे हैं कि आज राजस्थान के गरीब, किसान, नौजवान, सबके लिये तेजी से काम हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय कर्ज का बोझ बढ़ता गया, भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते गये, लेकिन जब से हमारी यह डबल इंजन की सरकार आई है, हमने राजस्थान के विकास को गति देने के लिये प्रथम वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान का इतना बड़ा आयोजन करके, जिसमें 32 देशों के उद्योगपति शरीक हुए और करीब 35 लाख करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. हुए। मैं यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमारे मुख्य मंत्री जी की मंशा है और वो लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, उससे लगता है कि अगर यह सब धरती पर उतर गया, पूरा नहीं, आधा भी अगर धरती पर उतर गया तो ना तो यहां बेरोजगारी की समस्या बचेगी और राजस्थान की विकसित प्रदेशों में गिनती होने लगेगी।

सभापति महोदय, आप जानते हो कि पिछली सरकार के समय किस प्रकार से पेपर लीक के मामले हुए। पेपर लीक के मामले में सरकार की सुस्ती की वजह से बड़े लोगों पर एस.ओ.जी. या पुलिस हाथ डालने में डरती थी या पीछे हटती थी। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा नहीं, जिन्होंने हमारे गरीब के साथ, गरीब के बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिये और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज हमारी सरकार बनने के बाद 250 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मैं कह सकता हूं कि इस पाप को करने वाला कोई भी आदमी, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा हो, निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही होगी।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा काम हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह किया कि वसुन्धरा जी के समय बनी ईआरसीपी की योजना, जिसको कांग्रेस के शासन में ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसके नाम पर लोगों को गुमराह किया, वोट लेने का एक तरीका ढूंढा, पर राजस्थान की

जनता ने उस असत्य सरकार को सबक सिखाया और जैसे ही हमारी डबल इंजन की सरकार आई, आप सब जानते हो उस ईआरसीपी, जिसका नाम आजकल राम सेतु लिंक परियोजना है, उसका लाखों लोगों के सामने जयपुर में 17 दिसम्बर को माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा शिलान्यास करवाया। यही नहीं, इससे 17 जिले और 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। यह फायदा होगा तो निश्चित रूप से हमारे जिन जिलों में पानी की कमी है, सिंचाई की कमी है, उन जिलों को भरपूर फायदा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आप यह भी जानते हो कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की और प्रधान मंत्री जी से उसका शिलान्यास करवाया और 9300 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान कर दिया। इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार की विकास की गति कितनी तेजी से चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां एक वर्ष का कम्पेरिजन करना चाहूंगा, इसमें दो मिनट का समय लगेगा, आप मुझे समय बख्शेंगे। माननीय भजन लाल जी की सरकार और अशोक गहलोत जी की सरकार का एक वर्ष का कम्पेरिजन मैं आपके सामने करना चाहूंगा। 1.1.2023 से 31.12.2023 तक अशोक गहलोत जी की सरकार और 1.1.2024 से 31.12.2024 तक माननीय भजन लाल जी की सरकार में सोलर पम्प सैट वितरण संख्या, उनके एक साल में बटे 1200, हमने बाटे 33,629 सैट। प्रति सोलर पम्प सैट अनुदान में उन्होंने दिये 67 करोड़ रुपये, हमने दिये 508 करोड़ रुपये। पीएच.ई.डी, बी.ए. और पी.जी. करने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि उनके समय में 23,252 दी गई और हमारे समय में 33,282 दी गई।

Msk/rtm/25.02.25/1340/2a

ड्रिप इरिगेशन में 66149 संयत्र उन्होंने दिये, हमने 1 लाख 501 दिये। माननीय सभापति महोदय, गोशाला सहायता की बात करते हैं। गोशाला में उन्होंने 733 करोड़ रुपये दिये और हमने 1233 करोड़ रुपये दिये। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना के तहत उन्होंने 4232 स्कूटी दी, हमने 14194 दी। आप कहीं पर भी देख लें। जिस प्रकार से महिलाओं के अपराधों में कमी आयी। उनके वक्त में एक वर्ष में, मैंने जो पिछली तारीख बतायी है, उनके एक वर्ष में 82,174 और हमारे समय में 37 हजार। प्रधानमंत्री आवास में उनके समय 24 हजार, हमारे समय में 23 हजार से अधिक। प्रधानमंत्री आवास शहरी में उनके समय में 7456 और हमारे समय 86,215 दिये गये। इस प्रकार से आप देखेंगे। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

नवीन सड़कों का मामला है। उनके समय में 4173, हमारे समय में 9600, इस प्रकार से विकास के प्रति, राजस्थान की जनता के प्रति हमारी सरकार का डेडिकेशन बताता है कि हम किस प्रकार से राजस्थान के पिछड़े व गरीब लोगों का भला करना चाहते हैं। यही नहीं, बोलने को अभी बहुत कुछ है। मैंने अपराधों का मामला जिक्र किया। राजस्थान पत्रिका में एक 'रक्षा-कवच योजना' के तहत साइबर क्राइम का मामला उठाया। आप जानते हैं कि भरतपुर संभाग में साइबर क्राइम बहुतायत में है, उसको रोकने के लिए और राजस्थान में कहीं

साइबर क्राइम नहीं हो, इसके लिए पुलिस हैडक्वार्टर पर कंट्रोल रूम और इसके लिए 350 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): एक मिनट और दे दीजिये, साहब।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 31 सदस्य बोलने बाकी हैं और अध्यक्ष महोदय ने 6 बजे समाप्त करने के लिए कहा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): पिछली सरकार के कार्यकाल में करौली, जोधपुर व अन्य जगहों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में दंगा हुआ और उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही, जो दोषी नहीं थे। दंगाइयों को छोड़ दिया गया। छबड़ा दंगे के पूरे प्रकरण की दुबारा जांच करवाने की मांग करता हूं।

श्री सभापतिः माननीय कैलाश जी मीणा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): साहब, दो लाइन और बोलने दें। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी और हमारे मुख्य मंत्री भजन लाल जी, दोनों एनवायरंमेंट के मामले में बहुत चिंतित हैं। हमने पिछले वर्ष 7 करोड़ पेड़ लगाये, यहां राजस्थान का पर्यावरण ठीक रहे। इस वर्ष भी बजट में घोषणा 10 करोड़ पेड़ लगाने की है।

श्री सभापतिः माननीय कैलाश जी मीणा। अंकित नहीं होगा। प्लीज।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): 000

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा 2025 में टीएसपी क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी, उप मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री महोदया जी के द्वारा किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, महिलाएं एवं समस्त वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है, जिससे राजस्थान में नये आयाम स्थापित होंगे, विकसित राजस्थान का सपना पूरा होगा। मैं मुख्य मंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय जी, 2025 के बजट में हमारी भाजपा सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र एवं समस्त वर्गों के लिए बजट में कई घोषणाएं हुई हैं। जैसे कि इस बजट में 19.84 करोड़ की पेयजल योजना गढ़ी, नगरपालिका में 400 केवी जीएसएस बांसवाड़ा, पनासी छोटी में 33/11 केवी जीएसएस, 220 केवी जीएसएस गढ़ी में, 150 यूनिट प्रतिमाह बिजली मुफ्त, डामर सड़कों के लिए गढ़ी विधान सभा क्षेत्र में 35 करोड़ से अधिक के कार्य स्वीकृत करना। बांसवाड़ा जिले के लिए सलूम्बर, बांसवाड़ा हाईवे की डीपीआर के लिए 1.40 करोड़ रुपये और प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में डामर सड़कों के लिए 15 करोड़ आवंटित किये। अटल प्रगति पथ, बांसवाड़ा में रिंग रोड, जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए 1750 करोड़ की राशि की बजट में घोषणा करने, जनजाति क्षेत्र को विकसित करने के लिए सबसे बड़ा कदम है। मैं बजट घोषणा के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी भजन लाल जी शर्मा एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी

को जनजाति क्षेत्र की ओर से आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय जी, आदिवासियों का महाकुंभ कहलाने वाला बेणेश्वर धाम विकसित करने, उदयपुर से बेणेश्वर, त्रिपुरा सुंदरी, माही डेम, गोठिया अंबा, मानगढ़ धाम, शहादत स्थली, गल्याकोढ तीर्थ स्थल, ऋषभ देव, सीता माता अभयारण्य, गौतमेश्वर आदि को पर्यटन से जोड़ने की घोषणा से लाखों आदिवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह आत्मनिर्भर भारत का प्रधान मंत्री मोदी जी का सपना साकार होने जा रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उड़ान योजना के तहत बांसवाड़ा में तलवाड़ा हवाई पट्टी को विकसित करने की घोषणा, वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए 6 हजार हवाई यात्रा, 50 हजार एसी ट्रेन से यात्रा की घोषणा। माननीय सभापति महोदय जी, हमारी सरकार ने युवाओं, बेरोजगारों के भविष्य को संवारने के लिए 1 लाख 25 हजार सरकारी क्षेत्र में नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर में डेढ़ लाख युवाओं को नौकरी देने और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से उद्योग बनने से हमारे युवाओं को सैंकड़ों रोजगार प्राप्त होंगे। प्रदेश के युवाओं के लिए आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी घोषणा करना मुख्य मंत्री जी का साहसिक कदम है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, हमारे जिले एवं विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सागवाड़िया, आसोड़ा, आमजा, चांदरवाड़ा, चोकला आदि गांवों में पीएचसी खोलने की घोषणा कर टीएसपी क्षेत्र को विकसित करने की ओर बड़ा कदम है। जनजाति के लोगों को नजदीक के स्थान पर चिकित्सा लाभ मिलने की..।

माननीय सभापति महोदय जी, विश्व के नेता प्रधान मंत्री मोदी जी ने वर्ष 2014 में केन्द्र में सरकार होने के बाद जनजाति परिवारों के 18 हजार गांवों में 46 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन मुफ्त दिया, गैस कनेक्शन मुफ्त दिया। 'हर घर नल से जल' योजना में गरीब को शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करायी। हमारी पार्टी ने सरकार में आने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक वर्ष में हर वादा पूरा किया। 450 रुपये में सिलेण्डर, घोषणा के अनुसार खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खोला। पीएम आवास वंचितों को देने के लिए सर्वे कार्य प्रारंभ करना, आदि वादे पूरे किये हैं। कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों में इन सभी योजनाओं को बन्द करने का काम किया। इनके पास जनहित की एक भी योजना नहीं थी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान डूंगरपुर के विधायक साथी और चौरासी के हमारे विधायक साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के खिलाफ पार्टी है। इनको यह पता नहीं है कि प्रदेश में पहली बार 1977 में स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत जी की सरकार बनी। गरीब के लिए अंत्योदय योजना लागू हुई। पहली बार गरीबों को लाभ मिलना शुरू हुआ। उससे पहले कांग्रेस एकतंत्र शासन में थी, परन्तु इनके पास गरीब, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार के नाम एक भी योजना नहीं थी।

माननीय सभापति महोदय जी, जनजाति क्षेत्र के बलिदानी लोगों का इतिहास, कांग्रेस के

पास नाम-निशान नहीं था। महान योद्धा राणा पूंजा हो, नाना बाई खाट, काली बाई, आदिवासियों के मानगढ़ पर 1500 से अधिक योद्धाओं का नरसंहार आदि घटनाओं का कहीं भी वर्णन नहीं था, परन्तु स्वर्गीय भैरोसिंह जी शेखावत द्वारा इन घटनाओं को इतिहास के पन्नों पर लाने का काम किया। डूंगरपुर में नाना बाई और काली बाई मूर्ति का अनावरण, पहली बार पैनोरमा एवं उदयपुर में राणा पूंजा की मूर्ति की स्थापना भैरोसिंह जी शेखावत साहब के द्वारा की गयी, जिसकी बाप के विधायकों को जानकारी नहीं है। मानगढ़ धाम, गोटिया अंबा, बेणेश्वर धाम, त्रिपुरा सुंदरी आदिवासियों के प्रख्यात जितने भी तीर्थ स्थल हैं, इनका निर्माण भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। कांग्रेस की 'बी' पार्टी बाप दोनों मिलकर आदिवासियों, युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, ये सब ज्यादा चलने वाला नहीं है। इनसे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। इन लोगों की वजह से हमारा वागड़ विकास में पिछड़ रहा है।

mdp/rtm/25.02.2025/13:50/2b

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि आदिवासी को 41 प्रतिशत आरक्षण देकर सैकड़ों नौकरियां भैरोसिंह जी एवं पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी की भाजपा सरकारों की देन है। कांग्रेस और बाप पार्टी को बताना चाहूंगा कि 1995 में पंचायती राज अधिनियम लागू कर स्वर्गीय भैरोसिंह जी ने पंचायती राज में जन-प्रतिनिधियों को एस.सी./ एस.टी./ओ.बी.सी. का आरक्षण लागू कर जिला प्रमुख, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच आदि जगहों पर चुनाव लड़ने का मौका देना भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने जीरो प्रतिशत अंक वालों को भी नौकरी दी। कांग्रेस के पास गरीब के लिए आज दिन तक कोई योजना नहीं है। कांग्रेस एवं बाप के लोगों ने आदिवासियों को भ्रमित कर सिर्फ वोट लेने का काम किया है, विकास का काम नहीं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बजट में आदिवासियों के हितों एवं विकास के लिए टी.एस.पी. क्षेत्र की कई सारी सौगातें घोषणा में ली हैं। दो बार बजट घोषणा, पहली बार टी.एस.पी. क्षेत्र के लिए विकास का वर्णन हुआ है। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मांग रखता हूं और मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनजाति विभाग के माध्यम से सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा चलित लिफ्टें, एस.टी. कृषकों को कुएं गहरे करने व मरम्मत के लिए व्यक्तिगत लाभ की योजना लागू करना, विद्यालय क्रमोन्नत करने, नये बालिका विद्यालय खोलने, उहाना घाटी सिसरवाला, डबल पट्टी सड़क, बछ़डिया से दशरा, आजना से गलियाखोट पूल तक, गढ़ी से अर्थूना, नया तालाब से भीमकुंड, रामकुंड आदि डबल पट्टी रोड आवश्यक हैं। उन्हें स्वीकृत कराने हेतु निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मेरी विधान सभा गढ़ी और सागवाड़ा के बीच में लम्बी दूरी होने की वजह से माही नदी पर एक पुल की आवश्यकता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गढ़ी और सागवाड़ा विधान सभा दोनों के बीच में, दोनों जिलों को जोड़ने के लिए कटकेश्वर महादेव

मन्दिर पर दोनों तरफ पुल, वजागरा पुल, रोहिड़ा, उलाईपनासी बड़ी एवं राजस्व ग्रामों को डामर से जोड़ना आवश्यक है। पंचायत समिति तलवाड़ा में माकोद, बड़गांव, उलघंटाला, रकावा पुल देवलिया नदी पर आदि स्थानों पर नदी-नालों पर पुलिया निर्माण करने की मांग रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद जी।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके लिए मेरी विधान सभा की जनता की तरफ से आपका दिल की हार्दिक गहराइयों से धन्यवाद।

सबसे पहले मैं इस शानदार, जानदार बजट के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी व हमारी वित्त मंत्री महोदया दिया कुमारी जी को हमारी तरफ से और हमारे प्रदेश की 8 करोड़ जनता की तरफ से बहुत-बहुत हार्दिक आभार व बधाई देना चाहता हूं। हमने सर्वजन हिताय की सोच के साथ इस बजट के माध्यम से प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है।

हमने तो समुन्दर के रुख बदले हैं।

मोदी जी, भजनलाल जी ने सोचने के सलीके बदले हैं।

आप कहते थे, कुछ नहीं होगा, मेरे कांग्रेस भाई यहां नहीं हैं,

लेकिन आप कहते थे, कुछ नहीं होगा,

हमने आपके भी सोचने के तरीके बदले हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट सार्वभौमिक, सभी वर्गों का ध्यान रखने वाला, किसानों, व्यापारी, युवाओं, महिलाओं और आम आदमी को राहत प्रदान करने वाला बजट है। जो पहला बजट सरकार ने दिया था, वह स्वर्णिम बजट था। अबकी बार सोने पर सुहागा जैसा बजट देने का काम किया है, हमारी वित्त मंत्री महोदया ने। आपने क्या किया? आपने तो 5 साल होटल में मौज मस्ती की है। लड़ाई झगड़े के अलावा किया ही क्या है? किसी शायर ने क्या गजब कहा है-

तुम लाख कोशिश कर लो, हमको बदनाम करने की,

जब भी बिखरेंगे, दुगुनी रफ्तार से निखरेंगे।

प्रदेश की जनता को कोटि-कोटि धन्यवाद। पिछले बजट की सभी घोषणाएं आज धरातल पर उतरती नजर आ रही है। यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय की मेहनत का परिणाम है। हमारी सरकार ने जो ठाना है, वह करके दिखाया है। रामजल सेतु परियोजना का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। सबसे बड़ा काम राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ से अधिक के समझौते, ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जन घोषणा पत्र की 58 प्रतिशत तथा बजट घोषणा की 73 प्रतिशत प्रगति हमारी सरकार ने सुनिश्चित की है।

हमारे प्रदेश की वित्त मंत्री महोदया ने पिछले बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र, जो सबसे लास्ट मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, उसमें प्रदेश की वित्त मंत्री महोदया ने मांगने से भी ज्यादा दिया। पिछली सरकार ने क्या दिया? हमारी सरकार की लम्बी फेहरिस्त पढ़ते-पढ़ते घंटा लग जाएगा। मुझे मनोहर थाना में पी.एच.ई.डी. कार्यालय, मनोहर थाना में नवीन बस स्टेंड, केल कोइरा पुलिया, अकलेरा में सी.एच.सी., सेटेलाइट, मनोहर थाना लहसुन मंडी, मनोहर थाना में नवीन बाइपास रोड, मनोहर थाना में चंदीपुर पी.एच.सी. क्रमोन्नत, छापी मध्यम परियोजना की सुविधा व सर्वे, ग्राम सरड़ा में एम.एस.टी., कश्तारी गोरधनपुर में गोपालपुरा तक सड़क, अकलेरा में एस.सी. छात्रावास, रामपुरिया से आकेपुर के मध्य पुलिया, सम्पर्क सड़क गणेशपुरा दरावत के मध्य पुलिया-20 लाख, बंदाजी खेड़ा जागीर देवरीखुर्द के मध्य पुलिया-15 लाख, एचएस 37 से पुनियांखेड़ी के मध्य पुलिया मरम्मत कार्य-14.60 लाख, असनावत से राता देवी के मध्य पुलिया मरम्मत कार्य-50.60 लाख, घाटोली से ओढ़ावाली माताजी की सुरक्षा दीवार 20.60 लाख, हरनावदा पुलिया बाम्बोला रोड से कामखेड़ा मध्य पुलिया मरम्मत कार्य-15.60 लाख, टोडरी जगन्नाथ से रोड वर्क एवं नाली निर्माण-16.60 लाख, एचएस 37 से बरडावड़ा रोड के मध्य पुलिया मरम्मत कार्य- 32.60 लाख, एनएच 52 से गोरबंध सड़क के मध्य पुलिया मरम्मत कार्य-28.60 लाख, घाटोली से दुर्जनपुरा पुलिया मरम्मत कार्य-40.60 लाख, चुरलिया से डाबा गांव के मध्य नाले की सुरक्षा दीवार-15.60 लाख, बासोदिया से सनखेड़ी के मध्य क्षतिग्रस्त दीवार 15.60 लाख, एनएच 52 से बासोलिया के मध्य 15.60 लाख, पुलिया कोखेड़ा से छडयाकुंआ के मध्य पुलिया मरम्मत कार्य-65.60 लाख, इस प्रकार से अगले बजट में ये मुझे मिला।

इस बार तो बजट में मौज कर दी।

कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें,
लहर-लहर तुफान मिले और संग-संग मंझधार हमें,
फिर भी दिखलाया हमने और आगे दिखा भी देंगे,
इन हालातों में आता है दरिया पार करना हमें।

इस बार तो बजट में मौज कर दी। राजकीय महाविद्यालय, अकलेरा इस बजट में दिया। मनोहर थाना बृहद सिंचाई परियोजना इस बजट में दी। कोडिझरी एवं नानगरदा एमएसटी इस बजट में दी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देलनपुर मठ मन्दिर छतरिया जीर्णोद्धार होगा, इस बजट में दिया। उनी, तुरकाडिया, बरडावदा, बिंदा, देवरीकला, मदनपुरा (एम.डी.आर. 380) (18.30 किमी)-28.36 करोड़ सड़क का निर्माण इस बजट में दिया। हमारी सरकार की सौगातें-

हमारे पंखों पर कौन विराम लगा सकता है,
जब हमें नियति से उड़ने का वरदान मिले।

सभापति महोदय, अब मेरी कुछ और मांगे हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को इस बजट में शामिल करवाएं ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को

इसका लाभ मिल सके। जो विकट समस्या है, हरनावदा, मनोहर थाना मार्ग से देवी जागीर के मध्य खेलड़ा गांव के पास परवन नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, उप जिला चिकित्सालय-विधान सभा मनोहर थाना, खेल स्टेडियम, खेल संकुल निर्माण-विधान सभा मनोहर थाना, नवीन नगर पालिका स्वीकृति एवं निर्माण-मुख्यालय विधान सभा मनोहर थाना, मेरी ये 4 मुख्य मांगे हैं। सरकार की इस बजट में ऐसी सौगातें आयी हैं, चाहे वह ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो।

ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के लाभान्वितों के घरों पर नि:शुल्क सोलर प्लांट्स लगाकर 150 यूनिट फ्री बिजली देना। दस मेगावाट के बिजली पावर प्लांट लगेंगे। दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदने की बिजली बैंकिंग व्यवस्था बंद होगी। पेयजल के क्षेत्र में तकनीकी कर्मचारियों का संविदा कॉडर बनाया जाएगा, इसके लिए 1050 नये पद सृजित होंगे। 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैडपंप लगाये जाएंगे। 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन दिये जाएंगे। रामजल सेतु लिंक परियोजना (ई.आर.सी.पी.) का आगाज किया गया है। सड़क के क्षेत्र में 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से 21 हजार किमी नान-पेचेबल सड़कों का सुधार भी इस बजट में शामिल किया गया है।

Ans/rtm 14.00 2c 25.02.2025

सभापति महोदय, 5 हजार करोड़ रूपये से अधिक की लागत से हाईवे बाईपास, ब्रिज, एलीवेटेड रोड बनेगे। 5 हजार से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण क़स्बों में अटल प्रगति पथ बनाये जाएंगे। बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाई जाएगी। युवाओं को लाखों की सौगात दी है, सरकारी विभाग व राजकीय उपक्रमों में 01 लाख 25 हजार पदों पर अगले वित्तीय वर्ष में भर्ती होगी व निजी क्षेत्र में 50 हजार युवाओं को रोजगार। युवाओं के लिए प्रदेश में विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की जाएगी। ग्रामीण विकास मनरेगा अंतर्गत 03 हजार 400 लाख मानव दिवसों का सर्जन किया गया है। स्वामित्व योजना में 02 लाख परिवारों को नये पट्टे दिये जाएंगे।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 06 हजार वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से तथा 50 हजार को एसी ट्रेन तीर्थयात्रा का आगाज किया है। सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न वर्गों के लिए पेंशन बढ़ाकर 01 हजार 250 रुपये प्रतिमाह, 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार, खाद्य सुरक्षा हेतु 10 लाख नवीन एफएस लाभान्वित के रूप में जोड़ना, यह हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी से जोड़ना। नगरीय विकास के दो लाख परिवार को नये पट्टे देना, 500 पिंक टॉयलेट बनाया जाना, 5 शहरी क्षेत्र में बसें मिलेगी। सुशासन के रूप में प्रथम चरण में 03 हजार से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों को अटल ज्ञान केन्द्र। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पीएचसी व डिजिटल एक्सरें मशीन लगेगी। 3 हजार 500 करोड़ का मां फण्ड बनाने की घोषणा। सभी जिला अस्पतालों में डाइबिटीज क्लिनिक खुलेंगे, 50 करोड़ की लागत से हाईवे के ट्रोमा सेंटर

का अपग्रेडेशन पीपीपी मोड़ पर होगा। कार्मिक कल्याण के रूप में समस्त मानदेय कार्मिकों के मानदेय में आगामी वर्ष में दस प्रतिशत वृद्धि, एनएफएस में राशन डीलरों के कमीशन में दस प्रतिशत तक वृद्धि।

श्री सभापतिः प्लीज समाप्त कीजिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): एक मिनट और। पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में आगामी वर्ष दस प्रतिशत की वृद्धि। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, 75 हजार किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान, 02 हजार किसानों को पॉली हाउस, शैड, मलचिंग के लिए 225 करोड़ का अनुदान। पशुपालन, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना श्रेणीवार बीमित पशुओं की संख्या दुगनी। एक हजार नवीन सहकारी समितियां, दुग्ध संग्रह केन्द्रों की स्थापना।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): इस प्रकार गोशालाओं तथा नंदी गोशालाओं हेतु पशुदेय अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन..

श्री सभापतिः श्रीमती कल्पना देवी।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारी सरकार की यह सौग़ातें हैं। जय हिन्द। जय भारत। जय-जय राजस्थान।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं कोटा की जनता की ओर से और खासकर लाडपुरा की जनता की तरफ से हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी और जिनके सहयोग के बिना यह मुमकिन नहीं होता, हमारे क्षेत्र के सांसद व लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को तह दिल से धन्यवाद देती हूं जिनके आर्शीवाद से हम इतने लाभान्वित हुए हैं।

माननीय सभापति जी, मेरा यह दूसरा कार्यकाल है। मैंने पहले भी पांच साल बजट की घोषणाएं सुनी है। मैं उन बजट की घोषणाओं और इस बजट की घोषणाओं को कम्पेयर करना चाहती हूं। वह केवल घोषणाएं थी और घोषणाएं तक रह गईं। हमारी सरकार आते ही, जो भी घोषणाएं हुई है, जिस तीव्र गति से उन पर कार्य किया जा रहा है यह बहुत ही सराहनीय काम है और इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि हमारी सारी घोषणाएं केवल घोषणाएं ही नहीं रहेंगी, इनका शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी इसी कार्यकाल में होगा। उद्घाटन की बात करूं, मैं पांच साल अपने क्षेत्र की बहुत सारी मांगें इस सदन में उठाती रही परन्तु गूंगी-बहरी सरकार ने एक नहीं सुनी। सार्वजनिक हितों की चिंता नहीं करने की वजह से आज शायद वह उस साइड विपक्ष में बैठे हैं, वैसे बैठे भी नहीं है, यहां है भी नहीं। मैं अपनी जनता को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने फिर भी मुझ पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा जताया और मुझे दोबारा एक अवसर दिया कि मैं उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों पर

खरी उतरू और उनकी जो भी समस्याएँ हैं, मांगें हैं उनको पूरा कर सकूं।

मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को कहना चाहती हूं, विकास की धारा अब बहने लगी, हर आशियाना में रोशनी आने लगी, कोटा की धरती फिर मुसकराई है जब बीजेपी सरकार की सौग़ातें आई है। कम्पेरिजन करने के क्रम में पट्टे की बात। बहुत हल्ला मचा था कि पट्टे जारी हो रहे हैं और इतने हजार पट्टे दिये जा रहे हैं। मैं बहुत दुख से कहना चाहती हूं कि लाड़पुरा विधान सभा क्षेत्र को बहुत ही द्वेषता पूर्वक देखा गया और वहां इतनी सारी कॉलोनियां अभी भी पट्टे से वंचित है। मेरे क्षेत्र में कृषि भूमि बसी कॉलोनियां कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है क्योंकि उनको अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने शहरी क्षेत्र की समस्या को समझते हुए आते ही अमृत 2.0 की योजना है, दो साल से प्रयास करने के बावजूद यहां डीपीआर की स्वीकृति हमें नहीं मिली, बार-बार फाइल जयपुर आती थी और कोई सुनवाई नहीं होती थी, मेरे क्षेत्र की लगभग 30 हजार जनसंख्या की आबादी को इस डीपीआर में जोड़ा भी नहीं, परन्तु इसके लिए मैं हमारे मंत्री कन्हैयालाल जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने कहा कि सभी को सम्मिलित किए बगैर यह कोई डीपीआर नहीं तैयार होगी और आते ही मेरे सोगडिया पूनम कॉलोनी क्षेत्र को इसमें जोड़ते हुए नई डीपीआर बनाकर, अमृत 2.0 योजना का कार्य अब जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है, उसके लिए मैं उनको और हमारे मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना से शहर में उपलब्ध कराने के लिए पानी का काम आरम्भ करने जा रहे हैं, यह भी बहुत ही सराहनीय कार्य है। शिक्षा का कम्पेरिजन करे तो बहुत बड़े शब्दों में उन्होंने राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की घोषणा करी, उससे क्या हुआ कि सर्वाधिक नामांकन वाले के जो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय थे उनको चिह्नित करके उनको अंग्रेजी मीडियम, अगर वह कोई नवीन भवन बनाते, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डालते तो हम मानते कि उन्होंने कुछ काम किया है, परन्तु मैं दुर्भाग्य ही बोलूंगी कि ऐसे काम करने से इतनी सारी बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह गईं, मैं समझती हूं कि उन बच्चियों के खिलाफ यह अक्षम्य अपराध है। आजादी के बाद पहली बार, हमारी सरकार आते ही, हमारे लाड़पुरा विधान सभा क्षेत्र में एक महाविद्यालय खोलने जा रहे हैं और इसके साथ ही कैथून में एक कन्या महाविद्यालय भी खुलने जा रहा है।

युवा के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं परन्तु किया क्या? हम देश का भविष्य युवा को मानते हैं, उनकी नवीन पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार ने उनके लिए एक स्पोर्ट्स अकेडमी लाड़पुरा में दी है। यह केवल घोषणा नहीं है, जमीन का आवंटन भी हो चुका है। मैं कहना चाहती हूं कि यह एक ऐसा प्लेटफार्म होगा, अपोरच्यूनिटी होगी जहां युवा अपने हुनर को निखारने के लिए, नशे में गलत कार्य करते हैं उसको भी डायवर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। साथ ही युवा को रोजगार हेतु तैयार

करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने उम्मेदगंज में पॉलिटेक्निक कॉलेज और 150 करोड़ की विश्वकर्मा स्किल इंस्टीटयूट की भी घोषणा की है। दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे राजस्थान प्रदेश में काफी हिस्से से जा रहा है, जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा में भी काफी हिस्से से गुजर रहा है, यह एक बहुत बढ़िया अपोरच्यूनिटी है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने गोपालपुरा में न्यु इंडस्ट्रीयल जोन के लिए घोषणा की है।

VPS-RTM-25.02.2025-14.10-2d

इसी के साथ मैं यह मांग रखना चाहती हूं क्योंकि कोटा की पहचान एक शैक्षिक नगरी के रूप में है और कोचिंग सेंटर्स की वजह से वहां पर काफी सारे हॉस्टल्स बने हुए हैं परंतु इस साल किसी कारण से कम बच्चे आने की वजह से यह काफी हॉस्टल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हैं परंतु वह यूज में नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप वहां पर एक लॉजिस्टिक हब या एक आई.टी. हब की घोषणा करेंगे तो रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा और यह बहुत ही बेहतरीन विकल्प मिलेगा। गुडगांव जैसे क्षेत्र की जैसे अगर आप यहां पर क्षेत्र देंगे।

इसी के साथ में कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली-मुम्बई की सारी ट्रेन कोटा से जाती हैं और आने वाले समय में एयरपोर्ट का भी जल्दी से जल्दी शिलान्यास होने जा रहा है। इसकी बात करने के बाद में तो पूर्ववर्ती सरकार ने एयरपोर्ट को खूब लटकाया, अटकाया और सब कुछ किया परंतु हमारी सरकार के आते ही सारी क्लियरेंसेज हमको मिल गयी हैं और डी.पी.आर. भी तैयार हो चुकी है और एयरपोर्ट का कार्य शीघ्र चालू हो जायेगा और साथ ही एक एयरोसिटी का निर्माण भी होगा। यह भी एक बहुत बढ़िया उदाहरण है डबल इंजन सरकार का।

मैं सिंचाई की बात करूं तो मण्डाना जो डार्क जोन है उसमें डी.पी.आर. के लिए दो करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है और वहां पर एक उम्मीद की राह जागी है कि वहां उनको सिंचाई का पानी मिलेगा और अभी एक माननीय वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे कि यह सरकार सिर्फ डी.पी.आर, डी.पी.आर. पर ही चल रही है तो मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट किये बिना डी.पी.आर. बनाये ही? डी.पी.आर. तो बनेगी तब ही तो काम चालू होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री ने हमें यह कहा है कि अवसर का फायदा लेना चाहिए, तो मैं चूकना नहीं चाहती और उसी अवसर का फायदा लेते हुए मैं अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांगें रखना चाहती हूं जो रह गयी हैं।

रायपुरा चौराहे पर एक फ्लाई-ओवर का निर्माण, नवीन खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय भवन का निर्माण, कैथून कस्बे में उप तहसील खोलने के क्रम में, एक नवीन मॉडर्न ऑडिटोरियम खोलने के क्रम में, एक लाडपुरा में बस स्टैंड के निर्माण के लिए, नवीन लाडपुरा पंचायत समिति भवन हेतु, कृषि भूमि में बसी कॉलोनियों के विकास हेतु रोड, नाली, लाइट,

पार्क आदि के लिए और इसी के साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि एम.एल.ए. फंड की राशि को पिछली सरकार में हमारे द्वारा 10-10 लाख रुपये एक विशेष यूनिवर्सिटी के लिए स्वीकृति मिली थी, मैं यह मांग रखती हूं कि हमें यह अनुमति मिले कि कोई भी एस.सी./एस.टी. छात्रावास के लिए अगर हम एम.एल.एल. फंड से राशि देना चाहे तो इसकी हमें अनुमति मिले। विधायक जन सुनवाई केन्द्र के लिए दस लाख रुपये जो दिये गये हैं वह बहुत कम हैं क्योंकि यह हमेशा के लिए एक ऐसा भवन बनने जा रहा है, तो यह राशि बढ़ाई जाये और सरकार की ओर से जो राशि और डाल सकते हैं वह डालें तो एक अच्छा भवन बन जायेगा जो बहुत ही अच्छा होगा आने वाले समय के लिए।

मैं अंत में यह कहना चाहती हूं कि अब कोटा की उड़ान होगी ऊंची, अब सपनों को पंख मिलेंगे, नई राहों पर चलने के लिए अवसर अनगिनत मिलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापतिः श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

बजट की चर्चा पर जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने इस बात पर विचार किया कि हमारी आदरणीय उप मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारीजी ने राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए भजन लालजी सरकार की जो दूरदृष्टि है उसको बड़ी स्पष्टता के साथ इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया लेकिन क्योंकि अभी हमारे कुछ युवा साथी, विधायक भी इस बात को रख रहे थे और मैं भी इस बात पर आज सदन में चर्चा करना चाहूंगी और अपनी बात मैं एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, रिवर व्यू नाम का एक छोटा-सा गांव हुआ करता था, जहां पर एक बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति, कभी भी गांव में किसी को समस्या हो तो वह यह बोलता था कि नहीं-नहीं, मैं हूं ना, आप चिंता मत करिये, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। गांव के लोग उसकी बातों से बड़े प्रभावित होते थे, बारबार वह अपनी बातों को रिपीट करता था, भाषणों में प्रयोग करता था तो गांव वालों को यह लगता था कि वाकई में हमारी कभी कोई समस्या होगी तो यह जरूर हमारे साथ खड़ा होगा।

माननीय सभापति महोदय, उस गांव में ग्रीष्म काल में भयंकर सूखा पड़ा। उस सूखे के कारण वहां पर पानी की समस्या बहुत आने लगी, तो सब गांव वाले उस प्रभावशाली व्यक्ति के पास गये कि हमारे गांव में अब सूखा पड़ा है, अब क्या करें? पानी पीने के लिए भी खतम होने वाला है। उन्होंने यह कहा कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, सब गांवों को एकत्रित करते हैं। गांव वालों को एकत्रित किया और बड़ी-बड़ी बातें कीं, गांव में सबको यह बात बोली कि अपन सब मिलकर एक नया कुआं खोदेंगे और उस कुएं के अन्दर से पानी जरूर निकलेगा। सब गांव वालों ने यह सोचा कि यह बात बोल रहे हैं तो ऐसा सच होगा, अब

हमारे को पानी का प्राब्लम सॉल्व हो जायेगा और नया कुआं खुदने से पानी कहीं न कहीं हमारे गांव वालों को मिल जायेगा। बातें होती गयीं। एक हफ़्ता, दो हफ़्ता, तीन हफ़्ता, चार हफ़्ता, पांच हफ़्ते निकल गये तो वापस सब गांव वाले मिलकर उनके पास गये तो उन्होंने यह कहा कि अब पांच हफ़्ते तो निकल ही गये, मैं तो सीधे बादलों से ही बात कर रहा हूं, वह बारिश जल्दी से आपके यहां गिराने वाले हैं। सब गांव वालों को उस दिन यह समझ में आ गया कि यह सिर्फ बातें करने वाले हैं और गांव कहीं नहीं होने वाला है। उस गांव के एक अनुभवी किसान के पास वे पहुंचे और उस किसान ने उन सब गांव वालों की यह बातें सुनीं, उसने अपना फावड़ा उठाया और गांव में जहां पर उन सबने यह तय किया था कि यहां पर हम कुआं खोदने की तैयारी करेंगे, वहां पर उसने धीरे-धीरे उस फावड़े से कुआं खोदना चालू किया। उसकी यह चीज देखकर सभी गांव वाले उसके साथ जुड़े और सभी गांव वालों ने मिलकर वहां पर कुआं खोदना चालू किया और एक-डेढ़ हफ़्ते में उस कुएं के अन्दर पानी भी हो गया और गांव वालों के यहां पर जो सूखा पड़ा था, उस समस्या का समाधान भी हो गया।

इस कहानी को यहां पर सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो प्रभावशाली बातें करने वाले या सिर्फ थोथी घोषणाएं करने वाले या सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करने वाली हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी और भजन लालजी की सरकार ने और इस बजट ने यह स्पष्ट किया है कि हम सिर्फ बातें ही नहीं करते, कार्य करके दिखाते हैं। जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हमारी जो चुनावी घोषणाएं थीं, उनका 58 प्रतिशत कार्य प्रगतिशील है, धरातल पर उतर गया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी और क्योंकि मैंने भी इस सदन में, मैं अपने आपको एक नई सदस्या ही मानती हूं क्योंकि ढाई साल मैंने कांग्रेस की सरकार के देखे और यह दूसरा बजट हमारी सरकार का हम देख रहे हैं, इस पवित्र सदन में कितनी बार कितनी ही बातें की गयीं लेकिन मैं यहां पर सिर्फ आपको राजसमन्द की ही कुछ बातें रखना चाहूंगी। खारी फीडर जो हमारे राजसमन्द के लिए एक बहुत ही ज्वलंत समस्या थी कि उस खारी फीडर को हमें रिपेयर करना था क्योंकि किसान भाइयों को पानी अच्छे से मिल सके और जो वेस्टेज हो रहा है पानी का वह बंद हो सके। क्योंकि उस सरकार का आखिरी बजट था, बड़ी-बड़ी बातें की गयीं और जो काम 150 करोड़ से भी, उस वक्त तो 125 करोड़ रुपये की लागत का ही था, तो उस काम के लिए हमारे को कुल 70 करोड़ रुपये की ही घोषणा की गयी और यह कहा गया कि हम खारी फीडर 70 करोड़ रुपये में बना देंगे, तो हमने उस बात का भी स्वागत किया कि बिलकुल आप इस खारी फीडर को बनायें लेकिन धरातल पर उतरने की कभी उनकी कोई मंशा ही नहीं थी। मैं आज इस पवित्र सदन में खड़े होकर धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लालजी को, हमारे आदरणीय सिंचाई मंत्रीजी को कि उन्होंने इस बात को गम्भीरता से लेते हुए पहले साल के बजट में ही 150 करोड़ रुपये इस खारी फीडर को दिये जिससे कि हमारे किसान भाइयों की समस्या का

समाधान होगा और यही नहीं इसका टेंडर भी हो चुका है और कार्य भी बहुत जल्दी से जल्दी चालू होगा। यह बात मैं आपको सिर्फ इसलिए कहना चाहती हूं कि यह एक नीयत दिखाती है, कहीं न कहीं यह बात यह बताती है कि भजन लालजी की सरकार सिर्फ बातें ही नहीं करती बल्कि इस बजट को एक पवित्र संकल्प के तौर पर लेती है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां पर जब उप चुनाव हुआ था तो यहां विपक्ष के साथियों में से कुछ मंत्री भी उस समय थे, उन्होंने वहां आकर बहुत सारी घोषणाएं की थीं कि हम इतना सारा काम राजसमन्द के अन्दर कराएंगे और राजसमन्द को एक नई गति देंगे, प्रगति की एक नई गति देंगे, लेकिन हम यह तब ही करेंगे जब आप हमें वोट दोगे, नहीं तो आप आपके और हम हमारे। ऐसी भावना रखने वाले उस समय के मंत्री और अभी वे हमारे विपक्ष के साथी भी हैं। ऐसी भावना रखने से ही जनता को साफ पता पड़ गया था कि यह काम कहीं नहीं होने वाले हैं। यह हमारी भजन लालजी की सरकार है जिसने एक बहुत बड़ी मांग कुंवारियां के अन्दर सी.एच.सी. देने का काम किया और वह काम इतना आगे बढ़ गया है कि जमीन भी अलॉट हो गयी है और बहुत जल्दी ही उसका शिलान्यास होगा और अगले एक-डेढ़ साल के अन्दर उसका उद्घाटन भी हम करेंगे, यह हमारी सरकार की कटिबद्धता है, यह हमारी सरकार किस तरीके से काम करती है, यह इस बात से बहुत स्पष्ट हो जाता है। इसके साथ-साथ ही मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को और हमारे चिकित्सा मंत्रीजी को जिन्होंने इस बात को संवेदनशीलता से लिया कि राजसमन्द के अन्दर आर.के. हॉस्पिटल जो एक जिला मुख्यालय पर एक जिला अस्पताल है, उसके अन्दर बेड्स की वृद्धि की है, जिससे हमारी जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर, वह जल्दी से जल्दी और बढ़ सकती हैं। इस बजट के अन्दर एक बहुत लम्बी मांग केलवा से आमेट की रोड को पक्का करने की थी।

SSY/RTM/25.02.2025/14.20/2e

क्योंकि वहां पर बहुत सारे उद्योग हैं और बड़े-बड़े डंपर्स निकलते हैं तो बार-बार वह रोड टूट जाती है और उसकी वजह से उद्योगों को नुकसान होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी आदरणीय दिया कुमारी जी और हमारे मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने 30 करोड़ रुपये इस रोड को बनाने के लिए दिये जिससे कि हमारे यहां के जितने भी उद्योग हैं उनको बहुत-बहुत सुविधा मिलेगी।

मैं आज यहां पर एक बात और कहना चाहूंगी क्योंकि सबने बजट की बहुत सारी बातें, मेरे साथियों ने भी रखी हैं कि बजट में हमें कितना सब कुछ मिला है, इस प्रदेश की जनता को बहुत कुछ मिला है। लेकिन आखिरी बजट की, कांग्रेस सरकार के आखिरी बजट की एक घोषणा, सिर्फ एक मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगी जो कि मोबाइल फोन वितरण योजना थी। जिस योजना के तहत महिलाओं को यह कहा गया कि हम आपको

डिजिटली इक्विपट करेंगे, हम आपको डिजिटली लोगों से जोड़ेंगे जिससे कि आप अपने घरों में बैठकर उद्योग भी कर सकते हैं, कितने नये आयाम कर सकते हैं, इसलिए हम आप सबको एक-एक मोबाइल फोन देंगे। बड़े-बड़े कैंप भी लगे। महिलाओं ने धूप में खड़े होकर भी अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन उस योजना का क्या हुआ? धरातल पर आधे से अधिक महिलाओं को मोबाइल फोन नहीं मिला। उन लोगों को सिर्फ यह बातें कही गयी, रजिस्ट्रेशन का सिर्फ एक पत्र दिया गया कि आप लोगों को हम यहां पर यह मोबाइल देंगे, लेकिन धरातल पर वह योजना कतई नहीं उतरी।

यहीं पर अगर हम देखें तो हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी जिस तरीके से संवेदनशील होकर इस राजस्थान के विकास के लिए काम करते जा रहे हैं निरंतर, उन्होंने राइजिंग राजस्थान पहले वर्ष में करके करीबन 350 खरब रुपयों के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त किये हैं। यह है हमारी सरकार और यह है हमारी सरकार की गुणवत्ता।

अब हम बात करें हमारे विपक्ष के साथियों की, आज वह यहां पर नहीं हैं और इतने हंगामे, मुझे तो लगता है, सभापति महोदय, वह हंगामे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं और नहीं होने का एक बहाना ढूंढा है क्योंकि उनके पास हमारी सरकार के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सरकार जिस तरीके से इतनी सीरियस होकर जब बजट पहला पेश हुआ था तो उससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार के टाइम पर बजट पेश होते थे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बजट सत्र चल रहा हो और प्रभारी मंत्रियों को भेजा गया हो मुख्यालयों पर और इस बात को रखा गया हो कि जितनी घोषणाएं हैं, उसमें तुरंत प्रभाव से उसके बारे में काम होना चाहिए। शायद यही कारण है कि पिछली बार जो बजट घोषणा हुई उसमें करीबन 73 परसेंट ऑलरेडी कार्यशील है, ऑलरेडी प्रगतिरत है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में भी जैसे ही बजट की घोषणा हुई इस रविवार को ही हम सब विधायक भी उन मीटिंग्स में मौजूद थे, जहां पर प्रभारी मंत्री अलग-अलग जिला मुख्यालयों पर गये और उन्होंने इस बात की जानकारी ली कि बजट को किस तरीके से धरातल पर उतारना है। साथ में प्रेस कांफ्रेंस करना, लोगों तक बताना क्योंकि हमारे पास कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सब कुछ इतना सामने है, सबके सामने है कि हम लोग यह चाहते हैं कि जनता तक हमारे भाव बहुत अच्छे से पहुंच सकें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता, हमारे इस विकसित भारत के शिल्पकार, हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी जिन्होंने यह बात कही कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए अगर 5 व्यवस्थाएं सही हो जायें तो प्रगति को कोई नहीं रोक सकता।

मुझे पता है आप समय को देख रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, सबसे छोटी सदस्या इस पार्टी की मानकर आप मुझे यह कहते हैं ना नेबर वाला धर्म निभायें और 2 मिनट थोड़ा सा और मुझे समय दें।

श्री सभापतिः बोलिये, बोलिये। समाप्त कीजिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उन्होंने 5 मूलभूत बातें, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य इस पर अगर हम काम करें तो हमारे देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता और हमारी राजस्थान की सरकार भी इन पांचों पर पूरी तरीके से काम करते हुए इस बात को सदा बता रही है कि हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम घोषणा नहीं करेंगे, हम संकल्पबद्ध होकर कार्य पूरे करेंगे। युवाओं को जिस तरीके से मजबूत करने के लिए इंडस्ट्री रेडी करने के लिए, फ्यूचर रेडी करने के लिए जिस तरीके से कार्य किये जा रहे हैं, सेंटर फॉर एडवांस कैरियर काउंसलिंग खोला जा रहा है, कौशल विकास के केन्द्र खोले जा रहे हैं। कौशल विकास संस्थान की घोषणा की गई है। मैं इस बजट में उसका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं। उससे हमारा युवा आत्मनिर्भर होगा और रोजगार के नये आयाम बनेंगे।

श्री सभापति: क्लॉज कीजिये। समाप्त कीजिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसके साथ-साथ हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने इस बार की मन की बात में कहा, मैं 2 मिनट में ही अपनी बात को समाप्त करुंगी। प्रधान मंत्री मोदी जी ने इस बार की मन की बात में कहा कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है। यह हमारी नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर होता है। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति में नारी शक्ति का सम्मान ही सर्वोपरि है। बेटियों को देवी जैसा माना गया है। हम उस परंपरा के वाहक हैं जहां पुरुषों की पहचान नारियों से होती है। यशोदानंदन, कौशल्यानंदन, कुंती पुत्र, आज नये इंडिया, न्यू इंडिया, नये भारत का सपना तभी साकार होगा जब नारी सशक्त होगी।

हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए चाहे लखपति दीदी योजना हो, चाहे कामकाजी महिलाओं के लिए आवास हो, बालिकाओं के लिए 35 हजार छात्राओं को स्कूटी वितरण हो या स्वयं सहायता समूहों का हो।

श्री सभापति: संदीप जी शर्मा।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 2 मिनट। 2 मिनट, संदीप जी, बैठिये आप। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या महिला उद्यमिता को बढ़ावा हो, इन सब पर कार्य करते हुए महिलाओं को सशक्त बनाया है। महिलाओं को नये आयाम दिये हैं कि वह आत्मनिर्भर हो सकें।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं अंत में अपनी बात को एक छोटी-सी कविता के साथ समाप्त करूंगी। एक छोटी-सी कविता के साथ। राजस्थान की माटी न्यारी, संस्कृति की गूंज है प्यारी, हर रंग में बसी यहां विरासत, हर स्वर में है अपनी खासियत, लोक गीतों की मिठास यहां, घूमर की छवि अनुपम, भाषाओं में मेलजोल, हर त्यौहार मनाये संग, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी की बात, हर क्षेत्र का अपना गौरव, अपनी अलग सौगात, लेकिन अब हम आगे बढ़कर विकास की राह बनायें, परंपरा संग नवाचार से राजस्थान को चमकायें। हर गांव में शिक्षा होगी, हर खेत में हरियाली, हर हाथ को काम

मिलेगा, ना होगी कोई बदहाली। सौर ऊर्जा से जगमग घर, तकनीक से बढ़े व्यापार।

श्री सभापतिः संदीप जी शर्मा।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सड़क, रेल, उद्योग बढ़ायें, युवाओं को दें नया आकार।

श्री सभापतिः प्लीज। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापतिः संदीप जी, आपका समय चालू हो गया।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे बजट 2025 पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

जो दृश्य मैं देख रहा हूं, बिलकुल खाली पड़ी हमारे सामने की सीटें और उसमें जिस तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय जो बहुत निष्पक्षता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ इस सदन को चला रहे थे और उनका प्रयास था कि चाहे वह पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, तटस्थ भाव से इस सदन को चलाकर राजस्थान की 8 करोड़ जनता की समस्याओं का निवारण इस सदन में हो सके, परंतु मात्र एक सदस्य की हठधर्मिता के कारण आज माननीय अध्यक्ष जी की आंखों में आंसू थे।

माननीय सभापति महोदय, हमारा दिल पीड़ा में था कि एक नेक शख्स जो पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, उनके दिल को आज माननीय एक सदस्य की हठधर्मिता ने तोड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बजट पर अपनी बात रखूं कि जिस तरीके से यह बजट 2025 माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी मेहनत से और सार्थक प्रयासों से एक बेहतरीन और एक प्रशंसनीय, सराहनीय बजट राजस्थान को दिया, जो राजस्थान के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है।

सभी वर्ग, सभी क्षेत्र और सभी विषयों को इस बजट में उन्होंने स्थान दिया। हर विषय को उन्होंने छूने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीयादिया कुमारी जी को जिन्होंने अपने सार्थक प्रयासों से इस बजट को बनाया है।

माननीय सभापति महोदय, इससे पूर्व जो 2023-24 का बजट था, हमें खुशी होती है कि जिस दृढ़ संकल्पबद्धता के साथ उसे धरातल पर लाया गया और प्रयास किया गया कि जो घोषणाएं बजट में की हैं, उन्हें शत-प्रतिशत क्रियान्वित किया जा सके। पूरी सरकार को धन्यवाद है कि पूरी सरकार ने उसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और आज वह सारी बजट घोषणाएं फलित होती हुई दिखाई देती हैं।

spp/rtm/25.02.2025/14.30/2f

यह यहां पर बैठे नहीं हैं, मैं इनसे पूछना चाहता था कि आपने 2018 से लेकर 2023 तक जितनी भी बजट घोषणाएं की गयी थीं, वह बजट घोषणाएं सिर्फ फाइलों में ही रह गयी थीं, उनमें से एक भी बजट घोषणाओं के लिये न तो प्रयास किये गये। जो अपने आप हो गयी, वह पूरी हो गयी।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने पांच हजार घोषणाएं बजट में कीं पांच साल के अन्दर, इनमें से मात्र दो हजार को यह क्रियान्वित करा पाये, क्योंकि न तो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, न इनके पास इम्प्लीमेंटेशन की, न एग्जिक्यूशन की, न कुशल प्रबन्धन की, किसी की भी इनके पास कोई इच्छा शक्ति नहीं थी, न इनके पास टीमें थीं। आज हमारे कार्य चुटकियों में पूरे होते हैं और जिस तरीके से इन्होंने पूरे पांच साल तक लोगों को गुमराह किया, किसानों को ऋण माफ करने के नाम पर, युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के नाम पर, महिलाओं को फ्री मोबाइल देने के के नाम पर, मरीजों को मुफ्त इलाज के नाम पर, जनता को सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया है। एक भी उद्योग यह राजस्थान में नहीं ला पाये। बेरोजगारी में इन्होंने राजस्थान को पूरे देश का नंबर एक राज्य बना दिया। महिलाओं में दुराचार और अत्याचारों में पूरे देश के अन्दर अग्रणी राज्य नंबर एक का राज्य राजस्थान को बना दिया और ऊपर से बानगी क्या, कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। पूरे राजस्थानवासियों को शर्मसार किया। यह हरकतें, इतना ओछापन, मुझे समझ में नहीं आता, किस प्रकार के संस्कार इनको विरासत में मिले हैं।

माननीय सभापति महोदय, साम्प्रदायिकता से पूरा प्रदेश झुलसता रहा। हमारे लोग पूजा-पाठ शांतिपूर्वक करते थे या कोई अपने त्योहार-पर्व मनाते थे तो उन पर सौ पाबन्दियां लगा दी गयीं। उनको चैन नहीं आने दिया। यह कृत्य इस राजस्थान में पिछले पांच सालों में कांग्रेस की सरकार ने किया है। आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया था।

माननीय सभापति महोदय, हम धन्यवाद देते हैं जिस तरीके से कोटा शहर को लेकर माननीय लोक सभा अध्यक्ष, ओम बिरला जी का सपना था और उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कोटा शहर के उस विकास के लिये काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कोटा शहर में पिछले पांच सालों में पांच हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ है। वह पांच हजार करोड़ रुपया कोटा के तीन कामों में हुआ। रिवर फ्रंट, ऑक्सीजोन और सिग्नल फ्री कोटा में रोड बनाया और इसके अलावा कुछ चौराहे बनाये जिसमें पांच हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिये गये। उन पैसों को उड़ा दिया गया जिनमें किसी की उपयोगिता को तय नहीं किया गया, न कोई टैक्निकली डिजाइनिंग उसको दी गयी। रिवर फ्रंट में एक भी पेड़ नहीं है, जीरो परसेंट, माननीय मंत्रीजी बैठे हुए हैं, उस रिवर फ्रंट में एक ग्रीन बैल्ट का काम नहीं है और जिस तरीके से अंडरब्रिज फ्लाईओवर का गलत डिजाइन किया, उससे आज भी एक्सीडेंट होते हैं। इस सौन्दर्यीकरण और विकास में सैकड़ों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गये, काल के ग्रास में

चले गये। पांच हजार करोड़ रुपयों ने कोटा के लोगों को बलि पर चढ़ा दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी का जिन्होंने कोटा में पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, धार्मिक महत्व, उद्योग, सीवरेज , पेयजल की पाइप लाइन, सड़कें और प्रत्येक आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोटा के चहुमुखी विकास की सुनिश्चितता को तय किया है और कोटावासियों के सुझाव व उनकी मांग पर हमने जो भी बात माननीय मुख्य मंत्रीजी को दी, शत-प्रतिशत उन मांगों को और हमारे आग्रह को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने माना। कोटा में हमें मिनि सचिवालय मिला है। कोटा एयरपोर्ट के निकट एयरोसिटी की स्थापना हुई है। मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट, कॉटेज वार्ड, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, 150 करोड़ से टॉय पार्क, बालिका सैनिक स्कूल, पैरा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, कोचिंग छात्रों के लिये युवा साथी केन्द्र, कोटा बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स एवं पैरा स्पोर्ट्स स्कूल को इस बजट में स्थान दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, वल्लभ सम्प्रदाय की प्रथम पीठ श्री मथुराधीश जी मन्दिर के विकास हेतु डी पी आर बनाने का प्रावधान भी इस बजट में किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस धार्मिक पर्यटन के विकास हेतु कॉरिडोर निर्माण हैरिटेज सिटी विकसित करने हेतु 65 करोड़ की डी.पी.आर.तैयार है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि डी.पी.आर. के मुताबिक इसमें 65 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कराकर हम कोटावासियों को अनुगृहित करें ताकि यह निर्माण शीघ्र हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं कोटावासियों की ओर से कि आपने कोटा में विकास की नई इबारत लिखी है। कोटा स्टोन में कई उद्योग चल रहे हैं जिसमें प्रमुख रूप से कोटा स्टोन और सैण्ड स्टोन है। कोटा पहले उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। पिछले बजट में कोटा स्टोन मण्डी को स्थान मिला था परंतु मेरी मांग है कि 2024-25 में जो स्टोन मण्डी का प्रस्ताव आया था, उसके स्थान पर कोटा के व्यापारियों की मांग है कि यहां स्टोन पार्क बने। व्यापारी इस पार्क में प्रोसेसिंग यूनिट लगा सके तथा कॉमर्शियल एक्टिविटी प्लान कर सकें। इस पार्क का उपयोग कर अधिक से अधिक लोग रोजगार से जुड़ सकें, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी यही विजन है, माननीय प्रधान मंत्रीजी का भी यही विजन है कि नये स्टार्टअप उद्योगों के माध्यम से आयें और हमारे पास कोटा स्टोन और कोटा का सैण्ड स्टोन ऐसा है जो विदेशों तक जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप इसको स्टोन पार्क में बदलने का काम करेंगे।

एक साल के जो हमारे काम हुए हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुनः हमारी सरकार को, जी.एस.डी.पी. 19 लाख 89 हजार करोड़ से अधिक होने का इस बार 2025-26 में अनुमान है। 2023 तक 350 डॉलर की अर्थव्यवस्था कर राजस्थान को एक विकास के नये आर्थिक आयाम मिलेंगे, आर्थिक सुदृढ़ता मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी के विकासवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी

शर्मा ने 2047 तक राजस्थान की इस अर्थव्यवस्था को तो मजबूत करेंगे ही परंतु आज जिस तरीके से ऊर्जा हो, पेयजल हो, सड़क हो, इस बजट घोषणा में उद्योगों को लेकर हमारी सरकार ने जो काम किया है, निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कार्य पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ किये जा रहे हैं, परिश्रम के साथ किये जा रहे हैं, उस दृढ़ इच्छा के साथ किये जा रहे हैं कि आने वाले समय में राजस्थान का अलग स्वरूप आने वाले इन पांच सालों में नजर आयेगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने यह बैठे होते तो इनको बताते कि आपने पांच साल में क्या किया और हमने जो आप लास्ट के तीन साल के अन्दर काम नहीं कर पाये, वह हमने एक साल के अन्दर करके बता दिया इस राजस्थान में।

मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी सरकार को, जो पहली बार आये थे और जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को संभाला है, इम्प्लीमेंटेशन करवाना जानते हैं लोगों को बिठाकर, किस तरीके से कार्य होता है, पूरी मेहनत के साथ, दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ राजस्थान के विकास को नये आयाम मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, निश्चित रूप से आपका भी बहुत बहुत आभार माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री अजय सिंहजी।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय सभापति महोदय, मैं बजट 2025-26 पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं, आपको समय देने के लिये धन्यवाद। डेगाना विधान सभा क्षेत्र के लिये दोनों बजट ही बहुत अच्छे रहे हैं। क्षेत्र के लोग खुश हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्रीजी को, वित्त मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और जनता की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी जिंदगी कब अच्छी होती है, हमारी जिंदगी तब अच्छी होती है जब हम खुश होते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी बेहतरीन हो जाती है जब हमारे कारण से हजारों, लाखों, करोड़ों लोग खुश हो जाते हैं। यह बजट भी इसी तरह का है। ज्यों-ज्यों यह बजट धरातल पर उतरता चला जाएगा, लोग भी खुश होते जाएंगे और विकास को भी नई गति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है।

jyg/Rtm/25.02.25/14.40/2g

माननीय सभापति महोदय, मेरे डेगाना क्षेत्र में उप जिला हॉस्पिटल बनेगा। देश की आजादी के बाद में मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसी भी भवन के ऊपर 40 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुआ है, अबकी बार पहली बार 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इसके लिए भूमि का आवंटन भी हो गया है, जहां पर हम चाह रहे थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्र चूई बिखरण्या कलां को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया है, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सीएचसी में क्रमोन्नत

नहीं किया गया है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत नहीं किया गया है, तो मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रहा है कि मेरी खुद की ग्राम पंचायत कुंदलोता तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसको सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये। इसके अलावा मेरी मांग है कि आंकरोली कलां को भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये। ग्राम पण्डवाला, रावलियास, भारली, मुण्डेलपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, बजट में घोषणा की गयी है कि 50 हजार नये कृषि एवं 5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन दिये जायेंगे, इसके लिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी घोषणा है। लेकिन मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि अभी भी कई ढाणियां ऐसी हैं जहां पर बिजली नहीं लगी हुई है, तो उनको सौभाग्य योजना में या किसी भी योजना में जोड़ने हेतु घोषणा करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना में गांव माझी निम्बोला कलां में 33/11 केवी के जीएसएस आपने स्वीकृत किये हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम थांवला बहुत बड़ी पंचायत है। अभी यह बेरूंदा के अधीन आता है और बेरूंदा जो एईएन ऑफिस है उसमें 35 हजार से ज्यादा उपभोक्ता हैं, तो मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि थांवला में 132 केवी जीएसएस निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें। थांवला में अभी जेईएन ऑफिस है, इसको भी एईएन ऑफिस में क्रमोन्नत करने का श्रम करें।

माननीय सभापति महोदय, अभी जो ऊर्जा विभाग का स्टोर है वो नागौर में है और मेरे डेगाना से वो 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है और कई जगह पर तो 140 किलोमीटर तक दूरी है। मेरा आग्रह रहेगा कि सब-स्टोर, उप भण्डार डेगाना में बन जाये, इसके लिए समुचित मापदण्ड की भूमि उपलब्ध है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा आग्रह रहेगा कि इसको जरूर-जरूर स्वीकृत करें।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन योजना का समय 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गयी है, यह बहुत ही अच्छी घोषणा है, इसके साथ ही जल जीवन मिशन शहरों में भी शुरू किये जाने की घोषणा की गयी है। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है कि डेगाना ऐसा विधान सभा क्षेत्र है जहां पर जल जीवन मिशन से सम्बन्धित न कोई भी अधिकारी बैठता है, न जेईएन बैठता है, न एईएन बैठता है, न एक्सईएन बैठता है। अभी दो एक्सईएन ऑफिस जायल में हैं, मेरी यह मांग रहेगी कि एक एक्सईएन ऑफिस को डेगाना में स्थानांतरित करें और जब कोई अधिकारी ही नहीं बैठता है तो किस तरीके से हम आशा रख सकते हैं कि जनता को पानी मिलेगा तो जरूर इस ओर माननीय मंत्रीजी, पीएचईडी के संज्ञान में भी यह बात ला चुका हूं।

इसके अलावा गत कांग्रेस सरकार के समय में जब एल एण्ड टी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पानी की लाइनें बिछायी जा रही थी तो उन्होंने गांवों में सड़कों को जगह-जगह से तोड़ दिया और पीएचईडी की लाइनें जब डेगाना शहर में बिछायी जा रही थी तो उन्होंने शहर में जगह-जगह से उसको तोड़ दिया और आज तक उनको दुरुस्त नहीं कराया गया है। मेरी सरकार से यह मांग है कि इसके लिए एक कमेटी गठित करे, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी, ईओ और पीएचईडी

के एईएन और जो वो रिपोर्ट दे कि जहां-जहां टूटी है उसको विभाग और ठेकेदार हैं वो उसको ठीक करे।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में मेरे चार ग्रामीण सड़कों को जिला सड़कों में क्रमोन्नत किया गया है और मेरी यह मांग है कि इन सड़कों को, इनमें से दो सड़कों को, मेड़ता सिटी एन.एच. 58, खेड़ूली, दत्ताणी, गयासनी, खुड़ी कलां, बरणा, बामणा, चूई, कवाल, जाखेला, मुण्डा खेड़ी, खारड़ीया, रानी गांव, इस सड़क का चौड़ाईकरण कराया जाये। इसी तरह से थांवला एन.एच. 58, देवगढ़, नृसिंह बासनी, कोट, कोडिया मोड, सथाना कलां, पादू कलां, मेवड़ा, नथावड़ा पाल्यास, पालड़ी कलां, नीमड़ी कलां, जावला तक ये जो रोड है, इसका चौड़ाईकरण कराया जाये। इसके अलावा सांझू में रेण से सांझू तक की जो रोड बनी थी, वो हमारी वित्त मंत्रीजी जब हमारे यहां से सांसद थी राजसमन्द की तो उनके प्रयासों से वो बनी लेकिन उसका बाईपास नहीं बन पाया था, इसके लिए समुचित भूमि भी है, मेरी माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग है कि सांझू कस्बे के बाईपास निर्माण की स्वीकृत प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे खुद की ग्राम पंचायत में एक शिव गुफा है, बहुत धार्मिक आस्था का प्रतीक है, धार्मिक आस्था का केन्द्र है, मेरा आग्रह है कि इसके आसपास अभी चेजा पत्थरों की खानों की नीलामी की गयी है। मेरा आग्रह है कि उसके आसपास जो नीलामी की है वो नहीं की जाये और जो आसपास की खानें हैं उनको निरस्त किया जाये और भविष्य में इस तरह की व्यवस्था की जाये कि इस गुफा को कोई भी नुकसान न पहुंचे। मेरी माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग रहेगी कि शिव गुफा तक सीसी सड़क बनायी जाये।

माननीय सभापति महोदय, डेगाना विधान सभा क्षेत्र में गत सरकार के समय बरसाती पानी और गंदे पानी के निकास के लिए नाला निर्माण शुरू करवाया था, वो पूरा नहीं हुआ है और उसका काम बीच में ही रुक गया है, मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि वो वित्तीय अनियमितता के कारण कांग्रेस के समय में नहीं बन पाया था तो इसके लिए कम से कम 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करे ताकि यह नाला पूरा बन सके।

माननीय सभापति महोदय, आपने एक हजार ट्यूबवैल और डेढ़ हजार हैण्डपम्प की घोषणा की, यह भी बहुत स्वागत योग्य है। मेरा इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है कि आप हमें जो ट्यूबवैल और हैण्डपम्प देते हैं उसकी जगह अगर सोलर सिंगल ट्यूबवैल या हैण्डपम्प दे दें तो बिजली का बिल भी नहीं आयेगा और ये सभी क्षेत्र के लोगों के लिए भी ठीक रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, बजट में घोषणा की गयी कि 35 लाख किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जायेगा। यह बहुत अच्छी घोषणा है कि बिना ब्याज के किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। लेकिन मेरा इसमें एक आग्रह माननीय मुख्य मंत्रीजी से है कि गत जो साल गया है उसमें किसानों से सैकड़ों करोड़ रुपये

वसूल नहीं हुए हैं। जब आप वसूल कर नहीं पाये तो किस तरीके से आप देंगे, तो इसमें मेरा आग्रह है कि जिन किसानों से वसूली नहीं की जा सकी है, उनका ब्याज माफ करें और तब वो जमा कर लें ताकि अपने पास पैसा भी आ जायेगा और किसानों को लाभ भी होगा और नये किसानों में वो पैसा भी बंट जायेगा। केसीसी लिमिट बढ़ायी गयी है, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने, इसके लिए उनका धन्यवाद। मैं इसके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि केसीसी की जो लिमिट बढ़ायी गयी है 3 से 5 लाख, अभी भी बैंक इसको ऋण देते हैं, इसमें सर्च के नाम पर 5-5 हजार रुपये वसूल कर रहे हैं, इसको वित्त विभाग देखे कि हर किसान से अगर 5-5 हजार रुपये अगर वसूल किये जायेंगे तो कहीं भी उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय था जिसको बहूद्देशीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, यह किसानों का रक्षा कवच है। वर्ष 2023 से खरीफ और रबी की नागौर जिले के हजारों किसानों का अभी भी बाकी है, उनको अभी भी क्लेम नहीं मिला है बल्कि जो किसान कुछ प्रदर्शन कर रहे थे, बीमा क्लेम की जो मांग कर रहे थे उनके विरुद्ध मेड़ता सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मेरी सरकार से यह भी मांग है कि वो मुकदमा वापस ले और मुकदमा बीमा कम्पनी के विरुद्ध करवाये, जिस बीमा कम्पनी ने किसानों का क्लेम समय पर नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, बाजरे के सम्बन्ध में भी बहुत अच्छी घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। बाजरा बड़ा पौष्टिक है और मिड-डे-मील में इसको लागू किया जायेगा। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से विनम्र आग्रह रहेगा कि भविष्य में चरणबद्ध तरीके से बाजरे की खरीद की जाये ताकि जो पश्चिमी राजस्थान के किसान हैं उनको लाभ भी होगा और मैं यह आश्वस्त होकर कह सकता हूं कि यह जो बाजरा है इसको हम हमारे अन्नपूर्णा की 25 हजार से अधिक दुकानें हैं वहां पर इसको बेच भी सकते हैं, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अभी कृषि बजट में घोषणा की गयी है कि 25 हजार फार्म पोण्ड्स और 10 हजार डिग्गियों का निर्माण किया जायेगा। इसके बारे में मेरा आग्रह रहेगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी, कि अभी हम जिन किसानों को लाभांवित करना चाहते हैं उनको हम लॉटरी के माध्यम से करते हैं, जब लॉटरी के माध्यम से करते हैं तो कोई गारंटी नहीं रहती कि हर व्यक्ति का इसमें नम्बर आयेगा, तो मेरा इसमें आग्रह है कि इसमें पहले आओ और पहले पाओ, यह नीति रखनी चाहिए। हमारी सब योजनाओं में यही नीति है क्योंकि इसके अन्दर कई ऐसे किसान है जिन्होंने अप्लाई कर रखा है लेकिन उनका नम्बर नहीं आता है।

श्री सभापति: विराजें।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बजट से डेगाना की जनता बहुत खुश है और मेरा जो क्षेत्र है वो पूरा कृषि पर आधारित है और इस बजट में सभी विधान सभा क्षेत्रों में कुछ न कुछ हुआ है। मैं सबके लिए कहना चाहता

हूं,

'अगर सब कुछ मिल जायेगा
तो तमन्ना किसकी करोगे,
कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो हैं
जो जिन्दगी जीने का मजा देती है।'

जय-जय डेगाना, जय-जय राजस्थान।

MLS/RTM/25.02.2025/14:50/2h

श्री सभापतिः श्री ताराचन्द जैन। (अनुपस्थित) श्री विक्रम सिंह जाखल।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, 2025-26 में राज्य की इस जन कल्याणकारी सरकार का, माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा व माननीया वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस प्रदेश की जनता के प्रत्येक वर्ग के हितों को केन्द्र में रखकर एक ऐसा शानदार बजट प्रस्तुत किया, जो राइजिंग राजस्थान के आयोजन के बाद ऐसा ग्रीन थीम बजट होगा, जो राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

सभापति महोदय, आपका ध्यान पिछली गहलोत सरकार के द्वारा किये गये राजनीतिक भ्रष्टाचार की ओर ले जाना चाहूंगा। जिस सरकार को विधान सभा और मंत्रालय से चलना था, वह सरकार होटलों से चल रही थी। इससे बड़ा अपमान लोकतंत्र का नहीं हो सकता, लेकिन आप आज सदन चलाने में रोड़ा अटका रहे हैं, यह राजस्थान की 8 करोड़ जनता देख रही है। देश में बीजेपी सरकार का उद्देश्य है राष्ट्र के प्रति समर्पण, परन्तु कांग्रेस सरकार का आजादी से ही उद्देश्य रहा है संसाधनों का अतिक्रमण करना और अपहरण करना। पिछली सरकार एक फेल्ड गवर्नमेंट थी। वह इस हद तक आ गयी कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत थी।

पिछली सरकार द्वारा किये गये नीतिगत भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीति, जिसमें अन्त्योदय के बारे में सोचा जाता है। कई बरसों से मेरे नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ट्रोमा सेंटर को लेकर, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, देश आजाद होने के बाद पहली बार कमल का फूल नवलगढ़ की जनता ने खिलाकर भेजा है। 76 साल में कभी भी जनता को अवसर नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास करवाने का। राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी और आदरणीया वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने पहला बजट जब नवलगढ़ को दिया तो नवलगढ़ की जनता ने पहली बार यह तय किया कि हम कभी किसी राज में शामिल हुए हैं।

मैं मुख्य मंत्री जी के 2023-24 के बजट और 2025-26 के बजट को लेकर बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे यहां नवलगढ़ में सबसे बड़ी समस्या ट्रोमा सैंटर की थी, जो हमें इस 2025-26 के बजट में दिया गया है। ट्रोमा सैंटर नवलगढ़, मण्डावा, लक्ष्मणगढ़ और उदयपुरवाटी में भी नहीं हैं। आसपास का हमारा पूरा क्षेत्र राज्य के स्टेट हाइवे से लगता है और लगातार एक्सीडेंट्स होते हैं। उन लोगों को हम लोग नवलगढ़ से झुंझुनूं, सीकर, जयपुर तक लाते हैं। आज हमें इतनी बड़ी सौगात इस सरकार की तरफ से, मुख्य मंत्री जी की तरफ से, आदरणीया वित्त मंत्री दिया कुमारी जी की तरफ से मिली है।

मैं उनका दिल की गहराई से बिजली की समस्या को लेकर धन्यवाद करते हुए यह कहना चाहूंगा कि पिछले पांच साल की सरकार में सदैव बिजली गुल रही। 2018 से लेकर 2023 तक लगातार बिजली को लेकर यह समस्या रही, आन्दोलन रहे, लोग रोड पर आ जाते थे। आज हमारी मांग पर, पहली बार, जब हम बच्चे थे तब यह देखते थे, एक छोटे-से पावर हाउस के लिए झुंझुनूं तक लोग सांसद के पास, सरकार के लोगों के पास, 10-10, 20-20 बार सालों-साल जाते थे, तब जाकर एक छोटा-सा पावर हाउस दिया जाता था। मैंने अपने गांव के लिए 132 केवी जीएसएस की मांग की थी। आदरणीय मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और हमारे नागर जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने 132 का जीएसएस जाखल को दिया और 33/11 केवी का सब-स्टेशन हमारे मुकुंदगढ़ को दिया, नवलगढ़ की बिजली की समस्या खत्म की। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।

पिछले समय से नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की, आज जो विशेष परिस्थिति में जहां नवलगढ़ खड़ा है, वहां की बताना चाहूंगा, क्योंकि नवलगढ़ की बाजू में झुंझुनूं, इधर सीकर, नवलगढ़ एक अपराधियों का गढ़ बना हुआ था और पिछली सरकार के पूर्व विधायक ने लगातार इतने गलत काम करवाये उन अपराधियों से कि आज भी वे नवलगढ़ का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं।

सभापति महोदय, मैंने पिछले समय में कहा था, पिछली बार भी इस विधान सभा में आपके माध्यम से एक मांग उठायी थी कि नवलगढ़ को एक थाने की सख्त आवश्यकता है देवपुरा बणी में। देवपुरा बणी थाने की बजट में घोषणा हुई थी। उसके बाद से अभी तक वह चालू नहीं हुआ। उसकी वजह से आज हमारे अध्यक्ष महोदय जी कह रहे थे कि उदयपुरवाटी के विधायक भगवाना राम जी सैनी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो घटना हुई, उसे लेकर एक चर्चा का विषय भी रखा था।

मैं आज यह कहना चाहूंगा, ये उसी कांग्रेस के टाइम के अपराधी, जिन्हें कांग्रेस के विधायक संरक्षण देते थे, वे ही पनपाये हुए हैं। एक साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में ये अपराधी नहीं पनपे हैं। अपराधियों के पनपने का मतलब लोहार्गल एरिया के जितने भी पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को तोड़ा गया और लोहार्गल से लेकर उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र तक नदियों को चीरा गया, ऐसे कांग्रेस के समय में विधायक और मंत्री होते थे।

सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं

रोजाना होती हैं। पिक-अप और कैम्परों में भरकर आते हैं वे लोग और लगातार हमले करते हैं, जिनके सामने पिछली बार हमारी राजस्व की टीम, पुलिस की टीम और हमारे वन विभाग की टीम ने मिलकर वन विभाग के अधिकारी अमित सैनी पर हमला किया गया था। यह जानलेवा हमला उन्हीं अपराधियों की वजह से, उन्हीं हिस्ट्रीशीटरों की वजह से हुआ था, जिनकी वजह से हमारे अधिकारी लोग उन पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं जा सकते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, आप देवपुरा बणी के थाने की पिछली घोषणा का लगातार ध्यान रखते हुए उसे पूरा करवाएं ताकि वहां अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम हो।

इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है, आज के दिन पानी की समस्या को लेकर, पूरे विधान सभा क्षेत्र में 100 ट्यूबवैल्स सूख चुके हैं। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी तरफ से यह मांग है कि पूरे प्रदेश को 1000 ट्यूबवैल्स दिये गये हैं, 1500 हैंडपम्प्स दिये गये हैं तो मैं सबकी तरफ से यह मांग करूंगा कि 1000 की जगह 2000 ट्यूबवैल्स होने चाहिये ताकि पूरे प्रदेश की समस्या खत्म हो, क्योंकि आने वाले गर्मी के समय में हम लोगों की जो समस्या है, वह सीधी जनता से जुडी हुई समस्या है पानी की।

हर विधान सभा क्षेत्र में परिस्थिति हर जिले की, हर विधान सभा की अलग-अलग है। मैं अपने नवलगढ़ का बता सकता हूं, जिसके अन्दर कम से कम 100 ट्यूबवैल्स की आवश्यकता है आज के दिन। वहां हमारे हैंडपम्प्स कोई काम नहीं करते हैं। सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र में बहुत बड़ा बजट देकर हम लोगों को आपने जो आशीर्वाद दिया है, उसका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए यह कहना चाहूंगा, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को मिलने वाली राशि 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये करने से किसानों की ताकत बढ़ेगी।

किसान इस बात को भी समझते हैं कि पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किसानों को सिवाय धोखे के कुछ नहीं दिया। अभी तो हमने जब वादा किया था और वादे के बद दूसरा बजट है, जब तक हमारी सरकार के पांच साल होंगे, तब तक किसानों को कितना लाभ मिल जायेगा। मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही यह कहना चाहूंगा, गत सरकार के मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड योजना से मिलने वाले तेल, मसालों के पैकेट गुणवत्ता के मामले में इतने खराब किस्म के साबित हुए कि जनता ने इस सामग्री को उपयोग में लेना तो दूर की बात, घर में रखना भी उचित नहीं समझा। सभापति महोदय, ऐसी फूड योजना जनता के लिए फूहड़ योजना साबित हुई।

MKD/RTM/25.02.2025/15:00/2j

हमारी सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नये परिवारों को जोड़ने की घोषणा, एक सराहनीय कदम है। जिससे गरीब तबके के लोग भी मुख्य धारा से जुड सकेंगे। सभापति महोदय, ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों के संरक्षण हेतु शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना एवं

हैरिटेज की घोषणा करने से नवलगढ़ शहर में स्थित हवेलियों को संरक्षण प्राप्त होगा, पर्यटन के क्षेत्र में भरपूर अवसर पैदा होंगे।

मैं मुख्य मंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिले में पंच गौरव जो लिये हैं, राजस्थान के हर जिले में, उनमें हमारे लोहार्गल पर्यटन स्थल को लिया है। उसके लिए मैं हृदय की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापतिः विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): सभापति महोदय, 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग चलने-फिरने में असमर्थ होते हैं, इस हेतु दवा आपके द्वार में घर पर दवा उपलब्ध कराने की घोषणा से बुजुर्गों के स्वास्थ्य में तेजी आयेगी। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री देवी सिंह शेखावत। कृपया, समय-सीमा में बोलने का प्रयास करें। बोलने वाले वक्ता बहुत हैं तो अपनी सीमा में ही अपनी बात कहें। बोलने वाले वक्ता बहुत हैं, फिर भी 11 बजेंगे रात के।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के बजट 2025-26 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भजन लाल जी सरकार ने केवल एक साल में जो कार्य किये हैं और उनके प्रेरणादायी सानिध्य में जो बजट हमारी प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने पेश किया, वह लाजवाब बजट है।

इसमें पूरे राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह मजबूत हो, इस पर विशेष ध्यान दिया। हमारा पांच साल का कार्यकाल होता है। इसमें किस तरह से सारे कार्य कर सकें। इसके लिए जो दृढ़ संकल्प शक्ति भजन लाल जी की है, वह परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है।

अपने पहले ही कार्यकाल में जो हमारी अटकी हुई परियाजनाएं, हमारा जो क्षेत्रफल है, वह पूरे इंडिया का 10.4 प्रतिशत है और हमारे पास जल 1 प्रतिशत है। मुख्य मंत्री जी ने सबसे पहले पानी की आवश्यकता को महसूस करते हुए, अपने कार्यकाल के शुरुआती महीने में ही राम जल सेतु लिंक का कार्य किया। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को यह लगता था कि यह कार्य हो नहीं पायेगा। उसके 9 हजार 54 करोड़ के कार्यादेश जारी जो चुके हैं, 12 हजार करोड़ की निविदाएं जारी हो चुकी हैं, 12 हजार करोड़ की निविदाएं स्वीकृति में हैं और बहुत तेजी से काम हो रहा है।

हमें याद आता है कि बचपन में रामगढ़ में 1983 में नौकायन प्रतियोगिता हुई थी। पूरे जयपुरवासी उसी के पानी पर निर्भर थे। एक बार फिर लगता है कि रामगढ़ के बंधे में पानी आयेगा और उसके नीचे के क्षेत्र जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं, सरसब्ज होंगे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहां छितोली बांध का बहुत ज्यादा प्रभाव, हमारे क्षेत्र के सतही जल पर पड़ता है, उसमें पानी आयेगा। बाकी साबी नदी है, उसमें यह जल छोड़ा जायेगा। 17 जिलों की तीन करोड़ आबादी को न केवल पीने का, 4 लाख हैक्टेयर जमीन को संचित करने का भी मौका मिलेगा।

राजस्थान के न केवल पूर्वी हिस्से का बल्कि चाहे हमारा हाड़ौती हो, चाहे हमारा मेवाड़ हो, चाहे हमारा मारवाड़ हो, हर जगह पानी पर विशेष ध्यान देते हुए राजस्थान के सपने को पूरा करने के लिए, किसानों को विकास करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।

हमारा सारा परिवेश ग्रामीण है। आने वाला समय जिस तरह, देश-दुनिया में और राजस्थान में भी कैंसर जैसी भयावह बीमारी बढ़ रही है। गेहूं से बहुत से लोगों को एलर्जी हो रही है और यह हमारा मुख्य खाद्यान्न है। हमारे प्रधान मंत्री बार-बार मोटे अनाज के लिए सभी से आह्वान करते हैं। यह प्रकृति की मेहरबानी है कि एक बहुत-बड़ा भू-भाग हमारे पास है। इस पर हम मिलेट्स का उत्पादन करेंगे और पूरे भारत में आज भी हम पहले नम्बर पर हैं। मिलेट्स का उत्पादन होगा, हमारे किसानों की स्थिति बहुत अच्छी होगी। पानी से हमारे किसान बहुत समृद्ध होंगे। हमारे सौर ऊर्जा का प्लान, प्रधान मंत्री जी ने सपना देखा और घर-घर पूरे देश में सात करोड़ शौचालय बने, ऐसा लगता था कि इतने शौचालय कैसे बन सकते हैं। प्रधान मंत्री जी ने 14 करोड़ से ज्यादा जन-धन खाते खोले। वैसे ही प्रधान मंत्री जी की घर-घर सौर ऊर्जा लाने की योजना है। इसमें मुख्य मंत्री जी सबसे अगुआ बने हुए हैं और राजस्थान को उन्होंने देश में एक नम्बर बनाया हुआ है। अपनी तरफ से सब्सिडी भी दे रहे हैं।

अब सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारे पास जमीन होनी चाहिए, जो प्राकृतिक रूप से राजस्थान में बहुत ज्यादा है। यहां का किसान सौर ऊर्जा के प्लांट लगाकर बहुत ही समृद्ध होगा। यह सौर ऊर्जा अग्नि का भी प्रतीक है और ताकत का भी प्रतीक है। साथ ही, यह हमारी आर्थिक प्रगति का बड़ा मील का पत्थर होगा।

राइजिंग राजस्थान के माध्यम से, जैसा हमारी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की, उन्होंने सवा लाख सरकारी नौकरी और डेढ़ लाख जॉब प्राइवेट सेक्टर में सुनिश्चित किये हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई संदेह होगा, क्योंकि राइजिंग राजस्थान में 35 हमारे विदेशी पड़ौसी मुल्कों ने भाग लिया, जो यहां इंवेस्ट करना चाहते थे। उनके साथ ही 16 हमारे और मुल्क थे, उन्होंने भी भाग लिया। 147 एक्जीबिटर आये, 32 हजार डेलीगेट और हमारे स्थानीय लोग थे। सभी उद्योग लगाने के लिए संकल्पित थे। राइजिंग राजस्थान के अन्तर्गत आज तक 1 लाख 75 हजार करोड़ के कार्य धरातल पर उतर चुके हैं। ये कार्य बगैर लोगों के सम्भव नहीं होंगे और इसमें डेढ़ लाख लोगों को, 35 लाख करोड़ के जो हमारे कार्य हैं, वे पूरे होते-होते डेढ़ लाख लोगों को रोजगार अवश्यम्भावी मिलेगा। हमारी समृद्धि आयेगी।

मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की भी कुछ बातें रखना चाहूंगा। बानसूर में भी औद्योगिक विकास की बहुत सम्भावनाएं हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, वित्त मंत्री जी से करना चाहूंगा, हमारे उद्योग मंत्री जी से करना चाहूंगा कि वहां उद्योग लाकर हमारे स्थानीय युवाओं के लिए और क्षेत्र को भी समृद्ध करने के लिए प्रयास करें। हमारा नया जिला कोटपूतली बना है। नये जिले में हमारा जो डीजे कार्यालय है, वह उस क्षेत्र को देखते हुए,

व्यवहारिकता को देखते हुए, प्राकृतिक न्याय को देखते हुए, कोटपूतली हमारे सेंटर में पड़ता है, बहरोड़, बानसूर और विराटनगर के बीच में है, वहां डीजे कार्यालय खुले। यह हम सभी लोगों की इच्छा है। वहां के 80 प्रतिशत लोगों की इच्छा है। साथ ही, हमारे नीमूचाणा से कोटपूतली पहले एक सीधी सड़क जाती थी, वह कच्चा रूट था, वहां बड़ी रोड़ बने, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा।

मेरे वहां उप खण्ड कार्यालय नारायणपुर है। मैंने वहां मुंसिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय की मांग की थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वह कार्य पूरा होगा। बानसूर में चालीस हजार की आबादी रहती है, लेकिन वहां लोगों के घूमने-फिरने के लिए स्टेडियम और पार्क की बहुत कमी है तो स्टेडियम बने, पार्क बने।

साथ ही, वहां बस स्टैंड की भी कमी है, नारायणपुर में भी की है तो वह बने। हरसौरा हमारा बड़ा कस्बा है, उस कस्बे में तहसील बने, ऐसी वहां के क्षेत्र की लोगों की और सभी की सुविधा के लिए बहुत ही आवश्यक है।

हमारा कराणा एक और बड़ा कस्बा है। उस कस्बे में उप तहसील का कार्यालय खुले। ऐसी हमारे क्षेत्र के सभी लोगों की क्षेत्र के विकास के लिए यह बहुत ही जरूरी मांग है।

Bhs/Rtm/25.02.25/15.10/2k

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नाथूसर, लोझ ऐसे गांव हैं जो सरिस्का में आने के कारण विस्थापित हो रहे हैं। उन लोगों की यह इच्छा है कि वो कोटपूतली, बानसूर से बाहर नहीं जायें, अन्य लोगों को तिजारा जमीन दी गई है, वे व्यावहारिक रूप से वहां कटा हुआ महसूस करते हैं तो मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि उन लोगों को कोटपूतली में या बानसूर में जहां पानी हो, वहां जगह उपलब्ध करायी जाये।

सभी पंचायतों में ओर मेरी दोनों नगरपालिकाओं में गन्दे पानी की निकासी की बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं पंचायती राज मंत्री जी और हमारे आदरणीय झाबर जी खर्रा साहब यहां विराजे हैं, इनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो सड़कें हैं वो गन्दे पानी के निकास सही नहीं होने की वजह से, लोगों का सिविक सेंस कम होने की वजह से चाहे पंचायत स्तर हो, चाहे नगरपालिका स्तर हो लोग पानी खुला छोड़ते हैं, सड़कें करोड़ों की लागत की खराब हो जाती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था हो तो ही हमारी सड़कें चलेंगी और हमारा विकास हो पायेगा। हमारी महिला और सभी सुरक्षित रहें इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज अपराधियों के मन में भय है। पुलिस अपराधियों को कोई मौका नहीं दे रही है उलटे उनको जाकर सावचेत कर रही है कि कोई भी बदमाशी करने की कोशिश की जायेगी तो उन्हें घर से उठा लिया जायेगा और जनता को आतंकित करने का लाइसेंस जिस तरह पिछली सरकार में उनको मिला हुआ था इस सरकार में बिलकुल नहीं रहेगा। मेरा बानसूर क्षेत्र एक अवैध

हथियारों का अड्डा बन गया था। मुझे खुशी है, मैं मुख्य मंत्री जी को साथ में आई.जी. साहब को, एस.पी. साहब को, मेरे सभी थानाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने अपराध पर लगाम पाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री ताराचन्द जैन।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सभापति महोदय, दोनों टी वी बन्द हो गये हैं।

श्री सभापतिः हां, ये दिखवाना एक बार।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का यह बजट विकसित भारत 2047 की आधारशिला रखने वाला बजट होगा। इसमें सभी वर्ग किसान हो या मजदूर, युवा हो या मध्यम वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का बजट होगा। वैसे मुझे आज भी वो लाइनें स्मरण में गूंज रही है कि इसी जयपुर शहर में राहुल गांधी 2017-18 में आये थे और उस समय उन्होंने एक लाइन बोली थी किसानों के लिए। एक ओर वसुन्धरा राजे जी जब मुख्य मंत्री थी तो उन्होंने कहा कि पचास हजार तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उन्होंने अपने काल खण्ड में ही पचास हजार तक का कर्जा माफ करके उसका सर्टिफिकेट दिया। दूसरी ओर राहुल गांधी जब आये और उन्होंने घोषणा की थी कि एक, दो, तीन, चार, नौ, दस, कर्जा माफ, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का कर्जा माफ होने की बजाय किसानों की जमीनें कुर्क हुईं। यह इस बजट में आजादी के इतिहास में जितना पैसा किसानों के लिए दिया गया है वह ऐतिहासिक होगा।

किसानों को केन्द्र सरकार 6 हजार रुपये सम्मान निधि देती है। पिछले बजट में दो हजार रुपये राजस्थान सरकार ने दिया। उसी के साथ इस साल एक हजार की और बढ़ोतरी करके और 9 हजार रुपये किसानों को एक सम्मान निधि बढ़ा कर एक सम्मान दिया है। गेहूं के उत्पादन में प्रति क्विंटल बोनस राशि बढ़ा कर डेढ़ सौ रुपये प्रति क्विंटल दी है। निश्चित रूप से किसानों को बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण, 35 लाख से अधिक किसानों को ऋण वितरित किया जायेगा, इसलिये किसानों की माली हालत में सुधार होगा।

किसानों की फसल नील गाय या आवारा पशुओं से नष्ट होती है उन जंगली जानवरों के नुकसान से बचाव हेतु 75 हजार किसानों को 30 हजार किलोमीटर लम्बी तारबन्दी हेतु 325 करोड़ रुपये का तारबन्दी के लिए बजट दिया है यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है।

पांच हजार किसानों को उन्नत खेती के प्रशिक्षण हेतु राजस्थान से बाहर एवं सौ किसानों को इजराइल, विश्व की सबसे उन्नत कृषि अगर है तो इजराइल है जहां पानी कम है, वैसी पद्धति सीखने के लिए किसान अगर जायेगा तो निश्चित रूप से इस राजस्थान के अन्दर

मील का पत्थर उत्पादन में साबित होगा। तीन लाख पचास हजार हेक्टेयर सिंचाई योजना में बारह सौ करोड़ रुपये व्यय किया जायेगा और उसके साथ-साथ जो पानी की तीन योजनाएं इस बजट में स्वीकृत होकर भले लिंक योजना, यमुना लिंक योजना, कालीसिंध योजना हमारे उदयपुर सम्भाग की जाखम से जयसमन्द जोड़ने वाली और उदयपुर देवास चौथी, इन चारों योजनाओं से राजस्थान, मेवाड़ ही नहीं सारा राजस्थान पिछले तीस-चालीस वर्षों से पानी की समस्या से निजात पायेगा यह निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के लिए यह सरकार धन्यवाद की पात्र है।

तीन लाख पच्चीस हजार फार्म पोंड, दस हजार डिग्गियों और पचास हजार सौर ऊर्जा संयंत्रों से बीस हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप की लाइन से 9 सौ करोड़ रुपये का जो अनुदान दिया है निश्चित रूप से किसान जहां भी जाओ, किसान इस बात को महसूस करता है कि यह सरकार किसानों के हित के कई कदम उठा रही है। यह सराहनीय है। पचास हजार नये कृषि कनेक्शन लघु सीमान्त कृषकों को दिये जायेंगे। उसके साथ-साथ अब हम देख रहे हैं कि बैलों की अनुपयोगिता बढ़ती जा रही है। किसान जो भार मान रहा था उन बैलों को, उनके लिए सरकार ने अपने बजट के अन्दर तीस हजार रुपये, एक बैल जोड़ी के ऊपर अगर किसान बैल से खेती करेगा तो तीस हजार रुपये का अनुदान देंगे। इससे निश्चित रूप से अब एक तरह से बैलों की भी रक्षा होगी और किसान को भी तीस हजार रुपये से राहत मिलेगी। इन घोषणाओं से किसानों को सम्बल मिलेगा। यह योजना किसान के लिए बहुत हितकारी साबित होगी।

इसके साथ ही राजस्थान सरकार पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नि:शुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को नि:शुल्क सोलर प्लांट लगाते हुए डेढ़ सौ यूनिट बिजली प्रति माह फ्री दी जायेगी। यह भी सरकार का सराहनीय कदम है। अल्प आय वर्ग परिवारों को रोजमर्रा की आवश्यकता हेतु पांच हजार उचित मूल्य की दुकानों का अन्नपूर्णा भण्डार रहेगा। साथ में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के 6 हजार वरिष्ठजनों को हवाई यात्रा, ऐसे में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिन 6 हजार हवाई यात्रियों को यात्रा दी जायेगी उनमें से कई तो जीवन में पहली बार हवाई यात्रा करेंगे तो यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और साथ में पचास हजार वरिष्ठजन को ए.सी. ट्रेन से तीर्थयात्रा करवायी जायेगी। यह निश्चित रूप से जन हितकारी, लोक कल्याणकारी योजना है।

पांच सौ रोडवेज बसें कांग्रेस के राज में मरणासन्न अवस्था में हो गई हैं, पांच सौ बसें नयी एवं जी.सी.सी. मॉडल पर पांच सौ, एक हजार बसों से मरणासन्न रोडवेज को नया जीवनदान मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाएं बढ़ेगी। यह निश्चित रूप से सरकार बधाई की पात्र है।

युवा बेरोजगारों की भर्ती - कांग्रेस के लोग रोज चिल्लाते हैं कि भर्ती कब करोगे, मेरा अन्दाज है कि साठ-सत्तर हजार तो भर्तियां कर दी हैं। एक लाख पच्चीस हजार की तो सरकार ने विभिन्न पदों पर भर्तियों की घोषणा की है। एक लाख पच्चीस हजार निजी क्षेत्र

में, इस वर्ष मैं कई रोजगार मेलों के अन्दर गया था, वहां बड़ी-बड़ी कम्पनियों के मेले लगे थे। उन मेलों के अन्दर नौजवान युवक जो टैक्निकल है उनको कइयों को रोजगार मिला और निश्चित रूप से पौने तीन लाख भर्तियों से युवाओं को रोजगार मिलेगा और केवल भर्तियों की घोषणा नहीं की उसके साथ-साथ तारीख का कलेन्डर जारी कर दिया है तो उससे भर्तियों की प्रक्रिया को सम्बल मिलेगा। 35 हजार छात्रों को स्कूटी देने में शिक्षा क्षेत्र में बेटियों को सुगमता और नयी ऊर्जा प्राप्त होगी। छात्राओं को आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए प्रत्येक भाग में एक उच्च शिक्षा महाविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केन्द्र स्थापित किये जाने से छात्राएं अपनी आत्म रक्षा के गुर सीखेंगी।

पच्चीस हजार पंचायतों में जी.एस.एस. लगेगा। इससे निश्चित रूप से बिजली आपूर्ति के अन्दर एक राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांव ऐसे हैं जहां जी.एस.एस. नहीं हैं। इस वर्ष पच्चीस हजार पंचायतों को एकमुश्त जी.एस.एस. देकर इस बिजली के अन्दर राहत दी जायेगी।

मिशन हरियाली के अन्तर्गत राजस्थान में दस करोड़ पौधे लगाये जायेंगे। हमारे उदयपुर शहर में जैसा कि नवरत्न कॉम्प्लेक्स में सीवरेज पाइप लाइन के कनेक्शन दिये जायेंगे। मेरा अन्दाज है उदयपुर शहर एक ऐसा शहर होगा कि जिसके अन्दर पहले नरेन्द्र मोदी जी ने बीस शहरों में स्मार्ट सिटी घोषित की थी, ...

Kas/rtm/25.02.2025/15.20/2l

पिछले पांच सालों में स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो गई है। उदयपुर पहले 50 परसेंट सीवरेज से जुड़ा हुआ था, अब यह 25 परसेंट पार्ट और जुड़ जाने से मेरा अंदाज है कि उदयपुर को आगामी एक-दो वर्षों में नालियों की गंदगी से मुक्ति मिलेगी। पर्यटन में हैरिटेज कमांड सेंटर एवं बाघ प्रबंधन सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे।

अंत में मैं दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड और पिछले साल एक एस सी के बालक की नृशंस हत्या कर दी गई, उससे सारा देश विचलित हुआ। इसमें दोनों ही असामाजिक तत्व जो एक समुदाय विशेष के थे, उन्होंने टार्गेट करके यह हत्या की है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से शहर में दो सेंसेटिव क्षेत्र है, एक तो है आयड़ और दूसरा है खालिबी, इन दोनों क्षेत्रों की चौकियों को थाने में क्रमोन्नत करने की मैं मांग करता हूं। हमारे उदयपुर शहर में पहले 50 बीघा जमीन में न्यायालय खोलने के लिये जमीन आवंटित की गई है और उसकी बाउंड्री भी बनी है। वहां शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा है, एक ओर हॉस्पिटल है, सामने कोर्ट है, इधर एस.पी. ऑफिस है और इधर कलेक्ट्री है, इन चारों का सेंटर कलेक्ट्रेट चौराहा है। अगर इस कोर्ट के लिये 10-15 करोड़ भी दे दिये जाये और काम स्टार्ट हो जाये तो न्यायालय हाईवे पर चला जायेगा और इससे बाहर से आने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी और शहर को भी एक राहत मिलेगी। मैं सरकार से मांग करूंगा कि कुछ राशि इसमें आवंटित करें। इस तरह से इन

दोनों मांगों के लिये मैंने आपसे निवेदन किया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आज बजट पर चर्चा हो रही है, विपक्ष यहां पर है नहीं। उन्होंने इस बजट पर और पूर्व बजट पर जो कहा है, जनता ने उनको जवाब देकर उप चुनाव में बता दिया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने यह कहा था कि हमको एक पैसा नहीं दिया, जीरो-जीरो की घोषणा करने वालों को बताना चाहता हूं कि हमारी वित्त मंत्री महोदया द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह हर वर्ग को राहत देने वाला है। इस जन कल्याणकारी बजट में गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिला, युवा, बुजुर्ग और बच्चों के कल्याण की सोच दिखाई देती है। प्रदेश के आमजन की भलाई वाला बजट पेश करने हेतु मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय भजन लाल शर्मा जी और सरकार की वित्त मंत्री महोदया दिया कुमारी जी का मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से कोटि-कोटि आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, पूर्व की सरकार ने हमको विकास पथ का जो असत्य झुनझुना पकड़ाया था, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में हर पंचायत में विकास पथ बनाने की बात की थी, मगर एक किलोमीटर या एक करनी भी विकास पथ के नाम पर नहीं लगी। हमने गौरव पथ बनाया था, उसको आज भी जनता सराहती है। कीचड़ में जनता जाती थी, महिला बहने उस में पैदल आ-जा नहीं सकती थी, उसको आज भी सराहते हैं। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार आई, उन्होंने अटल विकास पथ देकर हमारे उस गौरव पथ को वापस उजागर किया। पूर्व सरकार ने हर पंचायत पर नंदी गौशाला खोलने का वादा किया था, वह भी गौण निकला और वह पंचायत छोड़, मेरी किसी पंचायत समिति में भी नहीं खुली। मेरे यहां तीन पंचायत समितियां हैं, एक में भी नंदी गौशाला नहीं खोली।

सभापति महोदय, पेपर लीक की मैं क्या बात करूं, हमारे किसान, गरीब आदिवासी ने अपने बच्चे को नौकरी लगाने के लिये बच्चे को शहर में कमरा दिलाया, ट्यूशन करवाई, पैसे नहीं है तो ब्याज पर लाता है, जेवर गिरवी रखता है और उस बच्चे को कंपीटिशन के लिये तैयारी करवाता है और बच्चा परीक्षा देकर आता है और पेपर लीक हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह गरीब न घर का रहा न घाट का।

सभापति महोदय, किसानों के कर्ज माफी की बात कही गई। कर्जा माफी की थोथी घोषणा करके हमारे किसानों के साथ छलावा किया। हजारों किसानों ने कर्जा माफी के चक्कर में किश्तें जमा नहीं करवाई और उनकी जमीन नीलाम हुई। इन्होंने कहा था कि तीन-तीन हजार रुपये हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। मगर एक पैसा भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में बेरोजगारी भत्ते का नहीं दिया गया।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार के जल जीवन मिशन के पैसे का केवल और केवल दुरुपयोग किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2018 के पहले की टंकियां भी चालू नहीं हुईं।

जो काम चालू करके छोड़ दिये, उसका भी विकास नहीं हुआ। मैं हमारे जल जीवन मिशन के मंत्री और सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार आई, वैसे ही इस काम में तेजी लाए। आज वह काम भी शुरू हो गया है और बाकी पर भी संज्ञान लेकर काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, पूर्व सरकार ने पट्टे देने की बात की थी, गरीब आदमी आस लगा कर बैठा था कि हमको पट्टे देंगे, मगर पट्टे के नाम पर केवल और केवल छलावे का काम किया है। हमारे मुख्य मंत्री जी और केन्द्र सरकार के माध्यम से 600 से ज्यादा घुमंतू परिवारों को पट्टे देकर इस सरकार ने हमको राहत दी है। सभापति महोदय, मेरे से पहले वक्ता हमारी दीप्ति माहेश्वरी जी ने कहा कि मोबाइल का झुनझुना पकड़ाया और इसमें इन्होंने नाम मात्र का काम किया और इसमें इन्होंने केवल कुछ जगह मोबाइल दिये।

सभापति महोदय, मैं इस बजट के कुछ खास बिन्दुओं को कविता के रूप में सामने रखना चाहता हूं।

दिया जी के बजट ने सबको दिया है मान,
बजट देख सब बोल पड़े, जय-जय राजस्थान।
भजन सरकार ने दिया है महिलाओं को सम्मान,
20 लाख लखपति दीदी, जय-जय राजस्थान।
युवा सारे खुश हैं, निकली नौकरियों की खान,
रोजगार सबको मिला, जय-जय राजस्थान।
किसान सम्मान निधि बढ़ाकर किया किसानों का सम्मान,
हर घर खुशहाली आई, जय-जय राजस्थान।
गांव, गरीब और किसान का होगा अब कल्याण,
हर खेत को पानी मिले, जय-जय राजस्थान।
घुमंतू परिवारों को मिलेगा उनका मकान,
गरीब के सिर पर छत होगी, जय-जय राजस्थान।
ढाई लाख परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण का वरदान,
ग्रामीण विकास को आधार मिला, जय-जय राजस्थान।
शिक्षा और चिकित्सा की योजना चढ़ी परवान,
होगा सबका कायाकल्प, जय-जय राजस्थान।
जनहित के इस बजट में सबका रखा ध्यान,
यह भाजपा की भजन सरकार है, जय-जय राजस्थान।

Msk/rtm/25.02.25/1530/2m

सभापति महोदय, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन समय समाप्त होने की ओर है।

श्री सभापतिः ये सब आपसे कविता के माध्यम से आगे की बात सुनना चाहते हैं।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अब की बार पूरी लाऊंगा। सभापति महोदय, भारत रत्न अटल बिहारी जी वाजपेयी, भैरोसिंह जी शेखावत साहब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलते हुए लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय का संकल्प यह भाजपा सरकार कर रही है। नरेन्द्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने एक आदिवासी बहन द्रोपदी मुर्मू जी को देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर आसीन किया है। वहीं हमारे विपक्षी भाई ने उनके लिए अपशब्द बोलकर देश के संविधान का और जनजातियों का अपमान किया है। ये कहते हैं कि आदिवासियों का भला करेंगे, मगर हमारे आदिवासी परिवार की एक महिला को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च पद पर बिठाया, उसको भी ये हजम नहीं कर पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी को भी विदेश में सम्मान मिल रहा है।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी को विश्व के 20 से भी अधिक देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। जिससे हर भारतीय अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे विपक्षी साथी कुंठा से ग्रसित होकर राष्ट्र विरोधी जैसी हरकतें कर रहे हैं। सभापति महोदय, हमारे पराक्रमी प्रधानमंत्री जी ने चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटा दी। वहां शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाये। ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। मोदी जी और भजन लाल जी की जोड़ी देश और प्रदेश से भ्रष्टाचार का नामोनिशान मिटा रही है। मोदी जी के तेजस्वी नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष एक देश, एक चुनाव की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे युवा ऊर्जावान मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हम भी एक राज्य, एक चुनाव की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुके हैं। हमारी सरकार राजस्थान की आठ करोड़ जनता को जीवन्त देवता मानकर उनकी सेवा करने के लिए कटिबद्ध है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

'निभाई जिम्मेदारी, हर घर खुशहाली' की थीम पर हर पल विकास और कल्याण कार्य कर रही है। सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार ने पांच साल में 19 हजार से अधिक किसानों की जमीन को जो नीलाम करवायी, किसान कभी माफ नहीं करेंगे। हमारे मोदी जी से किसान निधि के माध्यम से जो 8 हजार रुपये मिल रहे थे, आज हमारे भजन लाल जी ने 9 हजार कर दिये। सभापति महोदय, मैं बोलना चाहता था, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री उदय लाल भडाणा।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी राजस्थान सरकार का जो बजट आया और जो पिछला बजट था, ऐसा बजट शायद राजस्थान के इतिहास में आज दिन तक कभी नहीं आया होगा। जो सरकारें जाती थीं, जाते हुए वक्त जो बजट देती थीं, वैसा बजट

राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार ने आते वक्त पहले ही साल में ऐसा बजट दिया और यह दूसरा बजट है, जिसमें सम्पूर्ण राजस्थान के विकास को गति मिले, ऐसा बजट भजन लाल जी और दिया कुमारी जी ने दिया है।

नरेन्द्र मोदी जी का सपना है 2047 में भारत विकसित बने। मोदी जी का जो सपना है, संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा। इन्होंने विकसित राजस्थान के लिए जो सपना देखा है और हर विधायक के माध्यम से, हर विधान सभा क्षेत्र के माध्यम से पूरे राजस्थान में जो नव निर्माण काम किया है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसा बजट दिया, वैसा बजट कभी नहीं दिया होगा।

अभी पिछले कुछ समय पहले राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जो 33 लाख करोड़ के बिजनस एमओयू हुए हैं, यह बहुत बड़ी बात है। 35 लाख करोड़ रुपये का व्यापार राजस्थान में आयेगा तो यहां के गरीब किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, काम-धंधा मिलेगा, व्यापार मिलेगा। विदेशों से भी व्यापारी वर्ग आया था और पूरे देश के हर राज्य के लोग यहां आये थे और एमओयू साइन किये थे। लेकिन जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार थी, वह एमओयू के नाम पर अपने मिलने वालों को जमीन अलाटमेंट करती थी। अपने मिलने वालों को खानों का अलॉटमेंट करती थी। अपने मिलने वालों को उद्योगों के लिए जमीनें अलॉट करती थी। ऐसा ही वाकया मेरे भीलवाड़ा में हुआ था। मैंने भी पिछली बार बोला था कि तीन-तीन रुपये महीने में भी जमीन अलॉटमेंट कर रखी है। 135 रुपये महीने में भी जमीन अलॉट कर रखी है। खुद जनप्रतिनिधि अपने दोस्त के नाम अलॉटमेंट करवाते थे। जनप्रतिनिधि ने 135 रुपये पर-डे के हिसाब से उद्योग में दोस्त के नाम पर करायी, फिर दोस्त को डरा-धमका कर उसको अपना रिसोर्ट बना लिया। ऐसा वे काम करते थे, लेकिन हमारी भजन लाल जी की सरकार ने टैक्सटाइल पार्क के लिए भीलवाड़ा में.. मैं केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा से संबंधित ही बात करूंगा।

भीलवाड़ा का टैक्सटाइल उद्योग पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में टैक्सटाइल नगरी के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा में सूटिंग का कपड़ा बनता है, वह पूरे भारत में अलग ही स्थान रखता है। राजस्थान सरकार की जो सौ दिन की कार्य योजना थी, उसमें शामिल करके भीलवाड़ा को टैक्सटाइल पार्क देने का काम किया और भीलवाड़ा को नये-नये उद्योग देने का काम किया। भीलवाड़ा और हमारा माण्डल विधान सभा क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, राजस्थान के अन्दर भीलवाड़ा का कैसे योगदान रहे, माण्डल का कैसे योगदान रहे, उसमें भी हमारा पूरा जिला एवं हमारी विधान सभा के सब लोग राजस्थान और भजन लाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।

राजस्थान के उद्योग को स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया? पिछली पूर्ववर्ती सरकार क्या करती थी? अपने मिलने वालों के नाम पर हरियाणा से बुला-बुलाकर जमीनें अलॉट करा दीं। मेरे भीलवाड़ा में एक जिंदल नाम से कंपनी है। 2008 में जब पूर्ववर्ती कांग्रेस

थी, तब उन्होंने अलॉटमेंट किया। सरकार का मकसद यह होता है कि अगर किसी उद्योग और कारखानें को वर्क दिया जाए तो लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, काम धंधा मिलेगा। इसके माध्यम से उद्योग/व्यापार लगाये जाते हैं, लेकिन उन्होंने 1258 बीघा जमीन उनके अलॉटमेंट की और आज भी उस कंपनी में 20 लोग भी ऑन रोल काम नहीं कर रहे हैं। सारे ठेके पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं के हैं। यूपी/बिहार के लोगों को लाकर कांट्रेक्ट/ठेका पद्धति पर काम दे रखा है। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि अगर हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, हमारे जिले के अन्दर जिनको खानें अलॉट की गयीं, जिनको फायदा दिया गया। फायदा इसलिए दिया गया कि यहां लोकल जनता के लिए, लोकल लोगों के लिए, लोकल व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध हो, उसके लिए काम किया था, लेकिन उसमें लोकल लोगों को व्यापार, रोजगार नहीं देकर दूसरे प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। ठेका पद्धति पर काम दिया जा रहा है। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार हमारे विधान सभा क्षेत्र की चरागाह भूमि, बिलानाम भूमि 1258 बीघा पर कब्जा किया, लोकल लोगों को रोजगार दिया जाए। पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं के अभी भी वहां ठेके चल रहे हैं और हमारा कोई कार्यकर्ता गया कि हमको रोजगार दिया जाए। जिस गांव में वह खनन क्षेत्र चल रहा है, उसी गांव का एक भाजपा कार्यकर्ता गया था, मेरे को भी रोजगार दिया जाये। उसके ऊपर गोली चला दी गयी। हरियाणा से बाउंसर लाकर वहां बैठा दिये गये। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे जो उद्योग हैं, उनको पाबंद करे कि लोकल स्तर के लोगों को रोजगार दिया जाये। राजस्थान सरकार यह कहती है कि जो क्षेत्रीय लोग हैं, उन लोगों को धंधा दिया जाये। पूर्ववर्ती सरकार ने जो घपले किये, घोटाले किये, जमीनों के बहुत सारे उलटे-सुलटे काम किये, पर हमारे भजनलाल जी की सरकार नये राजस्थान के निर्माण के लिए अच्छा काम कर रही है। सब लोग उनकी सराहना कर रहे हैं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर माण्डल विधान सभा क्षेत्र के 56 गांव यूआईटी पेरिफेरी में आते हैं। पेरिफेरी के अन्दर सारी चरागाह भूमि, बिलानाम भूमि और नगर विकास न्यास के नाम दर्ज हो चुकी है। बहुत सारे गांव के लोग हैं। मैं मेरा ही बताता हूं। मेरे खुद के गांव में 40 परसेंट लोग चरागाह भूमि में निवास करते हैं और मेरा खुद का भी घर चरागाह भूमि में है। मुझे मेरी खुद की कमी बताते हुए शर्म नहीं आती। मेरे गांव का सरपंच भी चरागाह में निवास करता है। अगर यह नगर निगम में जाता है तो मैं सरकार के माध्यम से मांग करता हूं कि जो हमारे पेराफेरी के गांव हैं, जो चरागाह में किसान बसता है, उसके लिए सरकार नीति नियम बनाकर, जो भी शुल्क होगा, किसान पट्टा बनाने के लिए तैयार है। सरकार के जितने नियम हैं, उन गरीब किसानों को भी पट्टा दिलाने का काम करे, मैं यह सदन के माध्यम से मांग करता हूं।

mdp/rtm/25.02.2025/15:40/2n

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार नया काम कर रही है।

पहले पूर्ववर्ती सरकार में, कांग्रेस की सरकार में चार बार लाइट आती थी। सुबह 6 बजे से दिन में 12 बजे, 12 बजे से शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे और रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे, चार वक्त किसानों को लाइट देते थे। हमारे भजन लाल जी की सरकार बनी और हीरालाल जी ऊर्जा मंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी, भजन लाल जी की सरकार आते ही इन्होंने लाइट को दो वक्त कर दिया। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक किसान को देंगे। ठंड के समय में पाला पड़ता था, बहुत सारे किसानों की ठंड के मारे मौत हो जाती थी। किसी को सांप, बिच्छू काटने से मौत हो जाती थी। भजन लाल जी की सरकार ने अच्छा काम किया। इस बजट में छोटे-बड़े ग्रिड मिलाकर 180 ग्रिड नये बनाकर किसानों को फायदा पहुंचाने का काम भजन लाल जी की सरकार ने किया। यह किसानों के लिए समर्पित सरकार है। किसानों का भला सोचने वाली सरकार है।

कुसुम योजना के माध्यम से सब्सिडी देकर किसानों को जोड़ने का काम कर रही है। 150 यूनिट बिजली फ्री राजस्थान सरकार किसानों को देने के लिए तैयार है। 50 हजार कृषि कनेक्शन एक साल में देने के लिए सरकार घोषणा कर चुकी है और 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए भी सरकार ने घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो घोषणा पत्र बनाया था, उस घोषणा पत्र के आधार पर 58 परसेंट कार्य पूर्ण हो चुके हैं। बाकी के कार्य भी अभी चार साल बाकी हैं, उनमें पूर्ण कर लेगी और 100 परसेंट कार्य पूर्ण करेगी। पिछले बजट के अन्दर सरकार ने जो भी घोषणाएं की थी, जो भी वादे किये थे, उनमें 73 परसेंट काम चालू हो गया। उसके अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने भी बहुत सारे काम मांगे थे। हमारे को भी काम दिया था। धुआला से लगाकार भादू तक रोड का काम मांगा था 7 मीटर का, वह काम चालू हो गया है। हरिपुरा चौराहे से लगाकर देवगढ़ तक फोरलेन की मांग की थी। उसकी भी डी.पी.आर. बन चुकी है और बहुत जल्द हाइवे का काम भी फोरलेन का हो जाएगा।

सभापति जी, मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उस हाइवे को हरिपुरा चौराहे से थोड़ा 10-12 किलोमीटर बढ़ाते हुए लांबिया टोल तक किया जाए, क्योंकि वह विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में आता है। मैंने सी.एम.साहब से भी बात की थी। अगर लांबिया टोल तक होता है तो सीधा देवगढ़ चला जाएगा और वहां से 40-45 किलोमीटर का एक चक्कर कम पड़ेगा। आने-जाने वाले हर व्यक्ति को उसका फायदा होगा।

इसी तरह ई.आर.सी.पी. की तर्ज पर जो राम जल सेतु लिंक योजना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना नदी से नदी जोड़ो का था। उस नदी से नदी जोड़ने के सपने को नरेन्द्र मोदी जी और भजन लाल जी ने मिलकर एम.पी. के मुख्य मंत्री जी के साथ ये ई.आर.सी.पी. योजना चालू की। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पूर्व मुख्य मंत्री मोहन लाल सुखाड़िया जी जब थे, शायद तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक योजना बनी थी कि जो खारी नदी है, उस खारी नदी से उठा-बोरा जो बांध है, उस बांध से जोड़ते हुए या फिर ईसर मंड, जो राजसमंद में

आता है, हमारी विधान सभा से एक किलोमीटर ही पड़ता है, वहां से खारी नदी से केनाल बनाकर करेड़ा के पास में जो बांध है, उस बांध का नाम बीच में सुखाडि़या बांध करना चाहते थे, लेकिन वह नहीं बना, फिर उसको चोर बावड़ी के नाम से बांध रखा। वह अधूरा है, उस बांध के निर्माण को भी पूर्ण करें और केनाल लाकर सारे तालाबों को, बांधों को जोड़ते हुए, उस नहरी तंत्र को किया जाए। अभी मैंने सी.एम.साहब से बात भी की थी, उन्होंने कहा था बनाएंगे, तो कम से कम उसमें 150 गांवों के लोगों को नहरी तंत्र के माध्यम से फायदा होगा।

सदन के माध्यम से मैं एक और बात करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, समय हो गया है तो मैं सिर्फ काम की बात करता हूं। दूसरे विभागों में मेरा काम निकल जाएगा। मेरे माण्डल विधान सभा क्षेत्र में 6 खेल स्टेडियम की मांग है। एक मगरोब के अन्दर दांतल गांव है, वहां बहुत बड़ा कस्बा है। एक सुआना के अन्दर, एक मेजा गांव के अंदर, एक बागोर के अन्दर, एक करेड़ा के अन्दर, एक ज्ञानगढ़ के अन्दर, 6 बड़े खेल स्टेडियम अगर बनते हैं तो युवाओं को खेलने के साथ उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन बड़े-बड़े कस्बों में खेल स्टेडियम बनाए जाएं।

मेजा बांध, भीलवाड़ा जिले का सबसे बड़ा बांध है, उसका सौन्दर्यीकरण करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए बजट दिया जाए। मेजा बांध को, जो हमारा माण्डल का तालाब है, उस तालाब को बांध का दर्जा दिया जाए। उसके अन्दर जो ऊपरी नहर निकाली, उस नहर का जल अगर माण्डल के तालाब के अन्दर छोड़ा जाता है तो किसानों को फायदा होगा।

इसी के साथ धोवनी नाड़ी जो माण्डल का बहुत बड़ा तालाब है, उसको धर्मतलाई के नाम से जाना जाता है। इसका भी अगर सौन्दर्यीकरण किया जाता है तो लोगों की धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और उसका फायदा मिलेगा। सभापति जी, दो मिनट। अभी तो वैसे ही कम है।

श्री सभापतिः सदस्य ज्यादा हैं।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): एक बेमाली से लादवास लुहारिया होते हुए माण्डल तक 7 मीटर का रोड चौड़ाईकरण किया जाए, जिससे लोगों को डायरेक्ट करेड़ा से माण्डल जाने के लिए फायदा मिलेगा। एक बावला से आमली कोठारी नदी पर कॉज-वे बनाते हुए साढ़े पांच मीटर का रोड बनाया जाए, जिससे लोगों को डायरेक्ट रायपुर, सहाड़ा, गंगापुर जाने के लिए फायदा होगा। एक 149डी सेमलो का बर्डिया से लगाकर खाजूणा होते हुए थाना तक अगर 7 मीटर चौड़ा दस किलोमीटर का रोड बनता है तो जो देवगढ़ वाला रोड है, उस रोड से सीधा देवगढ़ निकल जाएगा। इससे फायदा होगा। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे विषय हैं। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। राम-राम साहब।

श्री सभापति: श्री राम सहाय वर्मा।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): सभापतिमहोदय, आपने मुझे बजट 2025-26 पर

बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

विधान सभा में 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब के निर्देशन में तथा वित्त मंत्री का कार्य देख रही उप मुख्य मंत्री आदरणीया दिया कुमारी जी ने सरकार का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा व उप मुख्य मंत्री जी दिया कुमारी जी का हृदय से आभार जिन्होंने समाज के सभी वर्गों के हित का बजट हमे दिया।

आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी तथा उप मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि इस बजट में सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों, पेंशनर्स साथियों, किसानों, लघु उद्यमियों तथा बड़े उद्योगपतियों सभी को महत्व देकर आपने बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर जी की संकल्पनाओं को साकार करने का प्रयास किया है।

माननीय सभापति महोदय, 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' के ध्येय को लेकर बनाये गये बजट के लिए निवाई विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने मात्र घोषणाएं करने का कार्य किया है। उन घोषणाओं को धरातल पर लाने का कार्य नहीं कर पाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गहलोद में संस्कृत महाविद्यालय की घोषणा कर दी, लेकिन न भवन बना पाए, न शिक्षक लगा पाए। हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में संस्कृत महाविद्यालय गहलोद के लिए भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया है। यानी घोषणा कर रहे थे ये और काम कर रही है हमारी सरकार।

माननीय सभापति महोदय पूर्ववर्ती सरकार ने बजट वर्ष 2020-21 में घोषणा की कि झिलाई से संग्रामपुरा, झिलाई से सिरोही, बगड़ी से प्यावडी की सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा, लेकिन आज भी धरातल पर एक भी सड़क दिखाई नहीं दे रही है। पूर्ववर्ती सरकार के बजट वर्ष 2021-22 में अखबारों में पूर्ववर्ती विधायक द्वारा छपवाया गया कि निवाई में पुराने क्षतिग्रस्त नगरपालिका भवन को तोड़कर शहरवासियों के लिए अत्याधुनिक बस स्टैंड बनवाया जाएगा, लेकिन विगत 5 वर्षों की उदासीनता तो देखिए की बस स्टैंड बनना तो दूर, बसों को अंदर लाने तक में भी हमें बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पूर्ववर्ती सरकार ने बजट 2022-23 में निवाई के औद्योगिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के कार्य की घोषणा की, जिसके तहत आज तक कोई कार्य नहीं किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा की कि वैदिक संस्कृति के प्रोत्साहन व संरक्षण हेतु टोंक में वेद विद्यालय खोले जाएंगे, लेकिन पूरे टोंक जिले में एक भी वेद विद्यालय दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है।

पूर्ववर्ती सरकार ने बजट में बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं की डिग्गी से जस्ताना वाया मालपुरा निवाई रोड का निर्माण करवाया जाएगा, लेकिन ये कार्य आज तक लंबित है।

पूर्ववर्ती सरकार ने बजट वर्ष 2022-23 में चैनपुरा में फूड पार्क बनाने की घोषणा की, निवाई से जोधपुरिया तक 18 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण की घोषणा की तथा ग्राम भूरटिया में इंडस्ट्री एरिया बनाने की घोषणा की, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की ये सारी घोषणाएं मात्र घोषणाएं बनकर रह गई। चैनपुरा में फूड पार्क आज तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। निवाई से जोधपुरिया सड़क का हाल तो हमारे आराध्य देव धाम जोधपुरिया के लक्खी मेले में हम सब ने देख लिया। मेले के दौरान निवाई से जोधपुरिया जाने तक के लिए 8 घंटे का समय लग गया। आदरणीय, समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने 18 करोड़ की लागत कहां लगा दी। न रोड चौड़ी हुई, न ही आमजन को कोई सुविधा मिल पाई, औद्योगिक क्षेत्र तो बहुत बड़ी चीज होती है। आदरणीय, ग्राम भूरटिया में चारागाह भूमि है जिसे औद्योगिक प्रयोजनार्थ नहीं लिया जा सकता है,

Ans/rtm 15.50 2o 25.02.2025

लेकिन मेरे निवाई की भोली-भाली जनता को इन लोगों ने लगातार गुमराह किया। यहां तक कि बजट में घोषणा तक कर दी लेकिन आज तक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना नहीं कर पाए। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने इस बजट घोषणा में इसी रोड पर दत्तवास में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है।

विगत कांग्रेस सरकार ने अपनी बजट घोषणा में ट्रोमा अस्पताल निर्माण को तो खिलौना बना दिया। एक वर्ष तो ट्रोमा अस्पताल की घोषणा सोहेला में की गई, एक वर्ष के अंदर उसकी जमीन का आवंटन हुआ तो अगले ही वर्ष उसे परिवर्तित कर निवाई में ट्रोमा अस्पताल बनाने की घोषणा कर दी गई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह ट्रोमा अस्पताल ना सोहेला में बन पाया ना ही निवाई में बन पाया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि पिछले बजट में निवाई के अस्पताल को उप जिला अस्पताल घोषित किया था, इस हेतु जमीन भी आवंटित हो गई है और फाइनेंशियल निविदा भी निकाल चुके हैं। निवाई शहर में ही नवीन उप जिला अस्पताल भवन बनाने की तैयारी पूरी की जा चुकी है।

माननीय सभापति महोदय विगत कांग्रेस सरकार ने पीपलू में गौण कृषि मंडी स्थापित करने की घोषणा की थी लेकिन मेरे पीपलू क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए कृषि गौण मंडी की जमीन तक आवंटित नहीं कर पाए ये लोग। माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने विगत वर्ष के बजट में मेरे पीपलू क्षेत्र को कृषि मंडी की सौगात दी और आपके माध्यम से संपूर्ण सदन और पीपलू क्षेत्र की जनता को अवगत करवाना चाहूंगा कि जमीन का आवंटन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है, शीघ्र ही कृषि मंडी निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं तथा वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का हृदय से आभार, जिन्होंने विगत वर्ष के बजट में मेरे

विधान सभा क्षेत्र की लंबे समय से चलती आ रही माँगों को पूरी करते हुए उप जिला अस्पताल निवाई व राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय तथा पीपलू नगर को नगर पालिका तथा कृषि मंडी को निवाई से बनवाडा सडक निर्माण, डोडवाडी से बोरदा सड़क मय काज वे निर्माण हेतु सौगात दी।

इस वर्ष के बजट में भी मेरे क्षेत्र की महत्वपूर्ण माँगों को पूरा करते हुए निवाई शहर तथा वनस्थली की पेयजल आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण हेतु इस बजट में वनस्थली ग्रामीण पेयजल योजना के विस्तार और सुधार के लिए 8 करोड़ 69 लाख रुपए की घोषणा की। विद्युत आपूर्ति निर्बाध रखने की दृष्टि से चैनपुरा गांव में जीएसएस के निर्माण की घोषणा की। विधान सभा में सड़कों के निर्माण के लिए 9 करोड़ 57 लाख रुपए की घोषणा, स्टेट हाईवे 117 से जेबाढ़िया तक वेंटेड कॉजवे के निर्माण के लिए 5 करोड रुपए की घोषणा। नटवाड़ा गांव में भगवान बद्रीनाथ मन्दिर जो आस्था का केन्द्र है आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए बजट में घोषणा की। पीपलू अस्पताल में बेड्स की संख्या बढ़ाई । दत्तवास क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना की घोषणा की, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का व दिया कुमारी जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

हमारी सरकार इनकी तरह नहीं है जो कि माननीय वसुंधरा जी की सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई ईआरसीपी जैसी महत्वपूर्ण योजना को बंद बस्ते में डाल दिया। इन्होंने आनन फानन में जो घोषणाएँ की थीं उन सबको धरातल पर लाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। मैं इस सदन के माध्यम से मेरे निवाई की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि विगत वर्ष के बजट की भांति ही इस बजट की सभी घोषणाओं को धरातल पर लाने का कार्य हमारी सरकार द्वारा पूर्ण मनोयोग से किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई का उप खण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर स्थित कस्बा है जो कि जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर ज़िलों को जोड़ता है। शिवाड़ के द्वादशवें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर, देवधाम जोधपुरिया, डिग्गी कल्याण जी जाने के मार्गों के मध्य में स्थित होने से लाखों यात्री प्रतिवर्ष इसी मार्ग से आते-जाते हैं। केन्द्रीय बस स्टैण्ड ना होने से अधिकांश बसें क़स्बे में प्रवेश नहीं करती है तथा बाईपास पर भी नहीं रुकती हैं। बसों के अभाव के कारण यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पडता है। माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि निवाई में केन्द्रीय बस स्टैण्ड स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवाई उपखण्ड में एक तहसील निवाई तथा दो उप तहसील दत्तवास व सिरस है। माननीय, राहोली तथा इसके निकटवर्ती पटवार मण्डल निवाई क्षेत्र में तहसील के कार्यालय में आते है। निवाई तहसील मुख्यालय की दूरी अधिक होने के कारण आमजन को समस्या का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राहोली को उप तहसील तथा उप तहसील दत्तवास को तहसील में क्रमोन्नत करने की कृपा करे।

माननीय सभापति महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवाई उप खण्ड के ग्राम राहोली तथा आस पास के क्षेत्र से निवाई तहसील मुख्यालय की दूरी अधिक होने के कारण उच्च शिक्षा हेतु बच्चों को या तो निवाई रहना पड़ता है या चाकसू व जयपुर रहना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करुंगा कि मुख्य मंत्री जी राहोली में राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में रक्तांचल पर्वत स्थित है। रक्तांचल पर्वत सम्पूर्ण निवाई तहसील के लिए पौराणिक महत्व रखने वाली प्राकृतिक धरोहर है। प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को हज़ारों धर्मानुयायी उक्त रक्तांचल पर्वत के परिक्रमा लगाते है। निवाई शहर में आज तक किसी अच्छे पार्क का निर्माण नहीं होने से आमजन सेन्ट्रल पार्क विकास को लेकर लम्बे समय से मांग करते रहे है। माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि रक्तांचल पर्वत के पीछे स्थित भूमि को सेन्ट्रल पार्क के रूप में विकसित करने से निवाई तहसील के सम्पूर्ण आमजन के पर्यटन का प्रमुख केन्द्र हो सकेगा तथा आमजन को राहत मिलेगी। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा। माननीय सभापति महोदय, उपखण्ड मुख्यालय पर अगर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय का पद नव सृजित कर दिया जाएगा तो, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 06 थाने है व 02 डीवाईएसपी कार्यालय है, अगर यहां यह पद सृजित हो जाएगा तो छोटी-मोटी चोरिया, अत्याचार या इस तरह के अपराध हो रहे हैं, उन पर लगाम लगेगी।

सभापति महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई के उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय संचालित है जिसमें मात्र कला संकाय का ही अध्यापन करवाया जाता है। निवाई उपखण्ड के कई विद्यालयों में कक्षा 12 तक विज्ञान संकाय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को या तो टोंक जाना पड़ता है या जयपुर आना पड़ता है। अगर विज्ञान संकाय खुल जाएगा तो आस-पास के गाँवों के सैकड़ों छात्र-छात्राएँ निवाई में ही विज्ञान संकाय में पढ़ पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि निवाई उप खण्ड मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय प्रारम्भ करवाने की कृपा करे। वन्दे मातरम्। 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय', आपणो अग्रणी राजस्थान। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति:श्री विरेन्द्र सिंह।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज विपक्ष के सभी साथी बाहर गये हैं। मैं तो पहली बार विधान सभा में आया हूं, लेकिन विधान सभा में जो देखने को मिला, मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायतों में भी ऐसे दृश्य नहीं होते हैं। इनके आपस में लड़ाई-झगड़े पुराने हैं। आपस के लड़ाई-झगड़ों में इन्होंने पूरे पांच साल निकाले।

माननीय सभापति महोदय, इनका एक वाकया है, जब अजमेर में पूर्व मुख्य मंत्री जी

कार्यक्रम में आये थे तो इनके आपस की लड़ाई, वहां पूर्व सी एम साहब के पोस्टर फाड़े गये, दूसरे पक्ष के लोगों को थाने में बंद किया गया, पूर्व विधायक थाने के सामने धरने पर बैठे। इनके आपस की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। आपस में लड़ते रहे और पांच साल इन्होंने राजस्थान को पीछे धकेला।

हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले ही बजट में जितने काम किये, बजट में घोषणाएं हुई उनकी क्रियान्विति हुई, इनके पांच साल में भी उतने काम नहीं हुए।

माननीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही नये कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता के द्वारा व्यक्त किये विश्वास को सही प्रमाणित किया है। माननीय मुख्य मंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश निरन्तर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2030 तक 350 बिलियन अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है। हमारी सरकार ने अल्प अवधि में ही पूंजीगत व्यय में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करते हुये 9 हजार 600 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण और 13 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है। साथ ही राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए 9 हजार 300 करोड़ रुपये इस योजना में खर्च होंगे।

माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने जल जीवन योजना का 2028 तक समय बढ़ाया, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का केन्द्रीय मंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं।

VPS-RTM-25.02.2025-16.00-2p

क्योंकि पिछली सरकार ने जल जीवन मिशन में अगर काम किया होता तो आज प्रदेश में हर घर में पानी पहुंच सकता था, लेकिन इनको यह डर था कि कहीं जल जीवन मिशन को लागू कर देंगे तो मोदीजी का नाम होगा और अगले चुनावों में कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उनका हश्र यही हुआ।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने कार्य को गति देते हुए 1300 करोड़ रुपये के कार्यादेश तथा 41621 करोड़ रुपये की लागत के कार्य की निविदाएं जारी की हैं। आगामी वर्ष में 20 लाख घरों में कनेक्शन दिये जाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न कार्य करवाये जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शहरी क्षेत्रों में अमृत 2.0 योजना में 183 नगर निकायों में पेयजल के लिए 15123 करोड़ रुपये के कार्य करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) योजना प्रारंभ करने हेतु 5830 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य कराये जाएंगे। आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेयजल के लिए आगामी वर्ष में पूरे प्रदेश में एक हजार ट्यूबवैल व पन्द्रह सौ हैंडपम्प पूरे राजस्थान में लगाने का जो

लक्ष्य है, उससे पूरे प्रदेश को आने वाली गर्मी में पेयजल की किल्लत से राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में कांग्रेस के राज्य में पिछले कार्यकाल में जब बिजली बंद होती थी, किसानों को रात को बिजली दी जाती थी, जब हम ए.ईएन. और एक्स.ईएन. से यह पूछते थे कि लाइट क्यों बंद हो गयी? तो वे यह कहते थे कि साहब, राजस्थान बिजली प्लांट में कोयला नहीं है, कोयला खतम हो गया, जबकि छत्तीसगढ़ में इनकी कांग्रेस की सरकार थी। जब राजस्थान में इनकी कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर खानें कोयले की आवंटित होती थीं, लेकिन इनकी ही सरकार होते हुए भी इनको कोयला समय पर नहीं दिया जाता था। इनके मुख्य मंत्री केवल आपस की लड़ाइयों में उलझे रहे। आगामी वर्ष में भी 5700 मेगावाट ऊर्जा के कार्यक्रम प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में 50 हजार नये कृषि कनेक्शन तथा पांच लाख घरेलू कनेक्शन, इस बजट में जिसका उल्लेख हुआ है, दिये जाएंगे। 180 जी.एस.एस. की स्थापना होगी। अन्य राज्यों से अब बिजली लेना बंद होगा। पिछली सरकार ने एक बड़ा खेल खेला कि बाहर के प्रदेशों से महंगी बिजली उधार ली और इस प्रदेश को ऋण के गर्त में डुबोया। माननीय सभापति महोदय, अब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट बिजली फ्री करने का बजट में जो प्रावधान रखा है, इससे निश्चय ही पूरे प्रदेश के गरीब किसान को बिजली देने से उसको फायदा मिलेगा।

युवा वर्ग में जो कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले युवाओं को लोक-लुभावने वादे देकर जो सरकार में आयी, वह उन्होंने पूरा नहीं किया लेकिन हमारी सरकार ने 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्ती और निजी क्षेत्र में भी 1 लाख 50 हजार युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान रखा है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में वैदिक गुरुकुल व वैदिक पैटर्न केन्द्र खुलेंगे। इस बजट सत्र में, इस 2025-26 के बजट में 11 नये कॉलेज हमारे राजस्थान में खुलेंगे। नौ महिला कॉलेज और दो कृषि महाविद्यालय राजस्थान में खुलेंगे। 150 स्कूलों का अपग्रेडेशन होगा और 1500 स्कूलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगेंगे, यह सारी व्यवस्था, यह इतना बढ़िया बजट माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने रखा है।

पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में जयपुर में IIFA Awards का कार्यक्रम, दस स्थानों पर हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा, झीलों का सौंदर्यीकरण और पुजारियों का मानदेय 7500 रुपये करना, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब मैं विधान सभा के बाद में वापस मसूदा गया तो वहां पर पुजारियों ने कहा कि आपकी सरकार ने तो हमारे पुजारियों का 7500 रुपये मानदेय किया है और मंदिरों के रख-रखाव के लिए बहुत बड़ा काम किया है तो मैंने यह कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, मंदिरों के महत्व को जानती है। मंदिरों का रख-रखाव भारतीय जनता पार्टी के राज में होता है और अयोध्या में भी भगवान श्रीराम का मन्दिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में और प्रदेश में है, इसलिए यह सम्भव हुआ है। दस नये गांवों में रूरल टूरिज्म, 29 हवाई पट्टियों का विकास, यह सारा प्रदेश की सरकार करने जा रही है।

कृषि के क्षेत्र में देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों को

पहली बार अगर कोई किसान को सम्मान निधि के नाम पर उनका सम्मान किया गया है तो छह हजार रुपये माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों को सम्मान निधि के नाम पर दिये हैं। पिछले बजट में प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय भजन लालजी शर्मा ने दो हजार रुपये प्रदेश की ओर से किसानों को जो पी.एम. सम्मान निधि के नाम से और दिये थे, लेकिन इस बजट में एक हजार रुपये और बढ़ाकर अब राजस्थान के किसानों को नौ हजार रुपये प्रति माह किसान सम्मान निधि के नाम से मिलेंगे। एक लाख किसानों को कृषि उपकरणों के लिए अनुदान मिलेगा। एक हजार कस्टम हायरिंग सेंटर इस प्रदेश में बहुत जल्दी ही खुलने वाले हैं।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर वृद्धों और दिव्यांगों को, महिलाओं को 1250 रुपये पेंशन की गयी है। बालिकाओं को 35 हजार स्कूटी का वितरण होगा। आंगनबाड़ियों में सप्ताह में पांच दिन दूध मिलेगा। मुझे वह कार्यकाल भी कांग्रेस का पिछली बार का याद है जब विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को गेहूं उबाल कर दिये जाते थे। 2003 में माननीय वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनीं तब मिड डे मील चालू हुआ और दोपहर का शुद्ध भोजन उन बच्चों को मिलने लगा।

पशुपालन और डेयरी में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है।**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

माननीय सभापति महोदय, अभी तो पांच मिनट भी नहीं हुए हैं। दस मिनट का समय सभी को है और आज तो संख्या भी बहुत कम है। केवल अपनी पार्टी के ही लोग बोल रहे हैं।

श्री सभापतिः अभी आपका समय बाकी है। बोलिये।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): चिकित्सा के क्षेत्र में 750 चिकित्सकों की भर्ती, 1500 पैरा मेडिकल कर्मियों के पद सृजित, 70 साल से अधिक वृद्धों को घर पर ही मुफ्त दवा और आयुष्मान योजना का लाभ अब अन्य प्रदेशों में भी मिलेगा। इन्होंने केवल योजनाओं के नाम बदले, इन्होंने योजनाओं का नाम बदला, आयुष्मान योजना अगर लागू कर देते तो प्रदेश के बीमार दूसरे अन्य प्रदेशों में भी अपना इलाज करवा सकते थे।

सड़क के लिए कहना चाहूंगा कि पांच हजार करोड़ रुपये से पुलों व हाईवे का निर्माण, नौ ग्रीन फील्ड और 15 नये शहरों में रिंग रोड का निर्माण होगा।

अब मैं मेरे मसूदा विधान सभा क्षेत्र के लिए एक मांग रखना चाहूंगा कि बिजयनगर में हमारे उप खंड कार्यालय खोला जाये, बिजयनगर में एक खेल स्टेडियम बने, भिनाय में नगरपालिका खोलने का निवेदन है और रामगढ़-मसूदा में उप तहसील खोलने का भी माननीय सी.एम. साहब से मेरा आग्रह है और खरबा, जालिया, नागोला और देवलिया में पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत कराएं। मसूदा में अधिशासी अभियंता का कार्यालय खुलाएं। बेस्ट टूरिस्ट विलैज देवमाली, जो केन्द्र सरकार ने मसूदा विधान सभा क्षेत्र में देवमाली, भगवान देवनारायण का मन्दिर है तो वहां पर एक रोप-वे का निर्माण कराएं जिससे

बुजुर्ग यात्री जो दर्शन करने के लिए आते हैं तो वे वहां पर आराम से पहुंच सके। बिजयनगर में अपर जिला सेशन न्यायालय खोलने के लिए भी निवेदन करता हूं और लास्ट में अंतिम नारायण सागर बांध अजमेर और ब्यावर जिले का सबसे बड़ा बांध है तो उसको ई.आर.सी.पी. योजना से जोड़ने के लिए उसमें प्रावधान है लेकिन तत्काल लाभ देते हुए भीलवाड़ा जिले में जो चम्बल का पानी आ रहा है, उस पानी से इस नारायण सागर बांध को जोड़ा जाए, जिससे पूरे मसूदा विधान सभा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था हो।

माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री समाराम (अनुपस्थित)

श्री रामावतार बैरवा। (अनुपस्थित)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, इनको सुनने वाले ही नहीं है। इनको नींद आने लग गयी। इनको कोई दूसरा नहीं सुन रहा है।

श्री सभापतिः आप चिंता मत करो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इसलिए मैं बैठा हूं न। मैं इसीलिए आया हूं। आप मेरे को सुनाओ, मैं सुनूंगा आपकी बात। कम से कम सुनने के लिए बैठे हैं इनकी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री रामावतार बैरवा। (अनुपस्थित)

श्री गुरवीर सिंह। (अनुपस्थित)

श्री जेठानन्द व्यास।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, मां भारती के चरणों में नमन, जय श्रीराम।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं उस बीकानेर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे अच्छे वोटों से जिताकर इस सदन में भेजा है और जिसका नेतृत्व जो कर रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लालजी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि

हम नई चेतना की धारा, हम अंधियारे से उजियारा,
हम उस बयार के झोंके हैं जो हर ले जग का दु:ख सारा।

ऐसा बजट दिया है जो गरीबों का दु:ख हरण करने वाला है। हर व्यक्ति के पक्ष में यह हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी व हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लालजी की इच्छा के अनुसार, उनके अनुरूप हमारे उप मुख्य मंत्री व वित्त मंत्रीजी ने बजट सभी वर्गों के लिए, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, पत्रकारों, सबका ध्यान रखते हुए यह बजट रखा है।

SSY/RTM/25.02.2025/16.10/2q

यह बजट ऐसा है जो कि हर व्यक्ति के मन को भाने वाला है। जब बजट पेश हुआ उस दिन मेरे पास इतने फोन आये कि क्या बजट दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सब लोग प्रसन्न हैं। इस प्रसन्नता को देखकर हमारे जो विरोधी दल हैं वे दुःखी हो रहे हैं। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस ने कभी भी ऐसा बजट नहीं दिया पहले साल में इसलिए वे दुःखी हो रहे हैं। उनका विरोध करने का धर्म है। वे अन्दर ही अन्दर खुद तो प्रसन्न हैं कि ऐसा बजट मिला है। उनको भी फायदा मिल रहा है। वे भी इसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी वे जनता के सामने आकर अपना धर्म निभा रहे हैं विरोध करने का।

पिछले बजट में मेरे बीकानेर को, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने जितनी मांगें मैंने रखी उन सबको पूरा किया। मेरे बीकानेर को विकास प्राधिकरण बनाया गया और मुझे बड़ा दुःख होता है कि एक बड़ा नेता, कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हुए और मेरे प्रतिद्वंद्वी, उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो वायरल किया कि इस विकास प्राधिकरण से बीकानेर को नुकसान होने वाला है। ऐसी उनकी मानसिकता, जो कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाती है।

इस बजट में हमारे मुख्य मंत्री भजन लाल जी, उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी ने व ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर ने बीकानेर का ध्यान रखते हुए एक 132 केवी जीएसएस की भी घोषणा की है। मेरे जानकारी में आया है, यहां तक कि इधर घोषणा हुई उधर जिलाधीश के पास पत्र भी पहुंच गया है जमीन के लिए, तो मैं, धन्यवाद देता हूं सरकार को कि जो घोषणा करते हैं उसको तुरंत लागू करने का प्रयास करने वाली कोई सरकार है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई मुख्य मंत्री हैं तो भजन लाल जी हैं जो हर दृष्टि से विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं।

जब यह घोषणा हुई तो इनके जो बड़े नेता, मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं, उन्होंने एक अख़बार की कटिंग वायरल की कि हमने इस घोषणा को पहले ही कर दिया था और उसमें लिखा था कि 2021 तक यह पूरा कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा, हमने बजट भी दे दिया, उसमें यह भी लिखा हुआ था। लेकिन 2021 तक जहां वह घोषणा की, मुरलीधर व्यास नगर में एक इंच भी जमीन नहीं है, वहां घोषणा कर दी। आज तक वहां कोई जमीन नहीं हुई और यह कह रहे हैं कि हमने बजट दे दिया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बजट कहां गया? ऐसा लगता है कि उसमें कोई घोटाला हो गया है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है यह घोटालों की सरकार है। सब जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि यह घोटालों की सरकार है।

मेरे क्षेत्र में एक सैटेलाइट अस्पताल जिसको 2007 में और साथ में हमारे पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने जिला अस्पताल की घोषणा की, उसके बाद कांग्रेस सरकार आई उन्होंने उसकी स्थिति यह कर दी कि पिछले 2023 तक वहां पट्टी और रूई भी नहीं मिलती थी। लेकिन मैं, मेरे मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे ही यह सरकार आई, वहां सोनोग्राफी होना शुरू हो गया। डिजिटल एक्सरे मशीन

लग गई। एक्सरे होना शुरू हो गया। कई प्रकार की जांचें शुरू हो गई। गायनिक के ऑपरेशन शुरू हो गये और डिलीवरी भी शुरू हो गई। ऐसे हमारे मुख्य मंत्री जी ने हमें बजट दिया, जो जिला अस्पताल का आज स्वरूप ले रहा है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बीकानेर की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान हमारी सरकार ने रखा है।

कई ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनका उन्नयन भी किया है। हमारी सरकार ने प्रत्येक जिले में हेमोडायलेसिस सुविधा हेतु 10 बैडों की घोषणा भी की है। यह सरकार राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रही है।

जल की दृष्टि से अगर देखा जाये तो पिछले वर्ष प्रत्येक जिले को 5 ट्युब वैल और 10 हैंडपंप दिये। लेकिन मेरी मंत्री जी से और सरकार से मांग है कि हमारा जो शहरी क्षेत्र है वहां हैंडपंप नहीं लग सकता इसलिए हमें उनकी जगह पानी की टंकियां दी जायें। यही मेरी उनसे मांग है। मैं यही बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने बीकानेर में कुछ ऐसी टंकियों की भी घोषणा की, लेकिन उनके लिए जमीन नहीं हुई। सरकार चली गई, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने उनको जमीन भी दिलाने का प्रयास किया और वहां इसी सरकार में काम भी शुरू हुआ है। टंकियां भी बननी शुरू हुई हैं। इन्होंने केवल घोषणाएं कीं, कभी जनता के लिए काम नहीं किया। घोषणा करते और पता नहीं बजट भी लाते, कहां गायब हो जाता, यह भी इनका रहा है।

मैं, मेरी इस सरकार का, कन्हैया लाल जी का, मुख्य मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने 5 करोड़ रुपये ऐसे क्षेत्र के लिए दिये, करमीसर, सुजानदेसर, जैनाती रोड, जहां केवल मजदूर रहते हैं, उन मजदूरों का ध्यान रखते हुए 5 करोड़ रुपये दिये हैं, जिसमें वहां टंकियां भी बनेंगी और पाइप लाइन भी होगी। इन्होंने उस मजदूरों के क्षेत्र का भी पूरा ध्यान रखा है। मैं इनका आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि जेजेएम शहरों में भी आपने बजट दिया है।

अगर सड़कों की दृष्टि से देखा जाये तो मेरे क्षेत्र में पूरी सड़कें टूटी हुई हैं। पता नहीं, स्थिति यह थी कि बीकानेर में जब लोग आते थे तो लोग कहते थे कि यह एक बड़ा गांव है। एक बड़ा गांव कहते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और इन 14-15 महीनों में हम देखें तो बीकानेर का स्वरूप बदलना शुरू हो गया है। सड़कों की स्थिति सुधरनी शुरू हुई है। पहले में 10 करोड़ रुपये दिये और 15 करोड़ और दिये, उन सड़कों की स्थिति देखते हुए, क्योंकि बीकानेर शहर की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो मैं मांग करता हूं कि पूरे शहर के लिए, पश्चिमी विधान सभा के लिए 5 करोड़ रुपये और दिये जायें तो जनता की जो स्थिति खराब है, वह सही हो जाये।

मंदिरों के लिए भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। आज तक जितने भी देवस्थान विभाग के मन्दिर हैं, सारे जर्जर अवस्था में हैं। ऐसे बड़े मन्दिर जहां हजारों लोग हमेशा दर्शन करने जाते हैं, उन मंदिरों की स्थिति भी खराब है। लेकिन हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा। मंदिरों के लिए भी बजट दिया है और तो और देखा जाये, पिछली बार मैंने पर्ची के

माध्यम से एक मांग रखी थी कि हमारे पुजारियों का वेतन बढ़ाया जाये, भोग बढ़ाया जाये और सरकार ने उस मांग को मानते हुए पुजारियों का वेतन भी बढ़ाया है और भोग की राशि भी बढ़ायी है।

मेरा एक और निवेदन है कि वहां जो चौकीदार हैं, उनको केवल महीने के 3 हजार रुपये मिल रहे हैं। उनके भी 5 हजार रुपये हो जायें तो अच्छा हो जाये। उनके लिए भी मैं मांग करता हूं।

आपने प्रत्येक क्षेत्र में बजट दिया है। विकास की दृष्टि से हमारी सरकार ने खूब काम किया है। इस प्रकार से बीकानेर को अच्छा बजट दिया है। लेकिन मेरी मांग है कि बीकानेर में एक मिनि सचिवालय हो जाये, क्योंकि बीकानेर क्षेत्र बड़ा है। मिनि सचिवालय और पुलिस कमिश्नरेट किया जाये, जिससे जनता को और सुविधा मिल सके।

बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय है और वहां पर कृषि इंजीनियर्स के लिए सारे तामझाम हैं। लेकिन कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज वहां खुल जाये तो किसानों के लिए भी बहुत सुविधा होगी। जनसंख्या को देखते हुए बीकानेर शहर में 2 कार्यालय उपखंड होने चाहिंए, 2 कार्यालय तहसील के होने चाहिए, इसलिए मेरी मांग है कि एक उपखंड अधिकारी और एक तहसीलदार की और स्वीकृति दी जाये, जिससे कि बीकानेर का और विकास हो। जिससे किसानों को भी पूरी सुविधा मिले, हर व्यक्ति को सुविधा मिले।

सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की जय। जय श्रीराम।

श्री सभापतिः डॉ. ऋतु बनावत।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने बजट पर चर्चा में मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया।

सभापति महोदय, पिछली सरकार ने बयाना विधान सभा के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया। जिसके कारण से कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो थे, वहां पर पूरे नहीं हो पाये। पिछली सरकार में ना सड़कों का काम हुआ, ना पेयजल पर काम हुआ, ना चिकित्सा पर काम हुआ, जिसका खामियाजा आज भी जनता को भुगतना पड़ रहा है और मैं सरकार को धन्यवाद दूंगी, बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी कि पिछले बजट में भी और इस बजट में भी बयाना विधान सभा को बहुत सारी सौगातें प्रदान की गई हैं।

spp/rtm/25.02.2025/16.20/3a

इस बजट में हमें तीन बड़े रोड दिये गये, दो जी.एस.एस. दिये गये 33 के.वी.ए. 11 के.वी.ए. के और बयाना बस स्टेण्ड, रूपबास में रीको और बयाना के ड्रैनेज और सीवरेज के लिये हमें बजट प्रदान किया गया। इसके लिये मैं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार के

मुखिया हम सबके, हम सबके इसलिए कहूंगी कि वे भरतपुर से आते हैं, मैं भी भरतपुर से आती हूं तो भरतपुर के लाल आदरणीय भजनलाल जी, मुख्य मंत्रीजी का और डिप्टी सी.एम. का, जिन्होंने इतना अच्छा बजट पूरे ऑल ओवर प्रदेश के लिये दिया और जनता के हर वर्ग को, एक सहूलियत पहुंचाने का काम किया, हर विधान सभा क्षेत्र को सहूलियत पहुंचाने का काम किया और इस बजट के लिये कुछ चंद लाइनें मेरे दिमाग में हैं, जो मैं कहना चाहूंगी-

'नजर-नजर में उतरना कमाल होता है,
नफस-नफस में बिखरना कमाल होता है,
बुलन्दियों पर पहुंचना कोई आसान नहीं,
लेकिन बुलन्दियों पर ठहरना भी कमाल होता है।।

माननीय सभापति महोदय, समय की मेरी बाध्यता ज्यादा है। समय भी मेरे पास कम है। धन्यवाद देने के लिये तो बहुत सारी चीजें हैं और मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी मुख्य मंत्रीजी को और उप मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दिया है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की कुछ डिमांड्स हैं, जिनको भी सदन के पटल पर रखना चाहती हूं कि रूदावल को नगरपालिका क्षेत्र बनाया जाये। रूदावल एक कस्बा है, जो सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है हमारे क्षेत्र की और वहां पर नगरपालिका के रूप में उसको विकसित किया जायेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही, मेरे क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग, जो बहुत पुराना है और वहां पर किले का बहुत अच्छा काम भी चल रहा है ट्यूरिज्म को विकसित करने के लिये मैंने भी अपने विधायक कोष से 10 लाख रुपये रोप-वे के लिये वहां पर दिये हैं। अगर उस रोप-वे के निर्माण में सरकार सहयोग करे और बजट आवंटन करे तो वहां पर ट्यूरिज्म को ज्यादा अच्छी तरह से विकसित किया जा सकेगा। 33 के.वी.ए. के जो 11 जी.एस.एस. हैं, उसमें बिनउवा और मेरठा में मुझे दिया गया है, लेकिन वहां पर बिजली का सिस्टम बहुत खराब है। मैंने अभी सुबह भी यह डिमांड रखी थी कि थाना डांग और बुराबाई खेड़ा रिछोली में हमें तीन जी एस एस की और आवश्यकता है। सरकार हमारी इस मांग को भी पूरा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैंने सुबह कहा था कि 50 हजार से ज्यादा कंज़्यूमर हमारे बयाना उपखण्ड में हैं और एक अलग से ए.ईएन. आफिस की हमारी डिमांड है। बहुत समय से यह डिमांड चली आ रही है। इसको भी सरकार ध्यान में रखते हुए ए.ईएन. आफिस की स्थापना करने का काम करे।

बयाना में रीको एरिया है, वहां पर मीटर ए.ईएन. की आवश्यकता बहुत समय से है। रीको जब से बनता है, तब से मीटर ए.ईएन. की स्थापना होनी चाहिये थी। मीटर ए.ईएन. वहां पर बैठना चाहिए था, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी सरकार से डिमांड रहेगी कि आप इस ओर ध्यान देते हुए औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिये वहां पर मीटर ए.ईएन. कार्यालय स्थापित किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों की मैं बात करूं तो सड़कों के क्षेत्र में जो मैंने बजट में देखा कि हमारे आदरणीय प्रेरक अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा से प्रेरित होकर कहा

गया कि कनेक्टिविटी के लिये सड़कों की बहुत जरूरत है। मैं यह कहूं कि पिछली सरकार में जो PWD मिनिस्टर थे, वे मेरे ही विधान सभा के पास से वैर से आते थे और हालत देखिये कि PWD मिनिस्टर के बगल वाली विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति यह है कि 100 से ज्यादा सड़कों की अभी डिमांड है। क्या आप सोच सकते हैं कि वहां पर पिछले कार्यकाल में सड़कों का निर्माण किस तरह नगण्य रूप में हुआ और जहां पर जो घोषणाएं हुईं उनको भी धरातल पर नहीं उतारा गया। मैं सरकार को साधुवाद दूंगी कि जो घोषणाएं हो रही हैं, उन पर तुरंत काम शुरू हो रहा है। जमीन के अलॉटमेंट से लेकर सब चीजें हो रही हैं। मैं इसके लिये साधुवाद दूंगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही बहुत लम्बे समय से एक डिमांड है रूपबास क्षेत्र की ए.डी.जे.कोर्ट और ए.सी.जे.एम. कोर्ट की। आज भी वहां पर लम्बे समय से यह डिमांड चली आ रही है और आज भी क्षेत्र के जो वकील हैं, बार एसोसिएशन है, वे आज भी आन्दोलनरत हैं और उन्होंने अनिश्चितकालीन, जब तक यह डिमांड पूरी नहीं होती, उन्होंने आन्दोलन शुरू कर रखा है, क्रमिक अनशन पर भी वे लोग बैठे हैं तो मैं यही कहूंगी कि इस डिमांड की ओर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में मिलकपुर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में सरकारी भूमि है, यहां पर कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय खोला जाना चाहिए। बयाना और रूपबास में खेल स्टेडियम की घोषणा की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या है और इर्रिगेशन मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे भी हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगी कि तुरतीपुरा से थानाडांग के लिये बंद बारेठा पुल का निर्माण कराया जाये जिससे कि बयाना की दूरी 7 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। साथ ही, स्टेट हाईवे संख्या-1 सेवर से सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर लेन घोषित किया जाये। बयाना में ए श्रेणी का पशु चिकित्सालय है, उसके लिये भूमि आवंटित हो गयी है लेकिन अभी वहां पर भवन नहीं है तो मेरा यह भी सरकार से निवेदन रहेगा कि वहां पर इसके लिये भी राशि उपलब्ध करायी जाये।

इसके साथ ही, बयाना नगरपालिका क्षेत्र को नगर परिषद् में क्रमोन्नत किया जाये और डांग क्षेत्र में, बयाना का जो डांग क्षेत्र है, उसमें एक नन्दीशाला खोलने का मैं सरकार को निवेदन करती हूं। साथ ही यह कहूंगी कि समय ज्यादा नहीं है, सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद बजट देने के लिये और ऐसे ही सरकार बयाना विधान सभा क्षेत्र की जनता को बजट देती रहे जिससे कि हमारे क्षेत्र के विकास को चार चाँद लग सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुरवीर सिंह।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने बजट 2025-26 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया और मैं इस सदन में सोलहवें विधान सभा सत्र में दूसरे बजट पर जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान के इस लोकतंत्र के इतिहास में, लोकतंत्र के इस मन्दिर में इसकी मर्यादाओं को,

इसकी परम्पराओं को जिस तरीके से कल तार-तार किया गया, उसकी भी मैं घोर निन्दा करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि देशभर ने वह देखा कि लगातार विपक्षी दल कई दिनों से नोटंकी, जो बार-बार संविधान की प्रतियां लेकर लोक सभा में और देश के विभिन्न राज्यों में ले जाकर लहराया जा रहा है और जिस तरीके से कल यहां जो शब्द यूज किये गये, जो निम्न स्तर पर राजनीति को ले जाया गया और मुझे यह कहने में कोई शंका नहीं है कि विपक्षी दल के एक बहुत वरिष्ठ नेता, जब बाहर मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो संस्कार और परिपाटी हमें आप लोगों को सौंपनी चाहिए थी, हमें खेद है कि हम वहां वो नहीं कर पा रहे हैं। मुझे राजस्थान की आठ करोड़ जनता द्वारा 200 विधान सभा क्षेत्रों में से जो 200 विधायक चुनकर आये हैं, यह जनता आस और उम्मीद लगाकर बैठी है। उनके ख्वाब हैं, उनके सपने हैं कि राजस्थान की विधान सभा में हमारे लिये चर्चा होगी। पिछले पांच साल में पूर्ववर्ती सरकार के समय को भी राजस्थान की जनता ने देखा है और आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दूसरे बजट को भी जनता ने देखा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात शुरू करने से पहले कबीर जी के दोहे से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। कबीर जी ने कहा-

'चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय,

दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय।।

जहां पिछले पांच साल में चक्की के दो पाटन थे, आज वह पाटन बढ़कर चार हो गये हैं, और जिस तरीके से यह लड़ाई कल कांग्रेस का मनमुटाव इस सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है, इस सदन को शर्मसार कर रहा है, मुझे खेद है और दुःख हुआ कि आज आसन पर बैठे हमारे अध्यक्ष महोदय के आंखों में जब आंसू आये तो मैं संविधान की, उन कांग्रेसियों को और इस देश के और इस राजस्थान के लोगों को कांग्रेस का जो सच है, वह जनता को सामने लाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करता हुआ बजट पर आऊंगा। मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्री भजनलाल जी शर्मा का और हमारी उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि गंगानगर कृषि प्रधान जिले में जो हमने सपने संजोये थे, जो हमारा यहां आने के बाद जो हमारी आशाएं और उम्मीदें सरकार से थीं, उनसे कहीं बड़ा दिल रखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने हमें बजट दिया है। हमारे गंगानगर जिले की पूरी की पूरी इकोनोमी सिंचाई पर चलती है। पानी से हमारी रोजी-रोटी चलती है। चाहे गंगानगर का किसान है, चाहे गंगानगर का मजदूर है, हनुमानगढ़ और गंगानगर का किसान, मजदूर, व्यापारी की सारी इकोनोमी सिंचाई पर निर्भर करती है और मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्रीजी ने इन दोनों बजटों में सबसे ज्यादा ध्यान सिंचाई की तरफ रखते हुए, पानी की तरफ रखते हुए गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के लिये तकरीबन 1800 करोड़ रुपया इन दो बजटों में दिया है। गंगानगर का किसान आज उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिये गये पिछले बजट में फिरोजपुर फीडर का, जहां हमें

200 करोड़ रुपया मिला, मुख्य मंत्रीजी उसकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। हमने पंजाब की सरकार से सम्पर्क करके, राजस्थान के सिंचाई विभाग ने केन्द्र से सम्पर्क करके आज हमारी डी.पी.आर. लगभग मंजूर होने की स्थिति में है।

jyg/Rtm/25.02.25/16.30/3b

जो सतलुज-व्यास का पानी राजस्थान में लाया है, जो महाराजा गंगा सिंहजी की सोच जो 1927 में उन्होंने गंगानगर को जीवन दायिनी गंग नहर दी, आज उसका दुबारा अगर कोई काम डीपीआर बनकर उसकी रिलाइनिंग का काम होगा तो फिरोजपुर फीडर का होगा। आज हमारे बजट 2025-26 में जो बालेवाला हैड से लेकर राजस्थान बोर्डर के खखा हैड तक जो 300 करोड़ रुपये की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है उससे पानी की छीजत रुकेगी, उसमें पानी की पंजाब में चोरी होती है वो रुकेगी, इनके पटड़ों पर डामर सड़क बनाकर उसका जो काम होगा, उससे निश्चित तौर पर गंगानगर के किसानों को नया जीवन मिलेगा। पक्के खाळे जो प्रत्येक किसान की जरूरत है, आज पक्के खाळों के लिए भाखड़ा-आईजीएनपी और गंगनहर के लिए बहुत बड़ा बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है। उसमें यह नहीं देखा, क्योंकि पिछली सरकार न राजस्थान की जनता की सखी थी, न कांग्रेस की सखी थी, और वो सिर्फ और सिर्फ सखे थे तो जो उनकी कुर्सी के साथ उनके गुट में शामिल था, बजट उनको मिलता था। आज बजट राजस्थान की जनता के लिए है। आज हनुमानगढ़ जिले के भाखड़ा के क्षेत्र में, न संगरिया में बीजेपी का विधायक है, न हनुमानगढ़ में है, ना रावतसर में है, ना पीलीबंगा में है, पर उनके लिए 590 करोड़ रुपये का प्रावधान भाखड़ा में किया है। तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं हैं, पर उन किसानों के लिए मुख्य मंत्रीजी ने यह बहुत बड़ी देन दी है।

माननीय सभापति महोदय, अनूपगढ़ की बात करूं तो अनूपगढ़ और रायसिंहनगर, दोनों जगह कांग्रेस के विधायक हैं, पर 200 करोड़ रुपये वहां के पक्के खाळों के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है। हमारे 1 साल के कार्यकाल में, सिर्फ गंगानगर में 1 साल के कार्यकाल में 108 करोड़ के पक्के खाळों का निर्माण अभी हमारा चल रहा है और किसानों के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले साल में ही यह काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ पूर्ववर्ती सरकार का आंकड़ा मैं रखूं, जो इन्होंने अपने तीसरे अभिभाषण में गवर्नर से कहलवाया, पहले तीन साल के पूर्ववर्ती सरकार ने मात्र 40 करोड़ 80 लाख के खाळे बनाये। जहां हमने पहले ही साल में 108 करोड़ के खाळे बनाये है और हमारे पास में 800 करोड़ रुपये सिर्फ गंगानगर और हनुमानगढ़ के पक्के खाळों के निर्माण के लिए मिलेंगे, यह बहुत बड़ी सौगात है। सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र की चाहे एमजेडी नहर हो,एमएमके हो, एलएलजी हो, इसके लिए 92 करोड़ रुपये देना, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं। एसडीएस नहर का 50 करोड़

रुपया हो, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, साधुवाली गाजर मण्डी में न सिर्फ राजस्थान बल्कि पंजाब के किसान भी वहां आकर गाजर आकर बेचते हैं, तकरीबन 150 करोड़ रुपये की वहां लागत आयेगी और 110 करोड़ रुपये की 62 बीघा जमीन सरकार ने, उसको सरकार ने स्थानांतरित करके सरकार ने मार्केटिंग कमेटी को देदिया है उसका भी निर्माण जल्द शुरू हो जायेगा, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं, जिस तरीके से आज किसान सम्मान निधि के पैसे बढ़ाकर किसानों को 9 हजार रुपये किया है, 72 लाख किसानों को इससे राहत मिलेगी। इससे गंगानगर ही नहीं पूरे राजस्थान के किसानों के लिए जो आज बोनस दिया है गेहूं पर वो आज के किसानों को बहुत बडी राहत है। आज किसान बैंकों का कर्जदार हो चुका है, पर उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सहायता दी है उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, आज के बजट में भी 1 हजार कॉआपरेटिव कस्टम हायरिंग सेन्टर्स का ऐलान किया है। मुझे खुशी है कि 200 विधान सभा क्षेत्रों में से 1 नम्बर पर सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा कस्टम हायरिंग सेन्टर हमारी सरकार ने दिये हैं। 25 हजार फार्म पोण्ड और 10 हजार डिग्गियां, 20 हजार सिंचाई पाइप के जो हमारे इलाके में दिये हैं, उसके लिए मैं किसानों की तरफ से इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। 50 हजार नये कृषि कनेक्शन देना अपने आप में किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। कृषि कल्याण सेस का जो पिछली सरकार, जादुगर सरकार ने किसानों की जेब पर डाका लगाया, कृषि कल्याण सेस के माध्यम से आज उसमें भी बड़ी छूट हमारी राजस्थान की सरकार ने देकर किसानों को लाभ पहुंचाया है।

माननीय सभापति महोदय, गन्ना उत्पादक किसानों को जहां 11 रुपये प्रति क्विंटल की छूट देकर, आज गंगानगर के किसानों को बड़ी राहत दी है। गंगानगर की जो शुगर मिले हैं, आज सुबह भी प्रश्न काल में उस पर चर्चा आयी। माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धरा राजेजी ने उस समय उसके लिए 2013 में जो बजट दिया, एक साल में नई शुगर मिल तैयार हो गयी, आज राजस्थान की तीसरे नम्बर की प्रोफिट अर्निंग कम्पनी है जो 113 करोड़ का लाभांश राजस्थान की सरकार को दे रही है। मेरी मांग है कि गंगानगर में शुगर मिलों की संख्या बढ़ायी जाये, जहां गंगानगर में 23 लाख क्विंटल गन्ना पैदा होता है, 14 6 लाख क्विंटल गन्ना ही हमारी शुगर मिल वहां पर पिराई कर पाती है, अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ायी जायेगी तो लाभ भी ज्यादा प्राप्त होगा और इसके साथ-साथ हमारे को आमदनी भी ज्यादा होगी, किसानों को आमदनी ज्यादा होगी।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के क्षेत्र में हमारे को दी गयी सौगात का धन्यवाद करता हूं। सैनिक स्कूल का जो बड़ा हमें उपहार दिया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं। मिर्जेवाला के लोगों ने आतिशबाजी करके इसका जश्न मनाया है, पूरा गंगानगर इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभारी है।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट आपके लेना चाहूंगा।

गंगानगर के साथ में जो अनूपगढ़ जिले की घोषणा की, 5 साल का मौका कांग्रेस को मिला और 17 मार्च 2023 को अनूपगढ़ को जिला बनाने की थोथी घोषणा की, जिसका एक पैसा वहां नहीं लगाया। आज मैं अनूपगढ़ जहां पर कांग्रेस का एमएलए है, और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली देखिये, अनूपगढ़, अनूपगढ़ के लिए आज जहां उन्होंने नवीन आईटीआई कॉलेज सूरतगढ़ में जहां हमारा एमएलए नहीं है, ट्रोमा सेंटर रायसिंहनगर में जहां हमारा एमएलए नहीं है, अनूपगढ़ में मिनी फूड पार्क, अनूपगढ़ में एडीएम ऑफिस, अनूपगढ़ में सावित्री बाई फुले छात्रावास, अनूपगढ़ में स्पोर्ट्स के लिए इण्डोर हॉल, अनूपगढ़ में ऑडिटोरियम, अनूपगढ़ घड़साना में न्यू कॉलेज और हमारे अनूपगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इन्होंने सिर्फ जिला बनाने का काम किया है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य ताराचन्दजी।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): आज हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया है। मैं एक बात और करना चाहूंगा, सर, एक मिनट का समय लेना चाहता हूं।

श्री सभापतिः ताराचन्द जी।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ में नशा एक बहुत बड़ी बीमारी थी, उस पर सरकार ने जिस सख्ती के साथ पुलिस और प्रशासन ने जिस सख्ती के साथ काम किया है, आज उसका असर दिखने लगा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नशा मुक्ति केन्द्र दिये हैं, उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता ने मुझे यहां पर चुनकर भेजा, इसलिए श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की जनता का भी मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, बड़ा महसूस हो रहा है, हम लोग तो नये चुनकर आये हैं, किन्तु मैंने पिछले दो-तीन दिनों में देखा कांग्रेस का हाल, यह राजस्थान की 8 करोड़ जनता हमें यहां पर चुनकर और अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए भेजती है, न कि यहां पर ठुमका लगाने के लिए, न कि नाचने के लिए, न कि किसी को अपशब्द बोलने के लिए,

अध्यक्षजी को जो शब्द बोले गये हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बैठे थे विधान सभा के अन्दर में, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाये, यदि कोई बाहर होता तो हम भी उनको बताते कि ऐसे शब्द कैसे बोले जाते हैं। ऐसे शब्द उनने बोलकर उन्होंने जो इस सदन का अपमान किया है, इसके लिए वो माफी के योग्य नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, उन लोगों को भी जनता ने चुनकर भेजा है, अपनी समस्या के निवारण के लिए भेजा है, वो उनकी समस्या रखते, समस्या का निदान करवाते, मुख्य मंत्री से कहते कि हमारे क्षेत्र में यह समस्या है इसका निवारण करो, उनको अपनी जनता की समस्या की चिंता नहीं है। उनको अपनी राजनीति चमकानी है, अपने आप को चमकाना है कि कैसे हमें जनता पेपरों में देखें, कैसे लोग हमें पढ़ें तो लोग उत्सुकता ने उनको पढ़ते नहीं हैं, लोग उनको धिक्कारते हैं, लोग कहते हैं कि यह क्या कर रहे हो?

माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो किया, जल जीवन मिशन जैसी योजना को उन्होंने ठण्डे बस्ते में डाल दिया। लोगों को, राजस्थान में पानी की भयंकर समस्या है, किन्तु उस समस्या का उनको किंचित मात्र भी चिंता नहीं है। जल जीवन मिशन में केन्द्र सरकार ने इनको जो भी पैसा दिया उसको इन्होंने ऐसा मटियामेट किया, कहीं पर पाइपें बिछा दीं, कहीं पर नल लगा दिये, कहीं पर टंकी बना दी, पानी का कोई नाम नहीं, पानी कहां से आयेगा, कैसे आयेगा, उसकी चिंता नहीं और पूरे के पूरे जल जीवन मिशन के जो भी पैसे इनको मिले पूरा का पूरा इन्होंने खुलकर भ्रष्टाचार किया और इस भ्रष्टाचार के कारण से आज भी राजस्थान की जनता दु:खी है। उसको पीने के पानी के लिए समस्या है और उस समस्या से निजात पाने के लिए अब क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा की नजरों से ताक रही है।

MLS/RTM/25.02.2025/16:40/3c

सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय बिजली की स्थिति इतनी दयनीय थी कि बिजली 6-6, 8-8 घण्टे तक आती ही नहीं थी। जहां आती थी, वहां वोल्टेज नहीं आता था, बार-बार ट्रिपिंग हो जाती थी, किसानों की मोटरें जल जाती थीं। किसान खून के आंसू रो रहे थे। किसानों की हालत यह हो गयी थी कि हमारे क्षेत्र में 14-15 क्विंटल बीघे की मूंगफली होती है, वह 2 क्विंटल भी नहीं हुई और किसानों की माली हालत इतनी ज्यादा खराब हो गयी कि वे देख रहे थे कि अब हम क्या करें, किसानों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी हमारी भजन लाल जी की सरकार आयी और यह बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हुई।

इससे यह जो पिछली बार मूंगफली का सीजन गया है, इसमें हमारे 15, 16, 18 क्विंटल बीघे तक की मूंगफली हुई है। अब भी जो फसल है, वह बहुत बढ़िया फसल है। पूरे राजस्थान नहीं, मैं तो अपने विधान सभा क्षेत्र की बात बताऊं, मेरे विधान सभा के इस बजट से पूरे के पूरे लोग बहुत खुश हैं और आतिशबाजी बजाकर और पटाखे फोड़कर खुशियां मनायी हैं कि राजस्थान सरकार ने इतना बढ़िया बजट दिया है। मुझे तो बहुत ही बढ़िया बजट दिया है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र को बहुत बढ़िया बजट दिया है। विधान सभा के सारे लोग खुश हैं।

वहीं मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा, यह जो पूर्ववर्ती सरकार थी, इसने क्या किया, गरीबों का राशन डकारने के लिए अपने लोगों को, जो धन्नासेठ थे, उन्हें बीपीएल में जोड़ दिया। उन्होंने गरीबों का राशन डकारने का काम किया। मैं हमारे मुख्य मंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी और हमारे खाद्य मंत्री सुमित जी गोदारा का धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने कड़ाई से इस नियम को लागू किया। इसे लागू करने से लगभग 11 लाख ऐसे लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिये कि हम राशन नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें कह दिया गया कि आगे से आप सरेंडर नहीं करेंगे तो आप पर मुकदमा होगा, इसीलिए उन्होंने सरेंडर किया। देखिये, कितना भ्रष्टाचार किया है इन लोगों ने। यह सारा भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार की देन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बजट पर बोलूं, उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो यह बजट पेश किया गया है, इससे पूरा प्रदेश प्रफुल्लित है। प्रदेश की उप मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। इस बजट में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीब, व्यापारी वर्ग सहित ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा, जिसमें किसी को कुछ न कुछ नहीं मिला हो। हमारे प्रदेश के आम नागरिक इस बजट को लेकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ जन कल्याण तथा सुशासन की अवधारणा को लागू करने के लिए प्रदेश की बागडोर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी के हाथों में सौंपी है, उस दिन से ही प्रदेश सर्वांगीण विकास के पथ पर है। यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश में अद्भुत प्रगति हो रही है, जिसे पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी, जिन्होंने हमारे देश का मान-सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है, उन्हीं के पद चिह्नों पर चलते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने प्रदेश का जिस प्रकार से सर्वांगीण विकास करने की सोच के साथ बजट में सभी को लाभान्वित किया है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, प्रदेश की सरकार और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट ने हमें कई सौगातें दी हैं। काफी सड़कें दी हैं। हमारे क्षेत्र के अन्दर मैं बताऊंगा तो बहुत लम्बी लिस्ट है, समय नहीं है। सभापति महोदय, हमें इस क्षेत्र में बहुत लम्बी-लम्बी सड़कें दी हैं। लगभग-लगभग 150 किलोमीटर की सड़कें हमें दी हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है हमारे लिये। हमें आज तक नहीं मिलीं। सभापति महोदय, सड़कों की मांग हमारे क्षेत्रवासियों की बहुत लम्बे समय से चली आ रही थी, जिसे आज पूरा किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और साथ ही यह कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की लम्बे समय से चली आ रही मांग, जो औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए थी, हमारे पिछले 40 सालों से कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं था, उसके लिए

158 हैक्टेयर, लगभग-लगभग 600 बीघा के अन्दर औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा करके हमें एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जिससे हमारे क्षेत्र में व्यापारियों, मजदूरों और लोगों को काम मिलेगा और लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, सम्पूर्ण विश्व एवं देश के साथ ही प्रदेश को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा सस्टेनेबल ग्रीन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन बजट के अन्तर्गत 74 हजार 854 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस ग्रीन बजट से प्रदेश में कृषि, पशु पालन, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, भूमि प्रबन्धन तथा पर्यावरण संरक्षण के कार्य को बढ़ावा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया है, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे किसान भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण अंचल के क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से अनेकों सौगातें दी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र, जिसकी अधिकतर जनता गांवो में निवास करती है, क्षेत्र में पेयजल के अति दोहन होने के कारण हमारा क्षेत्र डार्क जोन में चला गया है। वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में एक सहायक अभियन्ता तथा चार कनिष्ठ अभियन्ता के पद स्वीकृत हैं, परन्तु क्षेत्र का भू-भाग विस्तृत होने के कारण प्रभावी निरीक्षण नहीं हो पाता तथा ग्रामीणों की पेयजल की समस्याओं का निवारण भी त्वरित नहीं हो पाता है। अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) का नवीन पद स्वीकृत करवाएं, जिससे आमजन को लाभ मिले।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीडूंगरगढ़ की आबादी 1 लाख से अधिक है और बसावट भी एक कटोरीनुमा होने के कारण आबादी क्षेत्र में जगह-जगह सीवरेज नालियों का पानी जमा हो जाता है।

श्री सभापतिः प्लीज समाप्त कीजिये।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): ड्रैनेज व सीवरेज नहीं होने के कारण से जगह-जगह जल भराव हो जाता है। इस कारण लोग बीमार रहते हैं और महामारी की आशंका हर वक्त बनी रहती है। अतः अमृत-2.0 योजना के अन्तर्गत आरयूआईडीपी के माध्यम से सीवरेज और ड्रेनेज की योजना बनवाकर यह कार्य करवाया जाये, जिससे क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके और वह सुकून से शहरी क्षेत्र में निवास कर सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में अधिकतर किसान कृषि आधारित कार्यों को करते हैं। सिंचाई जल के लिये बिजली की अति आवश्यकता रहती है। गत बजट में गुसांईसर बड़ा में 132 केवी जीएसएस लगाने की घोषणा की गयी थी। उसे बढ़ाकर परिवर्तन करके 220 केवी जीएसएस करवाने की उचित कार्यवाही करवाएं तथा उपनी में 33/11 का जीएसएस खुलवाने की उचित कार्यवाही

करवाएं, जिससे क्षेत्र में किसानों को सिंचाई सुविधाओं का और अधिक लाभ मिल सके।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये। श्री हरिसिंह जी रावत।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): श्रीडूंगरगढ़ में बिजली एईएन ऑफिस प्रथम, द्वितीय तथा उपनी तीन सब-स्टेशन हैं। एक एईएन सब-स्टेशन गुसांईसर बड़ा में खुलवाने हेतु उचित कार्यवाही करवाएं, जिससे क्षेत्र के किसानों को निर्बाध एवं सुचारु बिजली मिल सके।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा 2025-26 पर बोलने का जो आपने मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): श्रीडूंगरगढ़ से दुसारा, किसानों के पुराने रास्ते रेलवे ने बन्द कर दिये हैं, जो खेतों में जाने के लिए बहुत ही दूभर हैं। उनको 10-15 किलोमीटर चलकर अपने खेतों में जाना पड़ता है।

श्री सभापति: प्लीज समाप्त कीजिये, अंकित नहीं होगा।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): 000

श्री हरिसिंह रावत (भीम): जैसा कि आपको विदित है, हमारी भजन लाल सरकार का एक सपना है कि हमारा राजस्थान एक विकसित प्रदेश बने। इसी अनुरूप हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी का भी सपना है कि मेरा भारतवर्ष किसी जमाने में कहा करते थे कि एक सोने की चिड़िया था और विश्व गुरु था। 'था' को 'है' में परिवर्तित करने केलिये हमारी डबल इंजन की सरकार, इधर मोदी सरकार, इधर भजन सरकार, दोनों मिलकर, एक हमारा आत्म निर्भर भारत बने, सक्षम भारत बने, इसी सपने को संजोते हुए हमारी सरकार ने योजना बनायी।

कहते हैं न, इस धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्ति का एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार मिले। उसी अनुरूप हमारी सरकार ने योजना बनायी और उसी के माध्यम से हमारी सरकार ने आज पूर्व बजट और इस दूसरे बजट में जो घोषणाएं की हैं और जो कार्य धरातल पर उतर रहे हैं, वे वास्तव में सराहनीय हैं। राजस्थान की जनता भी इस चीज को देखकर खुश है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने केवल पांच साल तक भय, भूख, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, भू-माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया और जो-जो माफिया होते हैं, उन्होंने पैदा किये।

यही नहीं, उन्होंने तो केवल पांच सालों तक होटलों में ऐश-आराम करने के अलावा कोई कार्य नहीं किया और जनता को ठगा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को कि उन्होंने इस कांग्रेस सरकार की रीति-नीति को बदलकर पुनः एक आयाम कायम किया और हमारा विकसित राजस्थान कैसे बने, उसी अनुरूप उन्होंने योजना बनायी और उसी योजना के तहत हमारी सरकार ने, मैं समझता हूं, ऊर्जा के माध्यम से बात करना चाहता हूं, ऊर्जा में रबी 2025 हेतु विद्युत वितरण की पीक सप्लाई में वृद्धि कर 20 हजार 700 मेगावाट बिजली सप्लाई का प्रावधान किया है।

MKD/RTM/25.02.2025/16:50/3d

आगामी वर्ष 50 हजार नये कृषि कनेक्शन तथा 5 लाख कनेक्शन दिये जायेंगे। हमारे प्रदेश को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री सम्माननीय भजन लाल जी के विशेष प्रयासों से निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने का भी एक प्रस्ताव रखा है। इस बजट वर्ष में 33 केवी जीएसएस मेरे क्षेत्र में डांसरिया व जालपा में दिया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, ऊर्जा के माध्यम से मैं बात करना चाहता हूं, नगरपालिका भीम व देवगढ़ में विद्युत लाइन को भूमिगत किया जाये। विधान सभा क्षेत्र भीम के देवगढ़ में खनन की करीब 300 माइन्सों को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र देवगढ़ में बग्गड़ के आसपास सप्लाई के लिए नवीन सोलर पार्कों की स्थापना की जाए। विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 33/11 केवी जीएसएस की एक नई आवश्यकता हमें महसूस हो रही है, वह किया जाये। नन्दावट भीम में, कालेटरा कुकरखेड़ा में और पारड़ी देवगढ़ में। रीको बग्गड़ में अलग से 33 केवी जीएसएस भी प्रारम्भ किया जाए। कारण कि रीको इंडस्ट्री, पूर्ववर्ती सरकार ने, मेरे कार्यकाल 2013 में यह रीको बनाया गया था, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं आ सका, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद रीको इंडस्ट्री में उद्योगपति आने वाले थे, हम कुछ फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो हमारे पूर्ववर्ती के नुमान्इदे कहते कि हमारा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। इसकी वजह से उन्होंने कोई फैक्टरी प्रारम्भ नहीं की। जब हमारी भजन सरकार आई और हम आए और हर क्षेत्र से लोगों से फैक्टरी डालने के जो इच्छुक थे, वे आये और आज वे हमारे यहां 15 से 20 फैक्टरियां डाल चुके हैं। वहां अलग से जीएसएस नहीं है। रीको इंडस्ट्रीज ने जीएसएस के लिए एक जमीन आवंटित कर रखी है, केवल सरकार घोषणा करके वह जीएसएस लगा दे तो मैं समझता हूं कि हमारा चहुंमुखी विकास होगा और हमारी रीको इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।

इसके साथ-साथ, मैं सड़क विभाग की बात करना चाहता हूं। आगामी वर्ष स्टेट हाइवे, बाइपास रोड, फ्लाई ओवर, एलिवेटड रोड, आरओबी व आरयूबी ब्रिज आदि के निर्माण, रिपेयर तथा उन्नयन के कार्य हेतु 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत का प्रावधान किया गया है। अर्थव्यवस्था की जीवनधारा के रूप में 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक लम्बाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के कार्य का प्रावधान किया गया है, जिसकी लागत 60 हजार करोड़ आने वाली है। क्षतिग्रस्त सड़कों को सुधारने के लिए 21 हजार किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से चरणबद्ध किये जाए, ऐसा हमारी सरकार का प्रस्ताव रखा हुआ है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों का कार्य, मरुस्थलीय क्षेत्र में यह राशि 15-15 करोड़ रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र प्रस्तावित है।

सभापति महोदय, मैं इसमें कुछ संशोधन कराना चाहता हूं, जहां 10-10 करोड़ रुपये नॉन

पेचेबल, इसमें मिसिंग लिंक भी कर दिया जाए तो जहां जो आवश्यकता होगी, हम उसके अनुसार काम करा सकेंगे। इसमें मिसिंग लिंक भी जोड़ा जाये, ताकि हमारे विधायकों को जहां-जहां भी आवश्यकता लगती है, हमें यहां मिसिंग लिंक देना चाहिए तो उसमें एक सुविधा मिलेगी। इसके साथ-साथ प्रधान मंत्री सड़क योजना में 1 हजार 600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से आगामी 2 वर्षों में डामर सड़कों से जोड़े जाने का प्रावधान भी किया गया है।

समस्त सम्भागीय मुख्यालय पर कॉम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान भी बनाये जाने का प्रावधान किया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र भीम के देवगढ़ से आमेट वाया मादरी-लसाली-ताल सड़क 40 किलोमीटर, लागत 40 करोड़ रुपये की राशि का जो प्रावधान रखा है, उसमें मैं कुछ संशोधन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, यह 40 किलोमीटर की जो रोड है, वह पूर्व में ही बन चुकी है। उसकी इस समय हमें आवश्यकता नहीं है, उसकी तो केवल जांच की आवश्यकता है, जो पूर्व में रोड बना था, इतना क्षतिग्रस्त है, अभी बना नहीं, उससे पहले ही पूरी पपड़ी उखड़ गई है और जगह-जगह खड्डे पड़ गये हैं तो उसकी जांच कराई जाये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम के अन्तर्गत स्टेट हाईवे, बाइपास रोड, फ्लाई ओवर, एलिवेटेड रोड, आरओबी व आरयूबी ब्रिज आदि के निर्माण, मरम्मत तथा उन्नयन के कार्य के अन्तर्गत, पेज नम्बर 13, कॉलम संख्या 15 में क्रम संख्या 24, मादरी एसएच-12 से लसानी ताल एनएच-8 वाया आमेट की सड़क की घोषणा की गई है, वह ऑलरेडी बन चुकी है। उसकी जगह मैं चाहता हूं कि 2025-26 के बजट में, इसमें सुदृढ़ीकरण एवं चौडाईकरण कार्य, एनएच8 बग्गड़ से ढाक का चौड़ा सड़क, इसमें केटेगरी वीआर, लम्बाई 8 किलोमीटर, राशि करीबन 1200 लाख होगी। दूसरा, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य, ओडीआर-12 आमनेर से एनएच-148 डी समेलिया वाया पालरा-तितरी सड़क, वीआर, 10 किलोमीटर, इसमें 1250 लाख की लागत आयेगी। तीसरा, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य, एसएच-61 से ताल सड़क एसएच-56 वाया झांकरा, पुनियाना, मालकोट और मलकमालिया सड़क कार्य, इसका वीआर और 13 किलोमीटर रहेगा, इसमें 2080 लाख का खर्चा आयेगा।

सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य, बरार से टॉडगढ तक सड़क कार्य, वीआर, 7 किलोमीटर और 1050 लाख का इसमें खर्चा आयेगा। देवगढ़ से एनएच 58 सड़क कार्य, 2 किलोमीटर, इसमें 300 करोड़। देवगढ़ से एनएच-58 वाया गोशाला सड़क कार्य, इसमें 4 किलोमीटर और 600 लाख का खर्चा आयेगा, कुल 44 किलोमीटर जो इन्होंने 40 किलोमीटर किया, इसमें 44 किलोमीटर होता है और इसमें 6 हजार 480 लाख का खर्चा आयेगा। इसी अनुसार हमारा यह कार्य हो जाता है तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा हो जायेगी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए मिसिंग लिंक से 10 किलोमीटर की जगह 30-30 किलोमीटर किया जाए तो मैं समझता हूं, हमारे विधायकों को भी एक बहुत अच्छी सहूलियत मिलेगी। इस पर भी थोड़ा गौर और विचार किया जाए।

दूसरा, क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास विभाग। पंच गौरव योजना को गति देने के लिए 500

करोड़ रुपये के कार्य करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत बजट राशि 50 करोड़ को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपया किया गया है। इसके लिए, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना, 3 हजार 400 लाख मानव दिवसों का सृजन किये जाने का प्रावधान रखा गया है। स्वामित्व योजना के अन्तर्गत समस्त राजस्व ग्रामों को ड्रोन सर्वे करवाकर 2 लाख परिवारों को नये पट्टे वितरित किये जाने का प्रावधान है।

सभापति महोदय, इसमें मेरा एक सुझाव है, नरेगा कार्य योजना के अन्तर्गत जो काम किया जाता है, उसमें अगर संशोधन करके प्रत्येक ग्राम में फलदार वृक्षारोपण कराया जाए और साथ-साथ उन्हीं नरेगा कार्य मजदूरों को जिम्मेदारी दी जाये कि इनका पालन-पोषण करना, पानी पिलाना और यदि यह हो गया तो मैं समझता हूं कि इससे एक तीर से दो शिकार होंगे। हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, साथ ही साथ फलदार वृक्ष यदि लगेंगे तो इससे हमारे क्षेत्र की आय भी बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि पूरे राज्य में यह योजना लागू कर दी जाए तो राजस्थान फल, फ्रूट में एक्पोर्टर बन सकता है। यह भी एक विचारणीय बिन्दु है, इस पर भी गौर किया जाए।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, एक मिनट।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। प्रदेश में आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3 हजार 500 करोड़ का मां कोष गठित किये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकतानुसार घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाये जाने की एक बहुत अच्छी योजना बनाई है, इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसमें मेरी एक छोटी सी डिमांड है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उप जिला चिकित्सालय, भीम को जिला चिकित्सालय, भीम में क्रमोन्नत किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्न किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का आपसे अनुरोध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुआथल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुंदवा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाए और उप जिला चिकित्सालय, भीम में डॉक्टर्स एवं अन्य कर्मचारियों हेतु उप जिला चिकित्सालय, भीम परिसर में ही रहने हेतु निवास स्थान की व्यवस्था की जाए, धन्यवाद।

श्री सभापतिः महेन्द्र पाल जी मीणा। (अनुपस्थित)

श्री विश्वराज सिंह जी मेवाड़।

श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ (नाथद्वारा): आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे बजट के बारे में अपने विचार रखने के लिए इजाजत दी, उसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी को इस बजट के लिए बधाई देता हूं। पिछले कुछ दिनों से

भले सदन में हो या सदन के बाहर हो, बजट के समाचार और बजट के बारे में बातें चलती आ रही हैं। इस तरफ 100 करोड़, दूसरी तरफ 1,000 करोड़, 3 लाख करोड़ से ज्यादा बजट, ऐसे जो आंकड़े हैं, उन्हीं के बारे में बात हो रही है।

Bhs/Rtm/25.02.25/17.00/3e

लेकिन इन आंकड़ों का मतलब क्या है? इन आंकड़ों का मतलब हम टुकड़े-टुकड़े में नहीं समझ पायेंगे क्योंकि हम बजट को सब साथ में ही पढ़ें और अगर तीन-चार सालों के बजट अगर हम साथ में पढ़ें, अर्थशास्त्र का कुछ ज्ञान हो, अर्थशास्त्रियों से कुछ मदद लें तभी इन आंकड़ों का अर्थ हम पूरी तरह से समझ पायेंगे। इसके अलावा ये तो बड़े आंकड़े हैं लोगों में यह भी रुचि होती है कि इस बजट से उन पर व्यक्तिगत तौर पर क्या असर पड़ेगा। जो कमजोर हैं वे सोचते हैं कि बजट में उनके लिए क्या है जो मध्यम वर्ग हैं वे भी राहत की आशा रखते हैं और जो सम्पन्न हैं वे सोचते हैं कि कहीं हमें कुछ और ज्यादा न देना पड़े। यह तो स्वाभाविक है।

बजट की बात करें तो आंकड़ों की बात तो करना जरूरी है और जो आंकड़े हैं जो अर्थशास्त्र है वो बजट के लिए जरूरी है क्योंकि वे ही बजट को सीमित रखते हैं क्योंकि बिना इन दोनों के बजट है ही क्या, एक ख्वाबों का पुलिन्दा। हम ऐसे ख्वाबों के पुलिन्दे के शिकार हो गये हैं पहले। 2023-24 के बजट में जैसे घोषणा हुई थी कि एक राजकीय मेडिकल कॉलेज बनेगा जिसके लिए नाथद्वारा में गुंजोल में अस्सी बीघा जमीन आवंटित हुई थी, बाउंड्री वाल का काम भी शुरू हुआ, शिलान्यास भी हुआ लेकिन ये सब काम हुए बिना कोई प्लान के, बिना कॉलेज के प्लान के। तो अब काम रुका हुआ है और मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यह काम शुरू करें। हम विपक्ष को दिखायें कि काम कैसे किया जाता है और नाथद्वारा के लोगों के लिए एक उपलब्धि मिलेगी।

एक दूसरा उदाहरण है, जो नाथद्वारा में हाईवे जा रहा है वह हाईवे जो शहर के बीचों-बीच जाता है, जिसका जो चढ़ाव है, जिसका जो ढलान है, जिसके इतने विकट मोड़ हैं कि मेरे ख्याल से अगर आप उस हाईवे को उठा कर कोई मगरा क्षेत्र में, कुम्भलगढ़ में, ब्यावर में लगाते हैं तो जैसा है वैसा ही काम में आ जायेगा। और तो और, विकट मोड़ के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं और जो म्युनिसिपैलिटी के काम हैं उनके नियम हाईवे से मिलते नहीं हैं और काम होने में तकलीफ होती है। एक साल हो गये हैं नाथद्वारा में पानी के पाइप बदलने में। इसके कारण मुश्किल हो रही है, लोगों को मुश्किल आ रही है। तो यह है ख्वाबों के पुलिन्दे के तरीके से किये हुए काम।

इन ख्वाबों से दूर रह कर, व्यक्तिगत स्थिति पर ध्यान रखते हुए, पिछले साल और अबकी बार बजट पेश हुआ है और इन बजट के आंकड़ों से यह तो पता चलता है कि आय क्या है, व्यय क्या है लेकिन इसके अलावा यह भी पता चलता है कि जो सरकार है उसकी

मंशा क्या है, उसका मूल क्या है वो राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहती है। इन सब आंकड़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्प्रिचुअलिटी-टू-साइंस इस बजट में, जैसे हम कह सकते हैं धर्म से लेकर विज्ञान तक सभी चीजें इस बजट में मिलती हैं और सभी वर्ग के लिए, सभी उम्र के लिए कुछ न कुछ चीज है। उदाहरण के तौर पर 56 हजार को तीर्थ यात्रा करवाना, पुजारियों का पैसा बढ़ाना, पांच सौ विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाना, स्वस्थ शिशु के लिए अन्तिम पांच महीनों से गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त पोषण के लिए मुख्य मंत्री सुपोषण न्युट्रीकिट योजना, दिव्यांगजनों के लिए आर्टिफिशियल लिम्ब इक्विपमेंट उपलब्ध करवाना, अन्य चिकित्सा सुविधा, फिट राजस्थान पर जोर दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए जिम्स, स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग, ज्ञान केन्द्र, रोजगार के लिए सरकारी नौकरियां, कैम्पस इंटरव्यूज, अम्बेडकर इंस्टिटयूट ऑफ कंस्टिट्यूश्नल स्टडीज, श्रीअन्न से बना मिडडे मील, भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कृषि यंत्र, ट्राइबल टूरिस्ट किट, काश्तकार के लिए राजस्थान वाटर ग्रिड कारपोरेशन, पेयजल की व्यवस्था, कर एम्नेस्टी स्कीम, बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी; अब यह सब एक सूची है और इस सूची से पता चलता है कि यs काम किसलिये हैं और बाकी बजट में जो काम लिखे हुए हैं अगर मैं उन्हीं को भी एक सूची के रूप में पढ़ूं तो शायद जो समय मुझे दिया गया है वो कम ही पड़ेगा।

नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी इस बजट में लिखा गया है। यह पहले एक ग्रीन बजट है और हमें यह ध्यान रखना है कि जो पर्यावरण के कानून हैं जो प्रकृति के कानून हैं वो सर्वोपरि हैं। आपका विज्ञान भले कितना भी आगे हो लेकिन लम्बे तौर पर प्रकृति के कानून ही चलते हैं। शायद इसके द्वारा जो हमारा नुकसान हुआ है इन सालों में तालाबों में, पेड़ों में, मगरों में कुछ सुधार हो जैसे मिशन हरियाली है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी है, क्लीन एंड ग्रीन टैक्नॉलॉजी डवलपमेंट सेन्टर हैं ये सब इसी चीज में मदद करेंगे और पर्यावरण की जो महत्ता है उसे स्वीकारते हुए और भी प्रस्ताव है जैसे कि क्लाइमेट चेंज, एडप्शन प्लान 2030, सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फोर क्लाइमेट चेंज, एग्री फॉरेस्ट्री पॉलिसी, नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन, बैलों से खेती करवाने वालों को प्रोत्साहन, वाटर हार्वेस्टिंग, हरित अरावली विकास परियोजना, ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान, ग्रीन एनर्जी, रिसाइक्लिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल, सर्कुलर इकॉनॉमी, वेस्ट-टू-वैल्थ पार्क, प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन बैंक्स, ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म, ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी, राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड भी प्रस्तावित हैं।

यह एक पहला ग्रीन बजट है और इससे हमें संकेत मिलता है कि जो अब पर्यावरण का नुकसान हुआ है, उसका सुधार करने में हम लगे हुए हैं और यह भी संकेत मिलना चाहिये कि आगे जो भी कार्य सूची बनती है उसमें पर्यावरण हमेशा ही होगा और इस चीज को जो पर्यटक के पीछे, कुम्भलगढ़ हो, उदयपुर हो, नाथद्वारा में जो पर्यावरण का नुकसान करते हैं, यह चीज उन्हें भी समझानी है।

यह एक खुशी की बात है कि क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज की जो पहली सूची है उसमें

नाथद्वारा का नाम भी है और यह जो सामुदायिक सोलर प्लांट्स हैं यह भी ग्रीन प्रस्ताव में मदद ही करेंगे। इसके अलावा जो नाथद्वारा के लिए है वो जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, सीवरेज है, जो नहर का सुधार है, जो श्रीअन्न के लिए आउटलेट्स हैं, जो प्रोटीन पशु आहार के संयंत्र भी प्रस्तावित हैं, इन सभी चीजों के लिए मैं नाथद्वारा की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। शायद दूसरे राज्य नाराज हों लेकिन मेरा यह मानना है कि जो हमारे देश की संस्कृति है, जो गौरवशाली इतिहास है उसका केन्द्र राजस्थान है और शायद आप में से कुछ मुझसे नाराज हों, मैं मानता हूं कि इन चीजों के लिए राजस्थान में एक केन्द्र मेवाड़ है और इसी धरती में जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है जो महत्वपूर्ण सत्र में रुकावट आयी है, यह दुखद ही नहीं है बल्कि शर्मनाक भी है।

इन सालों में एक तरह से एक रीति हो गयी है कि जब कोई बजट के बारे में बात करे तो शायद रूखे-सूखे आंकड़ों में जान डालने के लिए कविता या कोई शायरी का उपयोग किया जाता है। मेरा तो यह मानना नहीं है कि कोई भी कवि या कोई भी शायर बजट से प्रभावित होकर अपनी कविता या अपनी शायरी लिखा होगा। फिर भी इसी चीज में ज्यादा गौर से न देखते हुए हम यह तो अवश्य कह सकते हैं कि यह बजट ताल और सुर मिला कर ही बना है।

आप सभी ने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री लालाराम जी बैरवा।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट सत्र में बोलने का अवसर प्रदान किया। राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के इस बजट में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की अवधारणा को फलीभूत करने के लिए निरन्तर अग्रसर होकर प्रयासरत है। प्रदेश की भाजपा सरकार, देश के माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से राजस्थान प्रदेश को विकसित बनाने के लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने अपना बजट पेश किया है। इस बजट में बिजली, सड़क, पानी आदि जैसी बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रख कर यह बजट बनाया है। इस बजट में महिला, युवा, किसानों एवं बेरोजगारों आदि के लिए बड़े एलान किये गये हैं, यह बजट अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देने वाला बजट है जो महिलाओं को सशक्त बनाने एवं किसानों को समृद्ध बनाने, उन्नत स्वास्थ्य और आमजन के खुशहाल जीवन और युवाओं के लिए सुअवसर लाने और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में ले जाने वाला बजट है।

Kas/rtm/25.02.2025/17.10/3f

राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के सरकार के लक्ष्य के तहत अगले चार वर्षों के लिये सरकार की परिकल्पना को भी पेश किया गया है। इस वर्ष बजट में किये गये वादों की

प्रगति की जानकारी भी दी गई है, जिसमें 60 प्रतिशत से अधिक वादों को पूरा करने का कार्य आदरणीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा की सरकार ने पूरा किया है। यह बजट हर व्यक्ति की आकांक्षाओं एवं सपनों को पूरा करने वाला बजट है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

'जीत की खातिर बस जनून चाहिये, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिये,
यह आसमान भी आयेगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिये।'

मैं हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री जी एवं उप मुख्य मंत्री आदरणीय श्रीमती दिया कुमारी जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शाहपुरा-बनेडा विधान सभा क्षेत्र के आधारभूत ढ़ांचे को मजबूत करने के लिये कई विकास कार्यों को बजट में शामिल किया है। विकास के यह कार्य हमारी सरकार के समग्र एवं समावेशी विकास की स्पष्ट अवधारणा को दिखाता है। बजट में सम्मिलित विकास कार्यों के सन्दर्भ में मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि आपने मेरे क्षेत्र की लंबे समय से की जा रही मांगों को पूरा किया है।

आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान में पिछली बार 2023 में कांग्रेस सरकार का शासन था। कांग्रेस राज में प्रदेशभर के पुलिस स्टेशनों में करीब 3.17 लाख एफआईआर दर्ज थीं। कांग्रेस के शासन काल में अपराधियों को केवल संरक्षण प्रदान करने का कार्य किया जाता था और जनता के साथ सिर्फ कुठाराघात किया जाता था। कांग्रेस राज में सिर्फ बजरी माफिया, भू-माफियाओं को पनपाने का काम किया जाता था। कांग्रेस राज में आमजन ने अपने आपको सदैव असुरक्षित महसूस किया है। आज साल बदलने के साथ ही प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार है। माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में 2024 के दौरान पिछले एक साल में एफआईआर की संख्या घटकर 3.97 लाख रह गई है। प्रदेश में शासन बदलने के साथ ही आंकड़े देखने पर करीब 20 हजार एफआईआर कम दर्ज होना सामने आया है। आज आमजन मजबूत कानून व्यवस्था के चलते राहत की सांस ले रहा है। आज अपराधियों के मन में डर उत्पन्न है। आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में आज वास्तव में आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय व्याप्त है। फ्री रजिस्ट्रेशन के बावजूद कम एफआईआर दर्ज हुई हैं। भाजपा सरकार में माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था में सख्ती के चलते एफआईआर की संख्या में गिरावट के साथ ही अपराध का ग्राफ भी गिरा है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा त्वरित न्याय के सिद्धांत पर काम करते हुए परिवादियों को राहत दी है। इसके चलते ही पिछले साल के मुकाबले प्रदेश में पेंडेंसी दर घटकर 3 प्रतिशत से कम हो गई है। केस की डिस्पोजल दर भी 20 प्रतिशत से घटकर 17 प्रतिशत पर आ गई है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी व नगर विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा साहब से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल मेरे विधान सभा क्षेत्र, पूर्व जिला मुख्यालय शाहपुरा में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं और एक विशेष समुदाय के लोग घरों में घुस कर पालतू जानवरों को उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसे

में घरों में घुस कर कीमती सामानों को भी चुराया जा रहा है। शहर में चोरों का आतंक है। माननीय मंत्री महोदय से मेरी विशेष मांग है कि शहर में कैमरे लगाने के लिये विशेष बजट शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र को दें, जिससे वहां पर कैमरे लगें और चोरों पर अंकुश लगे।

आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान को खुशहाली के पथ पर अग्रसर करने के लिये आवश्यक है कि कानून व्यवस्था सतत रूप से बनी रहे। आमजन, विशेषकर हमारी बहन-बेटियां पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव करें तथा साइबर क्राइम पर प्रभावी अंकुश लगाकर अपराधियों को कठोर सज़ा दिलाने का काम करें। आज भी विजय नगर में हुई जैसी घटनाएं हमें शर्मसार करती हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि किसी भी छोटी घटना को बहुत बड़ी बना कर प्रदर्शन करने वाले हमारे कांग्रेसी नेता इतने बड़े सुनियोजित षड्यंत्र पर भी मुंह पर ताला लगा कर बैठे हैं, क्योंकि यह उनकी राजनीति को सूट नहीं करता है। इसलिए आदरणीय सभापति महोदय, ऐसी घटनाओं पर राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर कठोर कार्यवाही करने के पक्ष में खड़ा होना चाहिये।

आदरणीय सभापति महोदय, शुद्ध पेयजल सबको मिले, यह आज भी कई क्षेत्र में एक चुनौती बना हुआ है। हम जानते हैं कि पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा पेयजल समस्या के समाधान पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। यहां तक कि जल जीवन मिशन योजना में भी घोटाले के प्रयास किये गये, लेकिन हमारी सरकार द्वारा अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिये मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, इससे हमारे क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी योजनाएं बनाते समय हमारी प्राचीन विरासतों को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, इसका भी ध्यान रखा जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने आनन-फानन में जो 19 जिले घोषित किये थे, उनमें शाहपुरा जिला भी एक है। बिना मापदंड के, बिना सीमांकन के शाहपुरा को जिला घोषित किया गया था। अभी वर्तमान में हमारे पूर्व आई.ए.एस. ललित के पंवार जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट में कुछ जिलों को मापदंड पूरा नहीं होने के कारण हटाया गया, जिसमें मेरा जिला शाहपुरा भी था। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, शाहपुरा पूर्व रियासतों के समय से जिला रहा है और यहां पर रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ भी रही है।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट लूंगा। यह अनेक वीरों के बलिदान की धरती भी रही है। इसलिए पूर्व से इसका सीमांकन किया जाये और इसमें रोजगार की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इसको पुन: जिला बनाने पर हमारी सरकार को विचार करना चाहिये। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री उमेश जी मीणा।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर से आपको खूब-खूब धन्यवाद, जोहार।

सभापति महोदय, इस बजट की घोषणा 19 तारीख को हुई, मैंने लगातार 3-4 दिन इस बजट को पढ़ा। बजट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस बजट से प्रदेश की जनता को जो उम्मीद थी, जो गांवों में उम्मीद थी, उस आधार पर यह बजट नहीं दिया गया है।

Msk/rtm/25.02.25/1720/3g

आज प्रदेश और देश के अन्दर देखा जाए तो 70 परसेंट जनसंख्या गांवों में निवास करती है और 30 परसेंट जनसंख्या शहरों में निवास करती है, लेकिन इस बजट के अन्दर गांवों के लिए कोई स्पेशल बजट नहीं दिया गया है। यह मुझे निराशाजनक लग रहा है, क्योंकि आज गांवों में सबसे ज्यादा जरूरत है, आज गांवों के अन्दर ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों के लिए तालाब बनाने की जरूरत है, एनिकट बनाने की जरूरत है। हमारी चार-पांच पंचायतों के बीच में अगर एक मिनी डैम बनाया जाये तो किसानों के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था हो सकती है, इस पर बजट देने की जरूरत थी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे गांवों और ग्राम पंचायतों के अन्दर अभी तक आजादी के बाद 78 साल हो गये हैं, उसके बाद डामरीकरण की सड़कें नहीं बनी हुई हैं, उन डामरीकरण की सड़कों की गांवों के अन्दर जरूरत थी। माननीय सभापति महोदय, आज मिसिंग लिंक की जो सड़कें थीं, वे भी सरकार ने बन्द कर दीं। मैं समझता हूं कि उन मिसिंग लिंक की सड़कों के माध्यम से दो ग्राम पंचायतों की सड़कें, जो बीच में रह जाती थीं, उसको जोड़ने का काम करती थीं। वह आम जन की सुविधा के लिए अच्छा काम था, लेकिन इस सरकार में बन्द हो गया। इसलिए यह निराशाजनक बजट साबित हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, उस ट्राइबल एरिये से आता हूं, उदयपुर संभाग से। ...(व्यवधान)... डिस्टर्ब मत करें, माननीय सदस्य महोदय। 1,500 करोड़ रुपये तो लैप्स हो गये हैं, उस पर तो आप कुछ बोल नहीं रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं ट्राइबल एरिये उदयपुर संभाग से आता हूं। इस बजट के अन्दर भी मैंने देखा कि वहां ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए अच्छी है। आज टीएसपी एरिये के अन्दर हमारे साथ अन्याय और भेदभाव सरकार ने किया है तो कहीं न कहीं मैं यह मानता हूं कि सरकार ने +++ की है। आज यह प्रदेश के अन्दर जो बजट है, वह पूरे राजस्थान प्रदेश का बजट है, न भारतीय जनता पार्टी का बजट है। आज मैं भारत आदिवासी पार्टी से विधायक बनकर आता हूं, लेकिन इस विधान सभा में खड़े होकर बोलना चाहूंगा कि कहीं न कहीं प्रदेश के बजट के अन्दर हिस्सा हमारी विधान सभा क्षेत्र की जनता का भी बनता है। सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि यह बजट पूरे

प्रदेश का है या फिर किसी पार्टी विशेष का है। एक तरफ सरकार बोलती है कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस प्रदेश में सब जगह विकास हुआ है। आज मैं इस बजट के अन्दर पढ़ रहा था और कई सारे विधान सभा क्षेत्र देखे।

श्री सभापति: वह +++ शब्द हटा देना।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): मुख्य मंत्री महोदय और उप मुख्य मंत्री महोदय ने 500-500 करोड़ का बजट प्रत्येक विधान सभा में दिया है और हमारे ट्राइबल एरिये के लिए बजट नहीं दिया गया। मैं उम्मीद करूंगा, इस बजट में नहीं मिला, लेकिन पूरक बजट में भी हमारी जो डिमांड है, ये डिमांड मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इस डिमांड को पूरक बजट में जोड़ा जाये, यह मैं आपसे उम्मीद करुंगा।

माननीय सभापति महोदय, उदयपुर संभाग के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक खेल स्टेडियम स्थापित किया जाये ताकि क्षेत्र के युवाओं को खेल में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। दूसरी डिमांड है कि प्रत्येक जिला व ब्लॉक स्तर पर कालीबाई भील आवासीय विद्यालय, छात्रावास खोला जाये, जिससे आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और उन सभी ब्लॉकों में सरकारी महाविद्यालय खोले जायें, जो अभी तक इस सुविधा से वंचित हैं। मैं तीसरी मांग करना चाहूंगा कि ट्राइबल एरिये के अन्दर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में न्यूनतम 25 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण किया जाये, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कें बेहतर हो सकें। मेरे विधान सभा क्षेत्र की डिमांड करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आसपुर सीएचसी है, उसको उप जिला चिकित्सालय क्रमोन्नत किया जाये, जिससे आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा की बात करूंगा। आसपुर मुख्यालय पर सरकारी महाविद्यालय अभी तक नहीं खोला गया है, तो आसपुर मुख्यालय पर सरकारी महाविद्यालय खोला जाये। दोहड़ा ब्लॉक में कृषि विज्ञान केन्द्र तो है, लेकिन वहां पर कृषि विज्ञान महाविद्यालय खोला जाये ताकि क्षेत्र के किसान व छात्र आधुनिक कृषि से शिक्षा प्राप्त कर सके। दोहड़ा ब्लॉक में पालनिठावा में भी सरकारी महाविद्यालय खोला जाये। माननीय सभापति महोदय, साबला ब्लॉक के कटारा क्षेत्र में पालनिठावा में एक सरकारी महाविद्यालय खोला जाये। इस सरकार को यह समझना होगा कि ये केवल मांगें नहीं, बल्कि हमारे क्षेत्र का अधिकार है। इसलिए मैं ये बातें रखना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए खूब-खूब धन्यवाद, जोहार।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र पाल मीणा।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार, आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं हमारे मार्गदर्शक विकास पुरुष यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा का, जिनके कुशल नेतृत्व में हमारी सरकारी ने प्रथम वर्ष पूर्ण कर नये आयाम स्थापित किये, नये कीर्तिमान स्थापित किये। मैं सम्पूर्ण जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की तरफ से

आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। मैं हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी के लिए कुछ पंक्ति बोलना चाहूंगा।

'बिजलियां जब चमकती हैं तो आसमान बदल देती हैं,
आंधिया जब चलती हैं तो दिन-रात बदल देती हैं,
धरती जब दरकती है तो दिशाएं बदल देती है,
जब भजन लाल सरकार ठान लेती है,
तो अपने राजस्थान की सूरत बदल देती है।'

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी का, जिन्होंने हमारी सरकार का दूसरा सम्पूर्ण बजट पेश किया। जिन्होंने पारदर्शी, आदर्श और संतुलित ग्रीन बजट पेश कर इस बात को सार्थक किया कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए हमारी भजन लाल सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इतिहास में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जो बजट आया है, इस बजट के अन्दर युवाओं, महिलाओं, गरीब, किसानों, पिछड़े वर्ग और हर तबके के लिए ध्यान रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, यह बजट ग्रीन बजट, रिनुअल एनर्जी बजट, रूरल बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। हमारी सरकार ने इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में 2750 किलोमीटर से अधिक के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की, यह अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए बड़ी अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में 62 करोड़ से अधिक की नवीन सड़कों की सौगात मिली, इसके लिए मैं यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा व माननीय उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी को मेरे एवं मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं और साधुवाद प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ जयपुर राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी है, परन्तु इतनी कम दूरी पर होने के बाद भी पिछली कांग्रेस सरकारों की वजह से यह अत्यंत पिछड़ा रहा, इसका कारण गत सरकारें हैं। इन गत सरकारों ने और गत जनप्रतिनिधियों ने मेरे क्षेत्र में और क्षेत्रवासियों के विकास पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, परन्तु मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक साल में ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार चांद लगा दिये।

माननीय सभापति महोदय, हमारी राजस्थान सरकार ने इस बजट में युवाओं का विशेष ध्यान रखते हुए बजट में बड़ी घोषणाएं युवाओं के लिए कीं। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए अगले एक वर्ष में 1 लाख 25 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरी निकाली जायेगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी डेढ़ लाख से ज्यादा नौकरियां युवाओं को दिलायी जायेगी। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया था, पिछली सरकार ने युवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा में हुए पेपर लीक,

नकल की घटनाओं से नौजवानों के साथ विश्वासघात हुआ और नौजवानों का परीक्षा परिणाम से भरोसा उठ गया। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कठोर निर्णय लेकर पेपर लीक, नकलचियों को, गत सरकार में हुई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले में करीब ढाई सौ लोगों को गिरफ्तार किया। वर्तमान सरकार में एक भी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुए, जिससे कोई भी भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की घोषणा की, जिसमें युवाओं को दो करोड़ तक के लोन 8 प्रतिशत ब्याज में, सब्सिडी व 5 लाख की मार्जन मनी दी जायेगी। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में नवीन महाविद्यालय, नवीन आईटीआई कॉलेज, नवीन संस्कृत महाविद्यालय, विद्यालयों को क्रमोन्नत। विद्यालयों की मरम्मत, नवीन भवन और अन्य बहुत सारी घोषणाएं कीं, यह अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित है।

mdp/rtm/25.02.2025/17:30/3h

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने किसानों और बुज़ुर्गों का भी ध्यान रखा है। किसानों के लिए पी.एम. किसान निधि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये की घोषणा की गयी। गेहूं की एम.एस.पी. पर 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गयी। इसके अलावा 25 हजार फार्म पोंड, 50 हजार सोलर पम्प, 3 लाख 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सिस्टम के लिए अनुदान किया गया। यह सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों का हमेशा ध्यान रखती है। किसानों की फसल को नुकसान नहीं हो, उसकी तारबंदी के लिए, 30 हजार से ज्यादा किलोमीटर तारबंदी के लिए अनुदान की घोषणा की गयी।

माननीय सभापति महोदय, हमारी भजन लाल जी की सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में 30 लाख किसानों की खेती-बाड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगभग 16 हजार करोड़ ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया और अब इस आंकडे को बढ़ाते हुए 25 हजार करोड़ ब्याज मुक्त ऋण वितरित करने की घोषणा की है। भजन लाल जी की सरकार इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद व साधुवाद की पात्र है।

श्री सभापति: प्लीज, सदस्य, आवाज नहीं।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): हमारी सरकार में 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाने की घोषणा की गयी। ये पथ सीमेंट-कंकरीट से बनेंगे। इसके अलावा प्रत्येक विधान सभा में हर विधायक को 10-10 करोड़ रुपये राशि की सड़कें बनाने की घोषणा की गयी। इसके लिए मैं भजन लाल सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद व साधुवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अरावली पर्वतमाला की ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थिति को

देखते हुए इसके संरक्षण और इसको हरित बनाने के लिए हमारी सरकार ने 250 करोड़ से हरित अरावली विकास परियोजना शुरू करने की घोषणा की। मेरा विधान सभा क्षेत्र भी अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है। चारों तरफ बड़े-बड़े पहाड़, जंगल, बांध, नदी-नाले, अनेक प्राचीन मन्दिर, जो कि लाखों लोगों की आस्था का केन्द्र हैं। यहां पर रामगढ़ बांध स्थित है, जो जयपुर शहर की आत्मा और लाइफ लाइन है, जिसने कई दशकों से जयपुर शहर को पानी पिलाया है। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और राजस्थान के भागीरथ श्री भजन लाल जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने रामगढ़ बांध को राम जल सेतु लिंक परियोजना (ई.आर.सी.पी.) के प्रथम फेज में शामिल कर बांध के लिए 9 हजार 600 करोड़ रुपये पास किये और रामगढ़ बांध में पानी लाने के सपने को साकार किया।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है कि मेरा क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है। गत सरकारों ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकास के ऊपर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय, हमारी वित्त मंत्री महोदय, जिन्होंने गत बजट की भांति इस बजट में भी जमवारामगढ़ के विकास में ध्यान दिया और बड़ी सड़कें, अस्पतालों को क्रमोन्नत करने का काम किया, उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किया, जिसकी घोषणा विधान सभा में हमारी वित्त मंत्री महोदया ने की। परंतु मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में अभी भी विकास कार्य की बहुत कमी है। मेरा क्षेत्र शिक्षा, चिकित्सा और पेयजल जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। गांव आज भी सड़क मार्गों के अभाव में पिछड़े हुए हैं। शिक्षा के लिए बालिकाओं को शहर जाना पड़ता है।

जल जीवन मिशन योजना में पिछली सरकार के घोटालों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी व वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि परिवर्तित बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता देवे, जिसमें हमारे जमवारामगढ़ के एस.डी.एम.कोर्ट से वाया सावधामना होते हुए सावसीरा तक नवीन सड़क निर्माण का कार्य है। दौसा मनोहरपुरा हाईवे से भावनी पावटा खड़ की नवीन सड़क का निर्माण कार्य है। एन.एच. 148, जिसमें झीलपुरा और खारड़ा की ढाणी होते हुए मातासुला की नवीन सड़क का कार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जमवारामगढ़ में एक बालिका महाविद्यालय की बहुत जरूरत है। हमारी आस्था का केन्द्र बांकी माता का मन्दिर, जिसमें एक बड़ा रोप-वे बन जाए, हमारे लाखों लोग उस आस्था में आते हैं।

सभापति महोदय, मैं पुनः इस ऐतिहासिक बजट के लिए आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय और हमारे वित्त मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने भाषण को विराम दूंगा-

'हमारे हौंसलों की इंतहा मत पूछिए साहब,
बहुत दूर हो मंजिल, मगर मंजिल को पा लेंगे हम,

हमारे बाजू में जोर है, सकंल्प हो मन में,

तो कलेजा चीर कर चट्टानों का भी रास्ता बना लेंगे हम।`

जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जी जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण 2025-26 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। राजस्थान का सर्वांगीण विकास करने वाला हमारी सरकार के मुखिया माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में माननीय दिया कुमारी जी, वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया। यह बजट दूसरी बार हमारी सरकार का बजट है। इसमें हमारी सरकार ने गांव, गरीब, मजदूर, किसान, सबका ध्यान रखते हुए शानदार और जानदार बजट रखा। हमारी सरकार गरीब को गणेश मानकर अंतिम पंक्ति में बैठे हुए उस व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए मदद करती है। गांव, गरीब, मजदूर, हर व्यक्ति का भला हो, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके, ऐसा बजट हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया।

राजस्थान विकास में अब जी.एस.डी.पी. वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर 9 लाख 89 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। हमारी सरकार इसी विकास की गति को निरंतर जारी रखते हुए 2030 तक 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार को अभी अल्प अवधि हुई है, हमारी सरकार को 13-14 महीने हुए है बने हुए और लगातार प्रयास किया। 9 हजार 600 किलोमीटर सड़कें नयी बनाने का काम किया और लगभग 13 हजार से अधिक जो सड़कें टूटी हुई पड़ी थीं कांग्रेस राज में उनको ठीक करने का काम किया। हमारी सरकार ने हर व्यक्ति का ध्यान रखने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, इन पांच वर्षों में चार लाख से ज्यादा नौकरी देने का वादा किया। पिछले वर्ष अल्प अवधि में हमने 76 हजार से ज्यादा नौकरियां देने का काम किया और इस बजट में सवा लाख से ज्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरी देने की हमने घोषणा की। हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। निजी क्षेत्रों में लगभग डेढ़ लाख से अधिक नौकरियां देने का हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर में काम करेगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हमारी सरकार आते ही एक हजार से बढ़ाकर 1150 रुपये किया। इस बजट में 1250 रुपये देकर ऐतिहासिक सफलता हमने हासिल की है। किसानों की सम्मान निधि में हमारे केन्द्र सरकार के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी 6-6 हजार रुपये प्रति वर्ष दे रहे हैं। मोदी जी जब सांवरा जी पधारे थे तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 12-12 हजार रुपये करेंगे। इस बार हमारी सरकार ने 3 हजार रुपये और बढ़ाकर के 9 हजार रुपये किये। आने वाले समय में इस 12 हजार की पूर्ति हम करने वाले हैं।

माननीय सभापति महोदय, गरीब को गैस कनेक्शन के बारे में कांग्रेस वाले बहुत हल्ला मचाते थे, तो 450 रुपये में गैस सिलेण्डर गरीब आदमी को मिल सके, ऐसा हमने काम किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन में बैठे हैं, सत्ता पक्ष है, कुछ दूसरी पार्टी

के हैं, लेकिन विपक्ष जो कांग्रेस का कहा जाता है, वह आज नजर नहीं आ रहा है और नजर नहीं आने का कारण यह भी है कि उन्होंने आसन पर टिप्पणी की। आसन के विरोध में इतना बोला और जिस प्रकार से उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, हम सबने आज निंदा प्रस्ताव पास किया। मैं तो यह चाहता हूं कि इसी प्रकार से नियमों को ताक पर रखकर चलेंगे तो जनता आने वाले समय में इनको आईना दिखाने में कसर नहीं छोड़ेगी। आपने देखा होगा अभी दिल्ली प्रदेश के चुनाव हुए थे, उनमें कांग्रेस को जीरो करने का काम किया और आने वाले समय में राजस्थान में भी ऐसा ही होने वाला है। इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है।

अभी अख़बार में प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था, बजट के अगले दिन, उन्होंने कहा कि इस बजट में थोथी घोषणाएं हैं। थोथी घोषणाएं कहां से हैं? आपका जब बजट होता था तो ऊंट में मुंह में जीरा होता था और हमारे तो इतना भारी बजट दिया है, जो आपके खुद के पांव हिल गए हैं। यह राजस्थान इस बजट से आत्मनिर्भर बनने वाला है, विकसित बनने वाला है, सर्वस्पर्शी है और सर्वांगीण विकास करने वाला यह राजस्थान का बजट है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने बुजुर्गों का ध्यान रखा। 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को घर जाकर दवा देने का काम हमारी सरकार करेगी। 750 डॉक्टर्स की भर्ती करेगी और 1500 पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती करके इन युवाओं की सेवा करने का काम करेंगे। 50 हजार से अधिक बुजुर्गों को ए.सी. रेलगाड़ी के अन्दर यात्रा करने का अवसर देगी। हैल्थ के लिए 3500 करोड़ रुपये मां कोष के अन्दर देने की घोषणा की है।

Ans/rtm 17.40 3j 25.02.2025

दस लाख गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना कदम उन्होंने उठवाया है। 150 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। कृषि के लिए पहले बिजली नहीं आती थी, मैं लगातार सदन में आता हूं, हमेशा जनता जनार्दन की कृपा रहती है, जब भी सर्दी का समय होता है उस समय बिजली नहीं मिलती थी, मुझे आज कहते हुए बड़ा हर्ष और गर्व है कि हमारी सरकार ने किसानों को दिन में छह घंटे बिजली देने का वादा किया था वह पूरा कर रही है, इसलिए मैं माननीय भजनलाल जी को बहुत- बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सौर ऊर्जा में भी बिजली को बढ़ावा देकर, सोलर को सब्सिडी के माध्यम से जनता जनार्दन को समर्पित करने का काम किया है।

मैं इतना निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले बजट में कपासन विधान सभा क्षेत्र को इतना दिया जो मैंने मुख्य मंत्री को कहा था कि आपने दिया तो छप्पर फाड़कर दिया। इतना बजट दिया कि 450 करोड़ तो पिछली बार मुझे सड़कों के नाम से दिये थे, उनमें नवीन सड़कें बनी, ब्रिज व बाईपास, पुलियाएं बन रही हैं, और वह सारे काम चालू हो गए हैं। पिछले बजट में रासमी के अन्दर महाविद्यालय देने का काम किया और इस बार भी

मैंने मांग की थी तो इस बार रासमी के भवन बनाने के लिए, महाविद्यालय के भवन के लिए भी बजट की घोषणा कर दी। मैं इस अवसर पर यह भी चाहूंगा कि भोपाल सागर में उपखण्ड है, वहां भी एक महाविद्यालय खुल जाए तो उनको भी सुविधा मिलेगी।

मैं हमारे सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जब सरकार बनी थी तो मैंने आपसे आग्रह किया था, मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया, उनके आग्रह पर रावत साहब भादरगुना पधारे, कपासन पधारे और हमारे कपासन के तालाब, धमान्या के तालाब, जासमा के तालाब, सिंदेसर फीडर से आने वाला पानी है, भोपाल सागर तक नहीं आ पा रहा था तो 2500 करोड़ रुपये देकर यह टेंडर लगे और वह काम भी प्रारम्भ होने वाला है, इस प्रकार से आपने हमारे क्षेत्र पर बहुत बड़ा उपकार किया है। एक दूसरी डिमांड थी। डिंडोली फीडर बंद करके डिंडोली बांध भरे, हमारे सिंगपुर भरे, तुमड्या भरे इसके लिए आपने साढ़े छह करोड़ रुपये देकर हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ देने का काम किया है।

माननीय जल संसाधन मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आपने एनिकट ठीक करने की बात कही थी, वह भी जल्दी से जल्दी स्वीकृति जारी हो जाए। एक मेरी महती आवश्यकता है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर मातृकुंडिया का बांध बना हुआ है, 1300 एमसीएफटी का है, सारा पानी भीलवाड़ा जाता है और भीलवाड़ा की पेयजल की समस्या, चम्बल का पानी आने से वह पूर्ण हो गई है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप मातृकुंडया बांध से मुझे 600 एमसीएफटी पानी रासमी क्षेत्र के लिए दिलवाने का काम काम करें। सभापति महोदय, आपका सरंक्षण चाहूंगा, अंतिम वक्ता होने के नाते आप घड़ी को मत देखिये, मुझे देखिये।

श्री सभापति: आगे और भी है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): पांच मिनट ज्यादामिल जाएगा तो ठीक रहेगा। सीएचसी के लिए स्वीकृति, भीमगढ में आकिया में पीएचसी दी और अब सोनियाना के अन्दर भी आपने पीएचसी देने का काम किया है इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो जाएंगे।

ऊर्जा के क्षेत्र में 132 केवी बांसवाड़ा को जीएसएस के लिए आपने दिया है। पीएम श्री में भी खूब पैसा दिया। नगरीय विकास में इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए आपने पैसा दिया। बांसवाड़ा और कपासन में नवीन थाने बनाने के लिए भवन के लिए पैसा दिया। इस प्रकार कई चीज़ें मुझे दी है। अभी मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में मुझे साढ़े तेईस करोड़ रूपये सड़क निर्माण के लिए दिये हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

मातृकुंडया के अन्दर, परशुराम जी भगवान की धरती है, वहां पर ट्रेवल टूरिज्म क्षेत्र से जोड़कर 100 करोड़ रुपये वहां देने का काम किया है, सारे टूरिज्म क्षेत्र है उसमें जैसे त्रिपुरा सुंदरी है, मानगढ़ है, बेणेश्वर धाम है, सीतामाता, ऋषभ देव है, गोमेतेश्वर है, इस प्रकार से आपने 100 करोड़ रुपये देने का काम किया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आकोला में हाथ से छपाई के कारखानें हैं। मातृकुंडया में मुख्य मंत्री जी आये थे मैंने उनके हैंण्ड प्रिंट का साफा बंधवाया था, तो मुख्य मंत्री जी ने दिल बड़ा रखकर कहा कि ऐसी जगह है वहाँ हम

इसको हब बनाएंगे, तो हस्तकला जो हब बनने जा रहा है पांच करोड़ रूपये देने का उन्होंने काम किया।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में अपनी बात कहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के राज में क्या होता था, 5-6 उदाहरण हैं, मैं शोर्ट में करूंगा। मैं भी विधान सभा में था लेकिन हमको बजट नहीं दिया जाता था। हमारी सरकार सबको समान रूप से बजट देने का काम करती है। इन्होंने पिछली बार जो कारनामें किए हैं, पहला उदाहरण देता हूं, मुख्य मंत्री की कुर्सी का घोटाला हुआ, मुख्य मंत्री की कुर्सी पर कौन बैठे, तो गहलोत साहब और पायलट साहब लड़ते रहे और यह जनता को भूल गये, तो जनता ने भी इनको नकार कर इधर भेज दिया। जल जीवन मिशन का घोटाला हुआ, इनके अधिकारी जेल गये, केस भी चल रहे हैं। इन्होंने तीसरा घोटाला किया, सरकारी नौकरियों में भर्ती का घोटाला, पेपर लीक घोटाला, एक बार नहीं 17-17 बार घोटाला करने का काम किया और पूरे शिक्षा विभाग को नाथी का बाड़ा बनाने का काम इन्होंने किया। मैं चौथा उदाहरण देना चाहता हूं वह है स्थानान्तरण का घोटाला, शिक्षकों की आम सभा हो रही थी तब मुख्य मंत्री जी ने डोटासरा जी के सामने पूछा कि ट्रांसफर में पैसा तो नहीं लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि लग रहा है, फिर दूसरी बार पूछा तो सब अध्यापक कुर्सी पर खड़े हो गये और कहा कि भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, इस प्रकार के कारनामे इस कांग्रेस ने किये, पूरे शिक्षा विभाग को नाथी का बाड़ा बनाने का काम किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं एक घोटाले का और निवेदन करना चाहता हूं। सचिवालय के पास एक-एक किलो सोना, ढाई-ढाई करोड़ रुपये रोकड़ा मिल रहा है। खान घोटाला, इन्होंने वन भूमि को नहीं छोड़ा, चरागाह को नहीं छोड़ा, इतना बड़ा घोटाला किया। भरत सिंह जी वहां से आने वाले थे, भरत सिंह जी ने कई बार शिकायतें की लेकिन उनकी बात को किसी ने नहीं सुना और खान घोटाला करने का काम किया।

श्री सभापति: श्री जयकृष्ण पटेल।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): पट्टा वितरण घोटाला। इतना बड़ा घोटाला किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। भूमि आवंटन का घोटाला तो जग जाहिर हो गया, अरबों-करोड़ों की ज़मीनें कोड़ियों के दाम देने का काम किया। इन्होंने कोयला घोटाला किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री जयकृष्ण पटेल।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आपने देखा होगा बिजली के नाम पर कोयला ऊंचे दामों पर खरीदा गया, इन्होंने बिजली खरीद घोटाला किया। ऊंचे दाम पर बिजली खरीद कर इन्होंने घोटाला करने का काम किया। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं, जय श्री राम।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं मेरी व मेरी विधान सभा की तरफ से आपका धन्यवाद अर्पित

करता हूं। माननीय सभापति महोदय मैं आज बजट की बात करूं तो मेरे क्षेत्र के अन्दर, अनुसूचित क्षेत्र के अन्दर जिस तरीके से पूर्व में बजट पेश किया गया उसके अन्दर आदिवासियो के विकास के लिए सरकार ने एक हजार से बढ़ाकर 1500 करोड़ रूपये किए थे। उन 1500 करोड़ रुपये में से आदिवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क के लिए एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। वर्तमान बजट के अन्दर 1500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1750 करोड़ रूपये सरकार ने किया है, मैं चाहूंगा कि इस बजट का सही उपयोग किया जाए। पूर्व में 1500 करोड़ रुपये लैप्स थे वह भी हमारे आदिवासी विकास के लिए खर्च किए जाए। मैं चाहूंगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के क्षेत्र में वहां सुधारात्मक काम हो।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के 78 साल बाद भी, जनजाति उप योजना क्षेत्र का पैसा आता है उस पैसे को धार्मिक आयोजन के कार्यों के लिए खर्च किया जाता है। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनको चमकाने के लिए उपयोग किया जाता है। सरकार ने योजना बनाई है कि उप योजना क्षेत्र के लिए जो बजट वह आदिवासियों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए और सरकार ऐसा नहीं कर रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी कहना चाहूंगा कि आज उस क्षेत्र के हमारे गरीब बच्चे हैं उनकी क्या हालत है, सड़क की क्या हालत है, चिकित्सा की क्या हालत है, उस ओर देखना होगा, उस पर काम करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस देश में आजादी के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है तो आदिवासियों ने लड़ी है। मैं कहना चाहूंगा कि जल, जंगल, जमीन की लड़ाई आदिवासियों ने सबसे ज्यादा लड़ी है। आज वहां वन विभाग की कोई जमीन है तो उस जमीन पर आजादी से पहले भी वहां आदिवासी रहता आया है और वहां पर उसका कब्जा है, वहां वह कृषि कर रहा है। उसके पट्टे 2006 के अन्दर दिये गये हैं लेकिन वहां वनाधिकार के अन्दर उनके पट्टे के कागज तो है लेकिन वन विभाग के कार्मिक हैं वह उस कागज को नहीं मानते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 1962 के अन्दर उस क्षेत्र के अन्दर वन विभाग काबिज हुआ, उससे पहले भी वहां आदिवासी रहता था, तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि प्रतापगढ़ अकेले में पट्टा आवंटन के लिए सरकार ने कहा है। मैं कहना चाहूंगा कि पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अन्दर जहां-जहां वन विभाग की जमीन है उस क्षेत्र के अन्दर आदिवासियों को वन के पट्टे दिये जाएं और पट्टे आवंटन के लिये सरकार स्पेशल कैम्प लगाए।

VPS-RTM-25.02.2025-17.50-3k

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि ग्रीन फील्ड रोड के नाम से सरकार ने वहां पर बजट तो दिया है लेकिन उस क्षेत्र के अन्दर हमारे ग्रामीण इलाकों के अन्दर सड़क की हालत बिलकुल खराब है। आज शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें तो वहां पर सरकारी जो स्कूलें हैं, उनके अन्दर किसी स्कूल के अन्दर टॉयलेट नहीं है, किसी स्कूल के अंदर खेल ग्राउंड नहीं है, किसी स्कूल के अन्दर जो भवन है, वह जर्जर अवस्था के

अन्दर है, उसमें अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ऐसे में हम सरकार की बातें करें तो मैं सरकार से यह चाहूंगा कि सरकारी स्कूलों में हम अगर सही सुधार करेंगे तो उसके अन्दर जो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित पढ़ने वाला जो बच्चा होगा उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी।

आज हम राजस्थान के विकास की बात करते हैं। देश के विकास की बात करते हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और दलित वर्ग के जो बच्चे हैं वे ज्यादातर सरकारी स्कूलों के अन्दर पढ़ते हैं, सरकारी अस्पतालों के अन्दर जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम यह चाहेंगे कि वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के लिए बेहतर काम करें। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मैं अंतिम वक्ता हूं, माननीय सभापति महोदय, आज अपन देखते हैं कि उस क्षेत्र के अन्दर आज सरकारी कर्मचारी है, वह वहां पर आधार कार्ड में नाम बच्चों के जुड़वाने के लिए जगह-जगह दौड़ते फिरते हैं और उनको वहां पर सही गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि ब्लॉक स्तर पर बच्चों के आधार कार्ड के लिए एक अलग से आदमी को नोमिनेट किया जाये ताकि अध्यापक को दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के विकास के लिए, खेल मैदान के लिए गांगड़तलाई और आनंदपुरी के अन्दर स्पेशल युवाओं के लिए खेल के मैदान की घोषणा करें। साथ ही साथ वहां पर जो डाक्टर्स के रिक्त पद हैं, वह भी दिये जाये।

मैं अंत में मेरी निम्न दो बातें कहकर मेरी बात को विराम दूंगा-

इस जग में जितना जुल्म नहीं, उतना सहने की ताकत है।

तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है।

जय जोहार, धन्यवाद। जोहार।

श्री सभापति: श्री कंवरलालजी। छह बजे यह समाप्त हो जायेगा। आपकी जो इम्पोर्टेंट बात है, आप पहले रख दें।

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर धन्यवाद और अपनी बात रखने का मौका दिया है, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सर्वप्रथम मैं इस गौरवशाली राजस्थान की धरा को कवि की इन पंक्तियों से, लाइनों से प्रणाम करता हूं-

त्याग, प्रेम सौन्दर्य,शौर्य की, जिसका कण-कण एक कहानी।

आओ पूजे शीश झुकाएं, मिल हम,माटी राजस्थानी।।

आपका यह खुशहाल राजस्थान, हरित बजट पेश किया है हमारी सरकार ने। ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): यह दूसरे का नाम आ रहा है। अब यह आपका नाम आ गया वापस। इसको सही कराएं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः सही कराओ। आप तो अपनी बात को चालू रखो।

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय सभापति महोदय, सबको बोलने के लिए बंद करो एक बार। ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): छह बजे पूरा हो जायेगा। आप तो बोलें।

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करते हुए मेरी बात को मेरी विधान सभा क्षेत्र का काम और भजन लालजी सरकार को मैं धन्यवाद देने की बात करूंगा लेकिन एक बहुत बड़ी बात है। पिछली सरकार का एक बहुत बड़ा घोटाला, गहलोत सरकार का और बहुत बड़ा घोटला खनन मंत्री का कोरोना काल का है जब पूरी दुनिया, पूरा राजस्थान, पूरे लोग बचने के लिए अस्पताल में पलंग ढूंढ रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग कर रहे थे तो उस समय खनन विभाग में लाइमस्टोन को मार्बल बताकर एक हजार करोड़ रुपये का जो घोटाला किया, मात्र माइन्स विभाग ने पांच करोड़ रुपये में ही दे दी। उस समय ए.सी.एस. सुबोधजी थे। यह ज्यादा लम्बी चौड़ी बात करूंगा तो मेरी विधान सभा क्षेत्र के विकास के काम मेरे वंचित रह जाएंगे। मेरे पांच सवाल आपके माध्यम से है कि सरकार इसकी जांच कराएं। पहला सवाल नौ माह में यह लाइमस्टोन मार्बल कैसे हो गया? दूसरा सवाल सिर्फ मार्बल निकालने की शर्त क्यों नहीं लगायी? उसमें बाद में चुपके से लाइमस्टोन कैसे निकाला गया?

(समयः बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबोधजी के आते ही यह फाइलें तुरंत क्यों दौड़ने लग गयीं? चौथा सवाल मेरा यह है कि एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान कैसे हुआ? पांचवां सवाल है कि रिकवरी 30 परसेंट ही हुई जबकि दावा 70 परसेंट का किया गया तो इन पांचों सवालों का आपके माध्यम से सरकार से उत्तर दिलायें। आप जांच करायें। दूसरा इसी में, खनन विभाग को 273 करोड़ रुपये की एक और चपत लगायी है। मोरदियाजी को वसूली के लिए जो कहा गया था, विभाग में इसको भी रोक लगा दी गयी और यह भी लिखा गया कि यह कोर्ट में अपील नहीं की जाये।

अब मैं मेरी बात, मेरे विधान सभा क्षेत्र पर आता हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग। मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रदेश में आगामी वर्ष करीब 5,000 करोड़ स्टेट हाई-वे, बाईपास, फ्लाई ओवर, एलिवेटेड रोड, आर.ओ.बी., पुलिया के कामों की घोषणा की गयी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र अंता में मांगरोल क्षेत्र में बहुत पुरानी मांग है। एन.एच. 27 अंता-सीसवाली तिराहे तक फोर लेन में आर.ओ.बी. 65 करोड़ की बजट घोषणा की है, मैं इसके लिए माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। नॉन पेचेबल रोड्स की भी घोषणा की है, उनके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में, मंत्री महोदय, सदन के माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अंता में गांव सोनवा का व अन्य गांवों में बरसात के समय

कालीसिंध का तेज बहाव होने से बड़े कस्बों से सम्पर्क टूट जाता है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार के प्रसंज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि वहां पर उच्चस्तरीय पुलिया का बजट जवाब में हमें मिल जाये तो मैं इस बात के लिए भी हमारे क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन की बात करता हूं। माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि बजट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से बेहतर सुविधाएं हेतु राजस्थान रोडवेज द्वारा 500 बसें तथा 300 इलेक्ट्रिक बसें चलाने हेतु बजट में घोषणा की गयी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अंता में रोडवेज बस स्टैंड की मांग बहुत पुरानी मांग है। अंता रोडवेज बस स्टैंड की घोषणा बजट के माध्यम से की जाकर आप क्षेत्रवासियों को राहत देने का श्रम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा और मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आधारभूत चिकित्सा सुविधा को प्रदेश के अंतिम छोर तक ले जाने के लिए मेरे पी.एच.सी., सी.एच.सी. के साथ, पी.एच.सी. को क्रमोन्नत किया है। बजट घोषणा में आपने मेरी बमोरीकलां को पी.एच.सी. से सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया है, उसके लिए मैं मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जन सुनवाई केन्द्र हेतु आपने दस लाख रुपये एम.एल.ए. लेड से देने की घोषणा की है, यह हम सब एम.एल.एज. के लिए, वहां बैठकर जन सुनवाई करेंगे तो जनता को सुगम और अच्छा अवसर मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं युवाओं की बात आपके माध्यम से सरकार के प्रसंज्ञान में लाना चाहता हूं। मैं विपक्ष के साथियों को यह बताना चाहूंगा कि यह भाजपा की सरकार है। माननीय भजन लालजी की सरकार है जो जनता के बीच में रहकर कार्य कर रही है। गत सरकार की तरह होटलों में बैठकर कार्य नहीं कर रही है। मात्र छह माह पहले बजट पेश किया है, 70 परसेंट काम धरातल पर आ चुका है। बेरोजगारों हेतु 1 लाख 25 हजार सरकारी नौकरियां तथा निजी क्षेत्र में 1 लाख 50 हजार नौकरियों हेतु घोषणा की गयी है जिनको माननीय भजन लालजी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी। अब पेपर लीक नहीं होगा और उनको पूरा किया जायेगा। साथ ही, माननीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार। पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में तीन हजार पांच सौ ग्राम पंचायतों में 35 करोड़ रुपये ओपन जिम खेल मैदान के लिए दिये हैं, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अंता में अंता नगर खेल स्टेडियम बना हुआ है जिसके बजट के माध्यम से आधुनिकीकरण करने का श्रम करें ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र के युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके।

अंत में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो काम हैं, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

अंता विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण कार्य। अंता विधान सभा क्षेत्र में नगरपालिकाओं में बरसाती नालों के निर्माण कार्य एवं साथ ही अन्य विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण का कार्य। ग्राम सोनवा में कालीसिंध नदी पर उच्चस्तरीय पुलिया का निर्माण कार्य, अंता विधान सभा क्षेत्र में मिनी सचिवालय तथा मांगरोल में मिनी सचिवालय का कार्य एवं शेष अन्य कार्य पूर्ण करवाने के लिए बजट और आशीर्वाद देने की आप कृपा कराएं।

श्री अध्यक्षः सदन की कार्यवाही 27 फरवरी, 2025 के सुबह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 17.59 बजे गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

....